तृतीय माला, खंड 47, अंक 9
Third Series, Vol. XLVII, No. 9

मंगलवार, 16 नवम्बर, 1965/25 कार्तिक, 1887 (शक)
Tuesday, November 16, 1965/Kartika 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
EW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9—मंगलवार, 16 नवम्बर, 1965/25 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 9—Tuesday, November 16, 1965/Kartika 25, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
239	अमरीका द्वारा गेहूं सम्बन्धी पेशकश	Wheat offer by U.S.A. .	735–736
242	अमरीका से खाद्यान्न का आयात	Food Imports from U.S.A. .	736–742
240	सुरक्षित पत्तन सुविधायें	Safe Port Facilities . .	742–744
241	आसाम के लिए स्टीमर सेवा	Steamer Service to Assam .	744–746
243	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme .	746–749
244	भारत के खाद्य निगम द्वारा चावल का समाहार	Rice Procurement by Food Corporation of India . .	749–753
245	अनाज का आयात	Import of Foodgrains .	753–754

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
246	गोआ में आम चुनाव	General Elections in Goa .	754
247	खरीफ फसलों का उत्पादन	Production of Kharif Crop .	754–755
248	पोत-निर्माण कार्यक्रम	Ship-building Programme .	755
249	राजस्थान में अभाव की स्थिति	Scarcity Conditions in Rajasthan	755–756
250	उर्वरकों के मूल्य निर्धारित करना तथा उनका वितरण करना	Pricing and Distribution of Fertilizers . . .	756
251	केन्द्रीय मछली विपणन निगम	Central Fish Marketing Corporation	756–757
252	देसी गेहूं की सप्लाई	Supply of Indigenous Wheat .	757
253	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का सेवा विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme of I.A.C.	757–758
254	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	758
255	गन्ने का मूल्य	Prices of Sugarcane . .	758–759
256	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers .	759
257	दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi .	759–760

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by at Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
258	निजी विमान सेवायें	Private Airlines . . .	760–761
259	गेहूं न उतारने के लिये विलम्ब शुल्क	Demurrage for Unloading of Wheat	761
260	निराश्रित महिलाओं के लिये संक्षिप्त पाठयक्रम	Condensed Courses for Destitute Women . .	761–762
261	पाकिस्तान द्वारा विमान उड़ानों में बाधा	Interference by Pakistan in Air Flights . . .	762–763
262	उप-चुनाव	Bye-elections	763
263	चीनी पर नियंत्रण	Control on Sugar . . .	763
264	निर्वाचन व्यय	Poll Expenses . . .	764
265	सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethusamudram Project . .	764
266	मूंगफली के मूल्य	Prices of Groundnut .	765
267	सामान्य निर्वाचन	General Elections . .	765
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
629	उर्वरकों का संभरण	Supply of Fertilizers	765–766
630	केरल में छोटे पत्तन	Minor Ports in Kerala . .	766
631	केरल में अन्तर्देशीय जलमार्ग	Inland Waterways in Kerala .	767
632	केरल के लिये चावल का सम्भरण	Rice Supply to Kerala . .	767
633	अनुसूचित जातियों तथाअनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	767–768
634	अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability	768
635	हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board for Harijan Welfare . .	768
636	अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956	Suppression of Immoral Traffic Act, 1956 . . .	768–769
637	अखिल भारतीय बंजारा सेवक संघ	Akhil Bhartiya Banjara Sewak Sangh	769
638	अनाज व्यापारियों के विरुद्ध मकद्दमे	Cases against Foodgrains Dealers	769
639	पशुधन का बीमा	Live-stock Insurance	769–770
640	किसानों को ऋण	Credit to Farmers	770
641	व्यापारिक फसलों की खेती	Cash Crop Cultivation . .	770–771
642	समाज सेवा के लिये महिला स्वयंसेवक दल	Women Volunteer Corps for Social Service . .	771
643	पर्वतीय क्षेत्र तथा कमी वाले क्षेत्र	Hill and Scarcity Areas .	771–772
644	कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities .	772
645	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम	Applied Nutrition Programme .	773
646	चावल का आयात	Import of Rice . .	773

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
647	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन	S.C. and S.T. Commissioner's Report	774
648	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के सम्बन्ध में गोष्टी	Seminar on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	774
649	चीनी कारखाने	Sugar Factories . . .	774–775
650	नारियल जटा कारखानों के मजदूर	Workers of Coir Factories .	775
651	खाद्य वस्तुओं में पोषक तत्व	Nutritious elements in Food .	776
652	परिसीमन आयोग	Delimitation Commission .	776
653	खाद्य पोलीटेकनिक	Food Polytechnics . . .	776–777
654	हैलीकोप्टर की दुर्घटना	Crash of Helicopter . .	777
655	मद्रास बन्दरगाह में विस्फोट	Madras Harbour Explosion .	777
656	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors . . .	777–778
657	राष्ट्रीय खाद्य नीति	National Food Policy . .	778
658	डेनियल वोल्काट के भाग निकलने से सम्बन्धित जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee on escape of Daniel Walcott	778
659	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	778–779
660	चने के दाम	Prices of Gram . .	779
661	राजस्थान में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को विमान सेवायें	I.A.C. Flights in Rajasthan .	780
662	सीमावर्ती सड़क विकास योजना	Lateral Road Development Scheme	780
663	केन्द्रीय पण्य समितियां	Central Commodity Committees	781
664	ग्राम स्वयंसेवक दल	Village Volunteer Force .	781
665	वनस्पति घी का रंगदार बनाया जाना	Colourisation of Vanaspati .	782
666	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद	Indian Council of Agricultural Research	782
667	"सी आइलेंड" कपास	Sea Island Cotton . . .	783
668	मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Mysore	783
669	अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की सड़कें	Roads of Inter-State and Economic Importance . .	783–784
670	दिल्ली में चावल की कमी	Scarcity of Rice in Delhi .	784
671	कैरावील विमान के फ्यूल पम्प	Fuel-Pumps in Car velle Aircraft	785
672	कृषि योजनायें	Agricultural Schemes . .	785
673	विमान परिचारिकाओं के रूप में चैकोस्लोवाकिया की बालायें	Czechoslovak Girls as Air Hostesses	785–786

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
674	उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Co-operatives	786
675	तेपिओका की खेती	Tapioca Cultivation	786–787
676	विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति	National Committee on Development of Extension Training Programme	787–788
677	विधि स्नातक	Law Graduates	788
678	उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति	Food Situation in U.P.	788
679	प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये असैनिक मोटर गाड़ियां	Civil Vehicles to meet Defence requirements	788–789
680	डकोटा विमानों का बदलाव	Replacement of Dakotas	789
681	बम्बई पत्तन से न उठाया गया माल	Uncleared Cargo at Bombay Port	789–790
682	अमरीका से चावल	Rice from U.S.A.	790–791
683	सामान्य माल पर अतिभार	Surcharge on General Cargo	791
684	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के बेकार खड़े विमान	Planes grounded with I.A.C. and Air India	791
685	विमान सेवायें	Air Services	791–792
686	"लेबर बैंक"	Labour Banks	792
687	ग्राम पंचायत	Village Panchayats	792–793
688	कराची हो कर चलने वाली विमान सेवायें	Airlines operating through Karachi	793
689	कराची में के० एल० एम० के विमान से माल उतारना	Off-loading of a consignment from a KLM Plane at Karachi	793
690	उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाईयों पर वन का लगाया जाना	Investments in Fertilizers and Insecticides	793–794
691	पटसन की खेती	Jute Cultivation	794
692	कानूनी सहायता	Legal Assistance	794–795
693	भोपाल-जोधपुर विमान सेवा	Bhopal-Jodhpur Air Link	795
694	रेगिस्तान विकास बोर्ड	Desert Development Board	795
695	सामाजिक विधान का समाज शास्त्रिक अध्ययन	Sociological Study of Social Legislation	795–796
696	भारतीय जहाजरानी निगम	Shipping Corporation of India	796
697	साल में धान की दो फसलें	Double Paddy Crops	796
698	वर्ष में गेहूं की दो फसलें	Double Wheat Crops	797
699	एरियाना अफगान एयरलाइन्स के काबल जाने वाले विमान का दिल्ली लौटना	Return of Kabul bound Plane of Ariana Afghan Airlines to Delhi	797

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
700	सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों के लिये विधान	Legislation for Curging Social Economic Crimes . .	798
701	भ्रष्टाचार	Corruption . . .	798
702	बतुल में लगुड़-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र	Logging Training Centre at Betul	798
703	लगुड़-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र	Logging Training Centres .	799
704	चमड़ा सामान उद्योग	Leather Goods Industries	799–800
705	कीड़ों की रोकथाम	Control of Insects and Pests .	800
706	"जो खाओ सो उपजाओ" आन्दोलन	'Grow what you eat' Campaign	800
707	केरल में उगाही प्रणाली	Levy System in Kerala .	800–801
708	केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep-Sea Fishing in Kerala	801
709	इन्दोर हवाई अड्डा	Indore Airport .	802
710	राशन व्यवस्था	Rationing . . .	802
711	सामाजिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्ति	Persons trained in Social Security Measures . . .	802–803
712	अनाजों का भाव	Prices of Foodgrains	803
713	नलकूपों का सामान	Tubewell Accessories . .	803
714	गुरदासपुर जिले में सड़क संचार व्यवस्था	Road Communications in Gurdaspur District . . .	803–804
715	आसाम में फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs in Assam . .	804
716	जयपूर तथा उदयपूर के लिये इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेश की डकोटा विमान सेवा	I.A.C. Dakota Service to Jaipur and Udaipur . . .	804
717	कृषि विकास	Agricultural Development .	804–805
718	केरल में उल्लेयोरी-पुठियांजली सड़क	Ulleyiri-Puthivanjali Road in Kerala	805
719	कृषि ऋण	Agricultural Credit . .	805
720	बच्चों को गोद लेने का कानून	Law of Adoption of Children .	806
721	अगरतला हवाई अड्डा	Agartala Airport .	806
722	वनों का विकास	Development of Forests . .	806–807
723	खाद्य विभाग केफेटीरिया सहकारी स्टोर्स लिमिटेड	Food Department Cafeterial Cooperative Stores Ltd. .	807
724	उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilizers . .	807
725	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme	808
726	राजस्थान की अनुसूचित जातियों के परिवारों का कल्याण	Welfare of families of Scheduled Castes in Rajasthan . .	808
727	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	808–809
728	संकर ज्वार	Hybrid jowar	809

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
729	कृषि परियोजनाओं के लिये कनाडा से सहायता	Canadian Assistance for Agricultural Projects . .	809–810
730	जरी कशीदाकारी (सोने का तार) का पुराना उद्योग	Old Zari Embrodiery (Gold Thread) Industry . .	810
731	अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन द्वारा विमानों के किराये में कमी	Reduction in Air Fares by IATA	810–811
732	कृषि नीति सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी	All India Seminar on Agricultural Policy . . .	811
733	कलिंग एयरलाइन्स के डकोटा का दुर्घटना-ग्रस्त होना	Crash of Dakota of Kalinga Airlines	811–812
734	मोटे अनाजों का उत्पादन	Production of Coarse Grains .	812
735	लाहोर-क्षेत्र में पकड़ी गई बसें	Buses Captured in Lahore Sector	812
736	सहकारी फार्म	Co-operative Farms .	812–813
737	भारतीय पर्यटन निगम	Indian Tourism Corporation .	813
738	विशाखापट्टणम पत्तन	Visakhapatnam Port . .	813–814
739	चावल की भूसी से तेल निकालना	Oil extraction from rice chaff .	814
741	सामुदायिक विकास खंड	Community Development Blocks	814
742	दिल्ली में खेती	Cultivation of Land in Delhi .	815
743	भूमि सर्वेक्षण	Soil Survey . . .	815
744	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई	Milk Supply by D.M.S.	815–816
745	बडनेरा स्टेशन के ऊपर रेल-व-सड़क पुल	Rail-*cum*-Road bridge over Badnera Station . . .	816
746	अमरावती में से होकर जाने वाली ट्रंक सड़क	Trunk Road passing through Amraoti	816
747	सहकारी चीनी कारखाने	Co-operative Sugar Factories .	816–817
748	बेलगांव हवाई अड्डा	Belgaum Airport .	817
749	कृषि फार्म	Agricultural Farms . .	817
750	बकसर अथवा गाजीपुर में गंगा पर पुल	Bridge over Ganga at Buxar of Ghazipur	818
751	विहार में फारबिसगंज-दरभंगा सड़क	Forbesganj-Darbhanga Road in Bihar	818
752	सीमा सड़कें	Border Roads . . .	819
753	भारतीय बाल-कल्याण परिषद	Indian Council for Child Welfare	819–820
754	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37	National Highway No. 37 .	820
755	उर्वरक का प्रयोग	Utilisation of Fertilizers	820–821
756	हल्दानी में भाण्डागार	Warehouse at Haldwani	821–822

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
757	उत्तर प्रदेश में पर्वतीय स्थान	Hill Stations in U.P. . .	822
758	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के शेडों में गेहूं का सड़ना	Rotting of Wheat in Sheds of Calcutta Port Commissioners	822–823
759	लापता भारतीय जहाज	Missing Indian Vessels .	823
760	लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes	823–824
762	दिल्ली-नागपुर विमान सेवा	Delhi-Nagpur Air Service .	824–825
763	राष्ट्रीय राजपथ का नेफा तक बढ़ाना	Extension of National Highway to N.E.F.A. . . .	825
764	नेफा में सड़कें	Roads in NEFA . . .	825
765	भारतीय बाल कल्याण परिषद	Indian Council for Child Welfare	826
766	उड़ीसा में सड़क विकास योजनायें	Road Development Schemes in Orissa	826
767	"बायां-गैस प्लांट"	Bio-Gas Plant . . .	827
768	उड़ीसा में बनाई गई खादी	Khadi Produced in Orissa	827
769	स्थानीय विकास कार्य	Local Development Works .	827–828
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
दिल्ली में मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना---		Alleged Firing by police on labourers in Delhi—	
श्री राम सेवक यादव		Shri Ram Sewak Yadhav	828
श्री हाथी		Shri Hathi . .	828
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	828
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ---		Motion re : International Situation—	
श्री बाकर अली मिर्ज़ा		Shri Bakar Ali Mirza	829–830
श्री फ्रैंक एन्थनी		Shri Frank Anthony	830–832
श्री मेहताब		Shri Mahatab . .	832–833
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी		Shri Tridib Kumar Chaudhuri	833–834
श्री दी० चं० शर्मा		Shri D. C. Sharma .	834–835
डा० राम मनोहर लोहिया		Dr. Ram Manohar Lohia .	835–836
श्री रवीन्द्र वर्मा		Shri Ravindra Varma	836–837
श्री सेझियान		Shri Sezhiyan .	838
श्री खाडिलकर		Shri Khadilkar .	838–839
श्री जी० म० कृपालानी		Shri J. B. Kripalani .	839–841
श्री हनुमंतय्या		Shri Hanumanthaiya .	841–843
श्री प्रकाशवीर शास्त्री		Shri Prakash Vir Shastri .	843–844
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा		Shrimati Tarkeshwari Sinha	844–846
श्री लाल बहादुर शास्त्री		Shri Lal Bahadur Shastri .	846–848

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 16 नवम्बर, 1965/25 कार्तिक, 1887 (शक)
Tuesday, November 16, 1965/Kartika 25, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 239, डा० सिंघवी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसी विषय पर प्रश्न संख्या 242 को भी इसके साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 245 भी लिया जा सकता है क्योंकि यह भी उसी विषय के बारे में है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : प्रश्न संख्या 245 अन्य क्षेत्रों के बारे में भी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 239 के साथ केवल प्रश्न संख्या 242 लिया जायेगा ।

+ **अमरीका द्वारा गेहूं सम्बन्धी पेशकश**

*239. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री किशन पटनायक :
श्री रा० बरूआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मोहसिन :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसबै :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री हिंमतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने केवल पांच लाख टन सर्विस गेहुं की पेशकश की है जब कि भारत को पचास लाख टन की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा भारत को खाद्यान्न के संभरण में कमी करने से सम्बन्धित बातों पर उच्चतम स्तर पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुये पी० एल० 480 करार में 43 लाख मीट्रिक टन गेहूं जिसका लदान अगस्त, 1965 तक होना था, आयात करने के लिये निधि की व्यवस्था थी । नया दीर्घ कालीन करार अभी तक नहीं हुआ है । इस बीच में, संयुक्त राज्य सरकार ने समय समय पर पत्र-विनिमय द्वारा कुल लगभग 20 लाख टन गेहूं आयात करने के लिये अनुपूरक निधि सुलभ की है । इस गेहूं का लदान दिसम्बर, 1965 के अन्त तक पूरा हो जाना है । अब तक प्रति मास उपलब्धि के स्तर में कोई कोई कमी नहीं दी गई है ।

अमरीका से खाद्यान्न का आयात

* 242. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रा० बरूआ :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात के बारे में भारत के साथ दीर्घकालीन करार करने में कोई अनिच्छा प्रकट की है;

(ख) अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर, 1965 में भारत ने कितने गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न की मांग की थी तथा अमरीका सरकार ने कितना भेजा; और

(ग) अगले छः महीनें में इस प्रकार का कितना आयात होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सितम्बर, 1964 में हुये पी० एल० 480 करार और इसमें दिसम्बर, 1964 में हुये संशोधन में 43 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 3.3 लाख मीट्रिक टन चावल जिसका लदान अगस्त, 1965 तक होना था, के लिये निधि की व्यवस्था थी। जब तक एक नया दीर्घ कालीन करार नहीं होता तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने समय समय पर पत्र-विनिमय द्वारा सितम्बर से दिसम्बर, 1965 तक लगभग 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने के लिये अनुपूरक निधि सुलभ की है।

(ख) अगस्त से अक्तूबर, 1965 के महीनों के लिये कोई विशिष्ट मात्रा नहीं मांगी गयी थी लेकिन पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका से खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं प्राप्त हुई :—

(हजार मीट्रिक टन)

	अगस्त, 1965	सितम्बर, 1965	अक्तूबर, 1965
गेहूं	501.9	537.3	585.6
चावल	14.4	..	
माइलो	37.3	22.4	

(ग) क्योंकि पी० एल० 480 के अधीन अभी तक नया दीर्घकालीन करार पूरा नहीं हुआ है, इस लिये इस अवस्था में यह बताना असम्भव होगा कि आगामी 6 महीनों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत कितनी मात्राएं आयात की जा सकेंगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार और **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री पी० एल० 480 कार्यक्रम को कमी को दूर करने के लिए मूल्यों को स्थिर बनाने में सहायक कार्यक्रम मानने पर दृढ़ हैं अथवा वे, अब यह समझ गये हैं कि इसका प्रयोग राजनैतिक दबाव डालने के साधन के रूप में और हमारे कृषि विकास पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले कार्यक्रम के रुप में किया जा रहा अथवा किया गया है, अथवा किया जाना है ? यदि हां, तो क्या इस कटौती को राजनैतिक दबाव का अंश समझा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम्) : वाद-विवाद के दौरान मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैं नहीं समझता कि राजनैतिक दबाव डालने के लिये खाद्यान्न का प्रयोग किया जा रहा है। मेरा और सरकार का भी यही विचार है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, पी० एल० 480 मुख्य रूप से कमी को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से इस वर्ष की कमी की स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह सभा यह जानना चाहेगी कि क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि श्री स० का० पाटिल को, जो अमरीका गये थे, पी० एल० 480 कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया था और क्या यह भी सच है कि श्री स० का० पाटिल ने

एक वक्तव्य किया था कि इस विषय में बातचीत करने के लिए उन्हें मंत्रालय अथवा मंत्री महोदय से कोई विशेष जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं थी ? क्या मंत्री महोदय इस अनुचित वादानुवाद पर सभा को जानकारी देंगे ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : कोई अनुचित वादानुवाद नहीं है। मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में संयुक्त उत्तरदायित्व है। मैंने कहा था कि पी० एल० 480 के बारे में श्री स० का० पाटिल को विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में भारत सम्बन्धी सामान्य मामलों पर बातचीत करने का उन्हें अधिकार है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the food being procured under P.L. 480 will be utilised for building buffer stock or is meant for consumption?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : दोनों के लिये होगा, हो सकता है कि अभाव की वर्तमान स्थिती को देखते हुए हमें चालू वर्ष में उपभोग के लिए अधिक उपयोग करना पड़े।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी खाद्यान्न की मात्रा और खाद्यान्न देते रहने का निश्चय राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाता है न कि परोपकार के विचार से, जैसे कि संयुक्त अरब गणराज्य को शांति के लिए खाद्यान्न के मामले में जिसका संभरण, अचानक बन्द कर दिया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है कि, अमरीका से खाद्यान्न मिलना बन्द हो जाने की स्थिति में किसी भी संकट का सामना करने के लिए भली प्रकार से तैयार हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : जी हां, अपनी योजनायें बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है।

Shri Sheo Narain : As the Government say that this time there has been drought may I know whether after this drought Government propose to discontinue from next year the procurement of food grains under P.L. 480?

Mr. Speaker : Who can say what will happen next year?

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के वक्तव्य और वाद-विवाद के उनके उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि पी० एल० 480 के क्लेश से बचा नहीं जा सकता और हमें यह खाद्यान्न लेना ही पड़ता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमें कब तक इस आयात किये गये गेहूं पर निर्भर रहना है तथा क्या हम चौथी योजना में गेहूं और चावल के मामले में आत्म-निर्भर होंगे ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : जी हां। मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि चौथी योजना के अन्त तक आत्म-निर्भर हो जाने के उद्देश्य से हम योजनायें बना रहे हैं। जब हम खाद्य पर चर्चा करेंगे तो सभा को इस कार्यक्रम पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

श्री श्रीनारायण दास : प्रश्न संख्या 242 के भाग (क) का उत्तर का तो नकारात्मक ही है और नही सकारात्मक। मैं जानना चाहता हूं कि अमरीकी सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का संभरण करने के लिए अन्तिम रूप से बातचीत करने में विलम्ब करने के क्या कारण बताये हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : यह मामला मार्च में भी उठाया गया था। 1964 का करार जून के अन्त में समाप्त होने वाला था और हमने अगले दो वर्षों के लिये मार्च में विचार-विमर्श आरम्भ किया। तब कुछ माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए हमें पी० एल० 480 पर निर्भर नहीं रहना चाहिए तथा दूसरी ओर हमें एक ऐसा कृषि कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे हम आत्म-निर्भर हो जायें। इसलिए वे आत्म-निर्भर होने के कार्यक्रम के बारे में जानने के इच्छुक थे तथा अतः हमने चौथी योजना के कृषि कार्यक्रम और इसको पूरा करने की कार्य-नीति की रूपरेखा भी अमरीका सरकार को भेज दी है। इस प्रयोजन के लिए इसपर भी विचार किया जा रहा है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जब तक प्रतिदिन हमारी बन्दरगाहों में खाद्यान्न से लदा एक पूरा जहाज़ नहीं आता, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी; यदि हां, तो क्या इस भयंकर स्थिति के लिए वे उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं पहले ही कहा चुका हूं कि प्रतिदिन हमारी बन्दरगाहों में गेहूं जहाजों के आने पर निर्भर रहना, विशेष रूप से 12,000 मील दूरसे, खतरनाक बात है। इसलिए हमारे लिए यथासंभव शीघ्र आत्म-निर्भर हो जाना आवश्यक है लेकिन रातोरात हम कोई चमत्कार तो कर नहीं सकते ।

श्री दी० चं० शर्मा : पी० एल० 480 का कार्य अमरीका के कृषि विभाग से लेकर राज्य विभाग को सौंपा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इसके अभिप्रेत आशय को समझते हैं और यदि समझते हैं तो वह क्या है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह अमरीका सरकार की आन्तरिक कार्य-प्रणाली का मामला है, स्थितियों के अनुसार वे जिस तरह सर्वोत्तम समझे उस तरह कार्य-व्यवस्था करें जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अवश्य ही यह जानने के इच्छुक हैं कि क्या इस हस्तांतरण से नीति में कोई परिवर्तन होता है। मैंने इस मामले में पूछ-ताछ करने का प्रयत्न किया है और मुझे विश्वास दिलाया गया है कि विभाग में इस परिवर्तन से नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री वासुदेवन नायर : ऐसा दिखाई देता है कि राष्ट्रपति जानसन सहित अमरीकी अधिकारी गत अनेक वर्षों में हमारे कृषि उत्पादन से बहुत चिन्तित हैं और चाहते हैं कि हम उत्पादन बढ़ायें तथा उनपर निर्भर रहना बन्द कर दें। क्या इस कारण से हमारी सरकार उन्हें संतुष्ट करने के हेतु सभी योजनायें और उत्पादन कार्यक्रम उन्हें भेजने के लिये बाध्य हो गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसा करने में शर्म नहीं आई ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : ऐसा करने में मुझे शर्म नहीं आती । जहां से भी सहायता मिले मैं लेने को तैयार हूं । (**अन्तर्बाधा**) ।

श्री वासुदेवन नायर : आप ऐसा क्यों करते हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : वास्तव में मुझे बारबार खाद्यान्न मांगने में शर्म आती है लेकिन जहां तक उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है यह एक तकनीकी मामला है । इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए मैं इसपर विश्व के किसी भी भाग के तकनीकी प्राधिकार से विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूं । इसमें शर्म की कोई बात नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका द्वारा अल्पकालीन सहायता के परिणामस्वरूप आयात किये गये खाद्यान्न तथा देश में अन्य खाद्यान्न के भी भाव बढ़ गये हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसके परिणामस्वरूप आयात किये गये खाद्यान्न के मूल्य नहीं बढ़े हैं । लेकिन मैं यह मानता हूं कि इससे हमारी वितरण योजना के बारे में कुछ सीमा तक अनिश्चितता पैदा हो जाती है ।

Shri Bade : Whether it is a fact.....

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, on a point of order I want to know whether my question has also been taken up with this question.

Mr. Speaker : Yes.

Shri Madhu Limaye : Then, call me after this.

Mr. Speaker : How can I call you first and ignore others?

Shri Madhu Limaye : Since my question has been taken up with it, I should be called.

Shri Ram Sewak Yadav : We are rising for the fifteen minutes but are unable to catch your eye. I do not want to say such things but when we witness such things daily, we are pained.

Mr. Speaker : I am sorry that such uncalled for allegations are made. More the time I give them more they come forward with such allegations. I am allowing everybody by turn.

Shri Ram Sewak Yadav : His number is first.

Mr. Speaker : I am coming to him also.

Shri Bade : It is not a fact that U.S.A. did not continue to pursue its earlier policy after the Indo-Pakistan fighting and whether U.S.A. is reviewing it?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसीलिये यह समझना आवश्यक है कि यह अल्प-कालीन प्रबन्ध किया गया। ऐसा पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के बाद नहीं हुआ; वह तो 5 अगस्त को शुरू हुआ था। अल्प-कालीन आधार पर पहली किश्त के लिए जुलाई, 1965 में व्यवस्था की गई थी जबकि पाकिस्तान के साथ कोई संघर्ष नहीं था।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या भारत सरकार के एक मंत्री के लिए यह कहना उचित है कि चौथी योजना के लिए इस सरकार की योजनायें अमरीकी सरकार को पेश की गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह किसने कहा है ?

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैंने मंत्री महोदय को ऐसा कहते सुना है। रिकार्ड से आप इसकी जांच कर सकते हैं।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हमने उन्हें यह बताया है कि पी० एल० 480 पर निर्भर रहने से किस प्रकार बचने का हमारा विचार है।

श्री वासुदेवन नायर : मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यहीं पर ऐसा कहा था।

अध्यक्ष महोदय : उनका आशय यह नहीं था।

Shri Madhu Limaye : Did U.S.A. say that they would consider the extension of agreement for food shipment only when Shri Sashtri visited U.S.A.?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं नहीं समझता कि यह धारणा सच है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पी० एल० 480 की मंजूरी से सम्बद्ध राजनीतिक पहलू के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके द्वारा संभरण किश्तों में करने के कारणों का पता लगाया गया है; यदि हां, तो अब सरकार ने क्या करना तय किया है ताकि भारत आयात से मुक्त हो सके ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हमें आत्म-निर्भर बनना है । जैसा मैं पहले कह चुका हूं, हमें कृषि विकास का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना है, जिससे हम आत्म-निर्भर हो जायें । जैसा मैं कह चुका हूं इसमें कुछ वर्ष लगेंगे ।

Shri Kishan Pattnayak : Is this the view of Government that first the country should become self-sufficient in food and then only P.L. 480 is to be discontinued, or whether Government feels this also that only after doing that this inactive Government can be prompted to take measures for increasing agricultural production?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : श्रीमान्, हमें देखना यह है कि मांग और पूर्ति में अन्तर इतना अधिक अथवा कम है जिससे हम आयात किये बिना काम चला सकें या नहीं । लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में विशेष रूप से मानसून की असफलता को ध्यान में रखते हुए यह सोचना मूर्खता होगी कि विदेशों से आयात किये बिना हम निर्वाह कर सकेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the wheat supplied by U.S.A. is inferior in quality and gives a bad smell and is not considered fit for their own use?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह बिल्कुल गलत धारणा है । मुझे नहीं मालूम कैसे यह भावना फैल गई है । अनाज की जांच की गई है ..... **(अन्तर्बाधा)**

श्री बड़े : क्या मंत्री महोदय ने प्रयोग किया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The people are not taking this wheat. Can the hon. Minister say that it is better than the indigenous wheat?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस अनाज की किस्म की हमारी प्रयोगशालाओं में जांच की गई है और यह देसी गेहूं से किस भी प्रकार घटिया नहीं है? वास्तव में दिनप्रतिदिन इस की अधिक मांग हो रही है । मुझे समझ नहीं आता कि माननीय सदस्य को कहां से जानकारी मिली है कि लोग इसे पसन्द नहीं करते हैं और इसकी मांग नहीं है । यदि मांग नहीं होगी, तो मैं अवश्य ही तुरन्त आयात बन्द कर दूंगा ।

Shri A. S. Saigal : Is it not a fact that after the breakout of Indo-Pakistan fighting, U.S.A. communicated to us that unless their advise was heeded to, the P.L. 480 food will not be supplied?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है ।

Shri Rameshwaranand : Does the Minister of Food & Agriculture realise that if the difficulties in the way of food production are removed, we can even supply wheat to U.S.A. what to talk of importing from there? Are attempts being made to remove these difficulties?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं ताकि हम आत्म-निर्भर हो जायें ।

श्री वारियर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत भेजे जाने वाले अनाज का मूल्य बराबर बढ़ रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अमरीका सरकार से ऐसा कोई संकेत मिला है कि आगे आने वाले अनाज का मूल्य भी अधिक होगा ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं नहीं समझता कि अमरीका सरकार द्वारा लिये जा रहे मूल्य में परिवर्तन होता रहा है। यहां मांग तथा आयात किय गय गेहूं के सस्ते भाव के आन्तरिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हम मूल्य में परिवर्तन करते रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : The wheat imported under P.L. 480 formed 40% to 58% of the total sales of wheat in our country during 1956 to 1964. In view of the widespread famine conditions this year, may I know whether the hon. Minister has made any assessment of the total quantity of wheat required to be imported this year?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी, हां। हम यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आन्तरिक उत्पादन कितना हुआ है और रबी की फसल में कितना उत्पादन होने की संभावना है। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा के द्वारा आयात करने की हमारी क्षमता सीमित है। इसलिए आयात के लिये अन्य व्यवस्था करनी ही है और वह प्रबन्ध मुख्य रूप से पी० एल० 480 है। जब तक अमरीका के साथ पी० एल० 480 के बारे में हम कोई दीर्घ-कालीन करार नहीं कर लेते, मैं यह नहीं कह सकता कि इस वर्ष हम कितना आयात करेंगे।

Shri Madhu Limaye : My question was whether any estimate has been prepared as to what will be the necessity?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : उत्पादन को ध्यान में रखकर अनुमान किया जा रहा है।

Shri Yudhvir Singh : Mr. Speaker, Sir, my name is there in both the questions but have not given an opportunity to put a question. At least those whose names are there on both the questions, should have been given an opportunity.

Shri Onkar Lal Berwa : Same is the case with me.

Mr. Speaker : I could not allot more than 20 minutes to both these questions. One should not feel if one is left out when there are so many members in the list.

सुरक्षित पत्तन सुविधायें

+

*240. **श्री हेम बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष के कारण सरकार कुछ अतिरिक्त तथा अपेक्षाकृत सुरक्षित पत्तनों की व्यवस्था करने का विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान पत्तनों में सुधार किया जायेगा अथवा नये पत्तन बनाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार की नीति भारत के सारे समुद्रीतट पर पर्याप्त पत्तन क्षमता विकसित करने की है जिससे भारत के समुद्री व्यापार में होने वाले विस्तार को तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति की कठिनाइयों और दबावों को हमारे पत्तन सहन कर सकें।

(ख) सरकार के विकास कार्यक्रम में मौजूदा पत्तनों के सुधार और नये बड़े पत्तनों का विकास करने का विचार है ।

श्री हेम बरुआ : मुझे आशा है कि सुरक्षा पत्तन सुविधाओं से सरकार का तात्पर्य प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी पत्तनों की सुरक्षा करना है । यदि उसका तात्पर्य यही है तो क्या सरकारने मौजूदा पत्तनों की शत्रुओं के हमलों से, मुख्य रूप से हमलों से रक्षा करने के लिये, क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : पत्तनों की सुरक्षा करना प्रतिरक्षा सैनिकों का एक अत्यावश्यक कर्त्तव्य है । मुझे आशा है कि उन्होंने हमारे पत्तनों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि मंत्री महोदय पत्तनों के लिये उत्तरदायी हैं अतः सुरक्षा के लिये की गई कार्यवाही के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उनका दूसरा प्रश्न क्या है ?

श्री हेम बरुआ : चूंकि कलकत्ता पत्तन उत्तरोत्तर पुराना होता जा रहा है अतः सरकार ने उसके नवीकरण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : हम कलकत्ता पत्तन में सुविधायें बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम मार्ग को मिट्टी निकाल कर–खुला रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमने सहायक पत्तन हल्दिया के विकास के लिये भी कार्यवाही की है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार हल्दिया पत्तन का कलकत्ता के निकट स्थानापन्न पत्तन के रूप में विकास करने के लिये वचनबद्ध है, क्या वर्तमान आपातकाल को देखते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं स्पष्ट कर दूं कि हल्दिया पत्तन का विकास स्थानापन्न पत्तन के रूप में नहीं किया जा रहा है । इसका विकास सहायक पत्तन के रूप में किया जा रहा है । इन दोनों में बहुत अन्तर है । यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफहमी हो तो मैं उसे दूर करना चाहता हूं । हम हल्दिया पत्तन का विकास कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : योजना के अन्तर्गत पत्तन की प्रस्तावित क्षमता क्या होगी और क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री राज बहादूर : हमें आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पत्तन की क्षमता 6 करोड़ 70 लाख टनभार की क्षमता हो जायेगी । यह क्षमता बढ़कर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्ततक 4 करोड़ से 4 करोड़ 50 लाख टनभार तक हो सकती है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : हल्दिया पत्तन के लिये हमने विश्व बैंक से जो सहायता मांगी थी क्या वह मिलने का अन्तिम आश्वासन मिल गया है अथवा इस सम्बन्ध में अभी विवाद चल रहा है ?

श्री राज बहादूर : विश्व बैंक तकनीकी विशेषज्ञों से कुछ तकनीकी जानकारी चाहता है । उन को रिपोर्ट भेज गई थी । इस समय मूल्यांकन दल भारत आया है और हम उनसे बात-चीत कर रहे हैं ।

श्री पें० वैंकेटा सुब्बय्या : क्या सरकार ने कुछ सहायक पत्तनों के, जो आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा आदि बड़े पत्तनों की तरह सामरिक महत्व के है, विकास के लिए कोई कार्य क्रम बनाया है, यदि हां तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री राज बहादुर : यथा संभव बड़े, दरम्याने तथा छोटे पत्तनों का विकास करने का प्रयत्न करते हैं और काकीनाडा पत्तन बाद की दो श्रेणियों के अन्तर्गत आता है।

डा० रानेन सेन : हल्दिया तथा प्रदीप पत्तनों के विकास करते समय यह विवाद उत्पन्न हुआ था कि इन पत्तनों से लौह अयस्क विदेशों को भेजा जायेगा अथवा मैंगनीज अयस्क। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया है?

श्री राज बहादुर : हम इस विवाद को अधिक महत्व नहीं देते। वास्तव में हल्दिया पत्तन से बड़ी मात्रा में कई वस्तुओं के, जिसमें किसी सीमा तक लौह अयस्क भी शामिल है, आयात और निर्यात किया जायेगा। जहां तक प्रदीप पत्तन का सम्बन्ध है, मुख्यत: यह लौह अयस्क के लिये है किन्तु इससे सामान्य माल का व्यापार भी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित नियम नहीं हैं। हम आयात अथवा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के स्तर अथवा माल की तत्काल लागत के अनुसार इन पत्तनों का उपयोग करेंगे।

श्री बसुमतारी : पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष को देखते हुए क्या सरकार का विचार जोगीघोपा और नियामतीघाट में दो पत्तन स्थापित करने का है; यदि हां, इन पर कितना व्यय होगा और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है।

श्री राज बहादुर : अब हम नदियों में भी पत्तन बना रहे हैं।

आसाम के लिये स्टीमर सेवा

+

*241. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल और आसाम के बीच चलने वाले स्टीमरों के अधिकांश नाविकगण (क) पाकिस्तानी राष्ट्रीक है;

(ख) क्या वर्तमान भारत पाकिस्तान संघर्ष को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित करने के लिये कि आसाम के साथ यह अत्यावश्यक संचार व्यवस्था भंग न हो; कोई विशेष उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जब से युद्ध शुरू हुआ तब से कलकत्ता से आसाम तक के नदी मार्ग की सेवाएं बंद पड़ी है। इस रास्ते को पुन: चालू करने का प्रश्न उपयुक्त समय पर उठाया जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसाम के लिए वैकल्पिक समन्वित परिवहन की व्यवस्था की गई है।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार ने जिस कम्पनी को इस समय अपने हाथ में लिया है क्या उसे सेवा अस्तव्यस्त हो जाने तथा जहाजों के अवरुद्ध हो जाने से अधिक घाटा नही होगा। इस कम्पनी को प्रतिवर्ष 90 लाख रुपये तक का घाटा होता है। इस कम्पनी के बन्द होने की स्थिति में सरकार ने सेवा चालू रखने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री राज बहादुर : मैंने इस सम्बन्ध में पीछे एक विस्तृत वक्तव्य दिया था। मैं फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि नदी स्टीमर सेवा के अस्तव्यस्त हो जाने पर निसंदेह घाटा होगा। हम एक ओर तो भारतीय क्षेत्र में जोगीघोपा से नियामतीघाट तक और उससे आगे डिब्रूगढ़ तक सेवाओं का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे है और दूसरी ओर आसाम दूसरी सहायक नदियों में भी सेवा चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कलकत्ता क्षेत्र में हम यथासंभव कुछ नदी मार्गों का उपयोग करने का विचार कर रहे हैं। इस तरह हम घाटे को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेवा अस्तव्यस्त हो जाने पर काफी घाटा होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान सरकार द्वारा चलाये गये "भारत कुचलो आन्दोलन" को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने समाप्त कर दिया, क्या सरकार भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय अनिवार्य छुट्टी पर भेजे गये इस कम्पनी के पाकिस्तानी कर्मचारियों के प्रति उदारता दिखायेगी ?

श्री राज बहादुर : ये तथ्य हमें समाचार पत्रों से प्राप्त हो रहे है और हम इस सम्बन्ध में सतर्कता-पूर्वक निगरानी रख रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1962 में चीनी आक्रमण के समय हड़ताल करने वाले इस कम्पनी के 15,000 कर्मचारियों में से 12,000 कर्मचारी पाकिस्तानी नागरिक थे, सरकार ने, हमारी अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच सेवा को बिना किसी प्रकार की गड़बड़ के चलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : 1962 से अब तक काफी परिवर्तन हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान में भी परिवर्तन की लहर चल रही है।

डा० मा० श्री० अणे : मंत्री महोदय ने बताया है कि फिर से सेवा उपयुक्त समय पर चालू की जायेगी। यह समय कब आयेगा ?

श्री राज बहादुर : यह बहुत कठिन प्रश्न है। उपयुक्त समय का तात्पर्य है कि जब अनुकुल स्थिति पैदा हो जायेगी हम सेवा चालू करेंगे।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखतेहुए कि पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष शीघ्र समाप्त नहीं होगा, क्या सरकार ने इन स्टीमरों में भारतीय को भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, हमने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the Government ascertained the number of Pakistani Nationals working on these steamers and whether they have also ascertained that the Pakistani crews of these steamers were engaged in anti-Indian activities?

Shri Raj Bahadur : 6,600 Pakistani crews were there and ....

श्री हेम बरुआ : 15,000 कर्मचारियों में से 12,000 पाकिस्तानी नागरिक थे।

श्री राज बहादूर : मेरे पास अधिकृत आंकड़े हैं। कुल 6,000 कर्मचारी थे जिन में से 5,300 रीवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी में काम करते थे और शेष अन्य गैर सरकारी कम्पनियों में।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Were they found engaged in anti-Indian activities?

Shri Raj Bahadur : I have no information about such activities. During the conflict, Pakistanis were interned in West Bengal.

श्री अ० प्र० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टीमर सेवाओं में अधिकांश कर्मचारी पाकिस्तानी नागरिक है, सरकार ने इन सेवाओं में भारतीयों को भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये क्या विशिष्ठ कार्यवाही की है और यह कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री राज बहादुर : अवश्य होने पर हम यह कार्यक्रम छः महीने में पूरा कर सकते हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : जब कि रेलवे पाकिस्तानी नागरिकों को बरखास्त कर दिया है, क्या परिवहन मंत्री इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : हमने उन्हें कलकत्ता क्षेत्र में निकाल दिया है । इस समय सेवायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्णतः नहीं चल रही है । इस समय कर्मचारी हमारी आवश्यकता से फालतू हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : चूंकि मंत्री महोदय ने दावा किया है कि 1962 की तुलना में अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है अतः मैं जानना चाहता कि इन कम्पनियों में 1962 की तुलना में भारतीय कर्मचारियों का अनुपात कितना बढ़ा है ? क्या इन कम्पनियों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों का अनुपात बढ़ा है अथवा केवल आंकड़े ?

श्री राज बहादुर : जिस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया था वह दूसरे संदर्भ में था । आंकड़ों के बारे में मुझे समय चाहिए ।

श्री बूटा सिंह : भारत सरकार इन सेवाओं को भारतीय नौ सेना को क्यों नहीं सौंप देती ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं जानता कि भारतीय नौ सेना इसे लेना चाहेगी ।

फसल बीमा योजना

\+

*243. **श्री लिंग रेड्डी** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री हेडा :
श्री बालकृष्णन :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मलाईछामी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांविधिक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इच्छुक राज्य फसल बीमा योजना चालू कर सके इसके लिये कानून बनाने का केन्द्रीय सरकार ने निश्चय कर लिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लिंग रेड्डी : राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कितने समय से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री शाहनवाज खां : यह काफी समय से सरकार के विचाराधीन है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि सरकार ने इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू करने का निर्णय किया है ?

श्री शाहनवाज खां : हम पूरी तरह चाहते हैं कि यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू हो। वास्तव में योजना का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है जिस पर इस समय मंत्रिमंडल विचार कर रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकार आरंभ में यह योजना पंजाब में लागू करेगी । क्या इस योजना के अन्तर्गत सामयिक अनिश्चिततायें भी आयेंगी ?

श्री शाहनवाज खां : हमारा विचार इसे पहले पंजाब में लागू करने का है । किन्तु इसे लागू करने से पहले सभा को इस सम्बन्ध में कानून बनाना होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : फसल् बीमा योजना कार्य सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र को अथवा सहकारी क्षेत्र को ?

श्री शाहनवाज खां : यह बीमा के अन्तर्गत होगा ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य सीधे मंत्री से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं । उन्हें मेरे जरिये प्रश्न पूछने चाहिए ।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह कार्य किस क्षेत्र को सौंपा जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : यह सरकारी क्षेत्र को सौंपा जायेगा ।

श्री बूटा सिंह : क्या पंजाब सरकार ने इस योजना को पंजाब में आरंभ करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कई अभ्यावेदन किये हैं और यदि हां, तो यह योजना स्थगित क्यों की गई ?

श्री शाहनवाज खां : मैं बता चुका हूं इस योजना को कार्यरूप देने के लिये सभा को कानून बनाना होगा । जैसे ही कानून बन जायेगा पंजाब में कार्य आरंभ हो जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the reaction of various States on the Crop Insurance Scheme? What are the names of the States which are in favour of this scheme?

Shri Shahnawaz Khan : The Panjab is the only State which does always come forward to take concrete steps and initiative. The Punjab has taken initiative in the matter and we will also take similar steps in other states after gaining experience.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या बीमा केवल खाद्य फसलों का ही किया जायेगा अथवा नकदी फसलों का भी किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : इसमें दोनों शामिल हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि सरकार काफी समय से यह योजना आरंभ करने का विचार कर रही है। इसमें इतना अधिक समय क्यों लगा है तथा विधेयक पारित करके योजना कब लागू की जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक नया कार्य है, अतः हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ा। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य था अतः हमें इसमे विदेशी विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ी और इसमें समय लगना स्वाभाविक था ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों, अथवा कम से कम पंजाब सरकार, को सूझाव देने का है कि इसकी प्रीमियम को अलग वसूल करने के बजाय लगान के साथ ही लिया जाये?

श्री शाहनवाज खां : प्रीमियम की वसूली लगान के साथ ही की जायेगी ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have considered over this fact that in the absence of this Crop Insurance Scheme a farmer who has a standing crop of sugarcane worth Rs. 10,000 can not get even Rs. 100 and if so, the measures proposed to be taken by Government to improve the situation?

Shri Shahnawaz Khan : The situation is not so bad as the hon. Member has stated. Farmers are given loans by the Co-operatives and they also get *Taccavi* loans.

श्री जसवन्त मेहता : योजना को विचार के लिये मंत्रिमंडल के सामने कब रखा जायेगा और सभा में विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : मैं सभा को बता चुका हूं कि योजना का सार मंत्रिमंडल के सामने है और मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृत किये जाने पर विधेयक के रूप में सभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has just stated that this scheme is being introduced. May I know whether the Government have collected information from all the States in this regard and sought their cooperation and if so, the reaction of the State Governments thereon and the names of States which have promised to give cooperation.

Shri Shahnawaz Khan : We wrote to all State Governments and they are of the view that this scheme should be first introduced in Punjab and they will follow.

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि इस योजना पर विचार करते समय विदेशी विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया था और यदि हां, तो सरकार के विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने की क्या आवश्यकता थी जब कि हमारे विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में काफी योग्य हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ देशों में फसल बीमा योजना लागू है और स्वभावतः हम उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहते थे । खाद्य तथा कृषि संगठन देशो को नये विचारों का विकास करने में सहायता देता है और हम भी इस संगठन से सहायता लेते हैं ।

श्री रंगा : मैं नहीं जानता कि फसल बीमा योजना का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति की जांच पड़ताल के बाद तैयार की गई रिपोर्ट पर सरकार तथा उसके सलाहकारों ने विचार किया या नहीं ।

क्या यह सच नहीं है कि पंजाब सरकार ने प्रयोग के रूप में यह योजना लागू करने का स्वयं विचार नहीं किया और इसी कार्य के लिये वे पंजीकरण चाहते थे और यदि हां, तो सरकार इसे एक राष्ट्रीय योजना का रूप देकर सभी राज्यों में लागू करने में कितना समय लेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह योजना पंजाब में लागू करने के बाद हम इसके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे और उसी के आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has stated that this scheme will first be introduced in Punjab. Perhaps it is being done because there are canals in Punjab. May I know whether it will first be introduced in canal areas ?

Shri Shahnawaz Khan : It is not necessary that it is introduced only in canal areas. It will be left to the desirous State Governments, to introduce it.

डा० सरोजिनी महिषी : क्या विदेशों में विशेषज्ञों से फसल बीमा की राष्ट्रीय योजना की तैयारी के सम्बन्ध में तकनीकी पहलुओं पर परामर्श किया गया है और यदि हां, तो किन पहलुओं पर परामर्श किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : हम ने एफ० ए० ओ० के विशेषज्ञ श्री वामचु से परामर्श किया था, उन्होंने प्राधिकार परियोजना को देखा था और व्यवहार्य बताया था ।

श्री पु० र० पटेल : ऐसा लगता है कि फसल बीमा योजना को इस देश में लागू होने में अभी समय लगेगा । जब तक यह योजना सारे देश में लागू नही होती तब तक के लिये क्या सरकार की कृषकों की वर्षा न होने या दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों से हुई हानि की पूर्ति करने के लिये कोई योजना है ?

श्री शाहनवाज खां : जब भी कुछ प्राकृतिक विपत्ति होती है तो कृषकों को लगान में कुछ छूट दी जाती है और कुछ उधार भी दिया जाता है ।

Shri Gulshan : The hon. Minister has said that a bill will be introduced in the House regarding crop insurance. May I know whether any time has been fixed as to when this bill will be introduced ?

Shri Shahnawaz Khan : As I have already stated the summary of the scheme has been submitted to the Cabinet. After the approval of the cabinet the Minister of Parliamentary Affairs will try to introduce this in the House.

Shri Gulshan : By what time it will come before the House ?

Mr. Speaker : It can not be said.

\+ **भारत के खाद्य निगम द्वारा चावल का समाहार**

*244. **श्री कपूर सिंह :** **श्री प्र० के० देव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री सोलंकी : **डा० रानेन सेन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम को आगामी खरीफ की फसल में चावल का समाहार करने का काम नहीं सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी नहीं । भारत का खाद्य निगम आगामी खरीफ की फसल में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल राज्यों और संघीय क्षेत्र पांडेचरी और करईकल में आंशिक रूप से चावल की सीधी खरीदारी करगा ।

श्री वासुदेवन नायर : उन्होंने बताया है "अंशता" या कुछ ऐसा ही ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : राज्यों के कुछ भागों में वे स्वयं खरीद करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : चावल के उत्पादन तथा देश में चावल की वास्तविक आवश्यकता में लगभग कितना फर्क है और उस को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बंधित नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस का फैसला आप को करना है न की मंत्री को ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कृपा करके प्रश्न को दोहरायेंगे क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह इस ओर नहीं था ।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न इस निगम द्वारा चावल की प्राप्ति से सम्बन्धित है । मैं जानना चाहता था कि देश में चावल के अनुमानित उत्पादन और वास्तविक आवश्यकता में कितना फर्क है । वह कहते हैं कि प्रश्न उत्पन्न ही नही होता ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : निश्चय ही यह प्रश्न खाद्य निगम द्वारा प्राप्ति से सम्बन्धित है । उत्पादन एक पृथक चीज है इस लिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कपूर सिंह : आवश्यकतायें प्राप्ति के आधार पर हैं । जब आवश्यकता नहीं होगी तो प्राप्ति कैसे होगी ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो वह सूचना चाहते हैं ।

श्री जी० भ० कृपलानी : उन्होंने ऐसा नही कहा कि उन को सूचना चाहिये ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में जहां चावल फालतू है वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार तथा खाद्य निगम को आंध्र प्रदेश के फालतू चावल वाले जिलों तथा दूसरे जिलों से चावल के खरीदने की आज्ञा नहीं दे रही है ? यदि हां, तो ऐसे राज्यों में खरीदने का क्या लाभ है जहां की सरकार फालतू अनाज वाले जिलों से खरीदने की आज्ञा नही देती ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : आंध्र प्रदेश में दो योजनायें हैं । एक योजना डैल्टा क्षेत्र से संबंधित है और दूसरी गैर-डैल्टा क्षेत्र से । गैर-डेल्टा क्षेत्र में उत्पादकों को लगान देना पड़ता है और उस को अब खाद्य निगम प्राप्त करेगी । जहां तक डैल्टा क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां उत्पादकों पर ऐसा कोई लगान नहीं है परन्तु वहां मिल वालों पर लगान है । इस लिये प्रश्न मिल वालों से प्राप्ति का है और मिल वालों से हम भण्डार ले लेंगे । खाद्य निगम मिल वालों से प्राप्ति के समय ही सामने आती है ।

Shri Yashpal Singh : The Government are to employ separate staff for procurement and that has to be paid lakhs of rupees as salaries. If we give remunerative prices to the farmers they themselves will give the stocks to the Government and then there will be no need of procurement. May I know why remunerative prices are not being given to them?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य को मालूम है कि हम ने न केवल इस वर्ष परन्तु गत वर्ष भी अच्छे और प्रलोभन वाले मूल्यों की घोषणा की थी ।

श्री प्र० के० देव : जब कि हमें यह जान कर दुख होता है कि कुछ राज्य केन्द्रीय योजना से सहमत नहीं हैं जैसा कि मैसूर राज्य क्योंकि वहां की सरकार दल के हित को अधिक मानती है ? या क्या यह इस लिये कि भारत खाद्य निगम की प्राप्ति योजना व्यवहार्य नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गत वर्ष उड़ीसा में सरकार ने अपने साधनों से मिल वालों से विशेषकर प्राप्ति की थी । इस वर्ष कमी को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने स्वयं प्राप्ति करने का सुझाव दिया है । इस बारे में उड़ीसा सरकार से अभी बात चीत हो रही है ।

डा० रानेन् सेन : क्या यह सच है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि चावल का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया जाना चाहिये नहीं तो चावल की प्राप्ति में कठिनाई होगी और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस वर्ष न्यूनतम 'सुपोर्ट' मूल्म घोषित करने की नीति है और राज्य सरकारें प्राप्ति मूल्य इस से अधिक नियत कर सकती है और अधिकतर राज्य सरकारों इस 'सुपोर्ट' मूल्य से अधिक प्राप्ति मूल्य नियत कर भी दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है और कि राज्य सरकार ही कृषकों से धान और चावल की प्राप्ति करेगी, तो क्या यह सच है कि वहां कोई न्यूनतम मूल्य नियत कर दिया गया है और क्या यह भी सच है कि मूल्य 16 रुपये नियत किया गया है जबकि कृषक 21 रुपये की मांग करते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि मुझे ठीक याद है तो हम ने धान का कम से कम मूल्य 39 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया था परन्तु प्राप्ति के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने चावल की प्राप्ति के लिये 41.12 प्रति क्विंटल या कम से कम मूल्य नियत किया है । मुझे विश्वास है कि हाल ही में इस को 41 रुपये 12 पैसे से कुछ बढ़ाने की मांग हुई है । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या सरकार बता सकती है कि आंध्र प्रदेश के डैल्टा क्षेत्र में मिल वालों मध्यवर्ती क्यों रखा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह चिरकालसे क्रय का काम कर रहे हैं आंध्र सरकार महसूस करती है कि यदि नई प्रणाली को लागू किया गया तो शायद इस से प्राप्ति की क्रिया तितर बितर हो जाये विशेषकर जब कि हम कठिनाई में है । यही कारण है कि उन को प्राप्ति की आज्ञा दी गई है परन्तु इस प्रणाली पर हमारा प्रभावशाली नियंत्रण है ।

श्री मुथिया : सारे देश में मद्रास राज्य विशेषकर, खरीफ मौसम में चावल प्राप्ति के लक्ष्य क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लक्ष्य अभी नियत किये जाने वाले हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : आम तौर पर जब राज्यों में कृषकों से खाद्यान्नों की प्राप्ति की जाती है तो भुगतान बहुत विलम्ब से किया जाता है । क्या खाद्य निगम भुगतान तुरन्त करेगा या वह भी भुगतान करने के लिये कुछ समय लेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक खाद्य निगम का सम्बन्ध है वह सौदा करते समय ही भुगतान कर देंगे । खाद्य निगम का यह एक लाभ है । जब राज्य सरकारें कोई काम हाथ में लेती हैं तो वे भुगतान करने में कुछ समय लेती हैं । यह एक वाणिज्यक उपक्रम है और इससे उत्पादकों को लाभ होगा ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मोटे अनाज जैसा कि जवार और बाजरा, का वर्तमान मूल्य लगभग 61 रुपये से 65 रुपये है और कि सरकार ने नई फसल का मूल्य 40 रुपये क्विंटल नियत किया है ? यदि हां, तो क्या हम इस को प्रोत्साहन मूल्य कह सकते है और क्या कृषक जिन को इस वर्ष पहलेसे अधिक खर्च करना पड़ा है, अपने खाद्यान्नों को विक्रय करने को तैयार होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क कर रहे हैं । आप कोई सूचना तो मांग नहीं रहे हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : नहीं महोदय । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि क्या हम इस को प्रोत्साहन मूल्य कह सकते हैं और क्या हम आशा कर सकते हैं कि कृषक इन मूल्यों पर खाद्यान्नों को बेचने को तैयार हो जायेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैं ने पहले बताया केन्द्रीय सरकार की नीति कम से कम मूल्य को सुनिश्चित करना है । जहां तक प्राप्ति के मूल्य का सम्बन्ध है राज्यसरकारों को उंचे स्तर पर मूल्य नियत करने की स्वतंत्रता है । यह मध्य प्रदेश सरकार के लिये है कि वह सब पहलुओं पर विचार करके उचित मूल्य नियत करे जिस पर वह खरीद करेगी । मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार कृषकों की आवश्यकताओं को उतना ही समझती है जितना मैं या माननीय सदस्य ।

श्री कोया : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि भूमि की उर्वरता पर ध्यान दिये बिना ही लगान की एक ही दर नियत की जाती है जिस से कृषकों को बहुत कठिनाई का सामना होता है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आप किस राज्य के बारे में कह रहे हैं ।

श्री कोया : केरल के बारे में ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केरल में बहुत ही साधारण लगान लगाया गया है और इस लिये प्रत्येक खेत की उर्वरता का सर्वेक्षण करना तथा उस के आधार लगान नियत करना सम्भव नहीं है परन्तु लगान की मात्रा इतनी नियत की गई है कि कम उर्वरता के खेत वालों को भी यह बोझ न महसूस हो ।

Shri Rameshwara Nand : First of all the hon. Minister told that the Food Corporation would start purchasing rice from February. Rice came to the market may late in the country and it has already been sold. Now the Food Corporation will start purchasing rice in February, may I know the difference in rates at which the Corporation will purchase and the rate at which the farmers have already sold the rice?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : फरवरी में नही अपितु पहली सितम्बर से ही निगम ने चावल क्रय करना आरम्भ कर दिया है ।

श्री रंगा : यह कैसे सम्भव है कि खाद्य निगम को कृष्णा गोदावरी डैल्टा के मिल वालों तथा अनाज के उत्पादकों से अनाज खरीदने की अनुमति नहीं या वह खरीद नहीं कर रही है यद्यपि गण्टूर जिले के उत्पादकों से प्राप्ति की गई है और कृष्णा तथा पश्चिम गोदावरी जिलों के मिल वाले यह शिकायत कर रहे हैं कि उन के पास अधिक भण्डार हैं और उनको कोई क्रय करने वाला नहीं है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निगम अभी हाल ही में बनाई गई है । अभीतक मिल वाले ही कृषकों से क्रय करते थे और यह प्रथा चली आ रही है । धान के पिष्ट होने के बाद ही हम भण्डारों की मिल वालों से खरीद करते हैं । मैं आप से सहमत हूं कि अन्ततः निगम को सीधा उत्पादकों से खरीद की प्रणाली को अपनाना होगा ।

श्री रंगा : प्रश्न यह नहीं है । मिल वालों के पास भारी भण्डार हैं और उन्होंने काफी राशि लगा रखी है जो रुकी पड़ी है । जब कि केरल में उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है निगम इन को बिल्कुल क्रय नहीं कर रही है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य से यह सूचना प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता हुई है उपलब्ध भण्डारों को शीघ्र क्रय कर लिया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has just now told that since last year they have fixed the prices. May I know whether the attention of the Government have been drawn to the fact that this year the foodgrains arrivals are less than before in the markets and the reasons therefor?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा विचार नहीं कि प्रोत्साहन मूल्यों का नियत किया जाना ही बाजार में खाद्यान्नों के कम आने का कारण है इस वर्ष अनाज के बाजार में पहले से कम आने के कुछ और कारण हैं ।

श्रीमती विमला देशमुख : इस प्राप्ति योजना से सरकार को कितना अनाज प्राप्त होने की आशा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रत्येक राज्य के लिये लक्ष्य अभी निर्धारण किये जा रहे हैं । अभी इस में कुछ समय लगेगा । दिसम्बर के अन्त तक लक्ष्य निर्धारण कर लिये जायेंगे ।

श्री क० ना० तिवारी : राज्य सरकारों की प्राप्ति की अपनी योजनायें हैं और इसी कारण से निगम प्राप्ति का अपेक्षित कार्य नहीं कर सकी है । यदि हां तो सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विचार का प्रश्न यह है कि निगम केवल पहली जनवरी से ही बनी है । पहले छः मास उन को संगठन करने, भण्डार एकत्र करने तथा उन के बांटने के कार्यक्रम को बनाने में लग गये हैं । पहली सितम्बर से उन्होंने अनाज की प्राप्ति का कार्य आरम्भ किया है । हमें देखना है कि इस नई निगम पर एक दम बहुत से कामों का बोझ न पड़ जाये कि कहीं इसको बन्द करना पड़ जाये । इसीलिये मुझे विश्वास है कि सारे देश में खाद्य निगम के प्राप्ति के कार्य को धीरे धीरे लागू करना सम्भव होगा ।

अनाज का आयात

*245. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री पाराशर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब० कु० दास :
श्री काजरोलकर :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेमराज :
श्री कपूर सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसबै :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से अनाज के आयात करारों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : दिसम्बर, 1965 तक गेहूं और चावल आयात करने के लिये निम्नलिखित करार किये गये हैं :—

(1) थाइलैण्ड से 53.5 हज़ार मीट्रिक टन चावल आयात करने के लिये 10 सितम्बर, 1965 का एक करार ।

(2) सितम्बर, 1964 के पी० एल० 480 करार में 26 सितम्बर, 1965 और 4 नवम्बर, 1965 के संशोधन । प्रत्येक संशोधन में 5 लाख टन चावल जिसका लदान नवम्बर और दिसम्बर, 1965 में होना है खरीदने के लिये अतिरिक्त निधि की व्यवस्था है ।

(3) नवम्बर, 1965 में संयुक्त अरब गणराज्य से 3,700 टन चावल मंगाने के लिये एक सौदा । बाद में कुछ अन्य करार पूरे होने की आशा है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether there is any possibility of long term agreement being finalised or every month and every year we are to go to them ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा मैं ने प्रश्न की तीसरी कंडीका में बताया है वे विचाराधीन हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ में साधारण निर्वाचन

*246. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **विधि** मंत्री गोआ में साधारण निर्वाचनों के बारे में 31 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : इस मामले में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

खरीफ़ फसलों का उत्पादन

*247. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कैसी खरीफ़ फसल होने की आशा है;

(ख) क्या कोई अनुमान लगाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके राज्यवार आंकडे क्या हैं; और

(घ) देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर आगामी फसलों का उत्पादन बढाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : 1965-66 में खरीफ़ के उत्पादन की मात्रा का अनुमान इतना शीघ्र नहीं लगाया जा सकता है। परन्तु चालू खरीफ मौसम में वर्षा की कमी के कारण दक्षिणी राज्यों के अतिरिक्त अन्य अधिकांश राज्यों में खरीफ के अनाज का उत्पादन गिरने की आशा है। उत्पादन के पिछले वर्ष के रिकार्ड में इस वर्ष खरीफ के अनाज का उत्पादन लगभग 30 लाख टन होने की संभावना है।

(घ) राज्य सरकारों में आपातकालीन खाद्य आन्दोलन चलाने के लिये कहा गया है। इसके अन्तर्गत रबी तथा ग्रीष्म मौसम में और अधिक क्षेत्र में खेती करने का विचार है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि एक ही जमीन पर कई प्रकार की फसल उगाने का नया ढंग इस्तेमाल करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि इन क्षेत्रों में बीज उर्वरक तथा कीटाणुनाशक दवाइयों में आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं। सिंचाई संभावनाओं के उचित उपयोग का प्रस्ताव है। ग्रामीण तथा नगरिय खाद कार्यक्रम बढाया जा रहा है तथा 1966 के खरीफ की धान की फसल के लाभ के लिए अप्रैल-मई के महीनों में हरी खाद वाली फसल की खेती करने का सुझाव दिया गया है।

Ship-building Programme

*248. **Shri Bagri :** **Shri P. K. Deo :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Solanki :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Kapur Singh :**
Shri P. C. Borooah : **Shrimati Tarkeshwari Sinha :**
Shri Rameshwar Tantia : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of ship-building at Visakhapatnam ship-yard has been curtailed due to the difficulties of foreign exchange; and

(b) if so, the other steps taken to meet the shortage of ships?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) There is no curtailment in the ship construction programme of the Hindustan Shipyard, Visakhapatnam. Although due to shortage of foreign exchange, some delays are occurring in respect of some of the ships currently under construction at the shipyard.

(b) Does not arise in view of (a) above.

राजस्थान में अभाव की स्थिति

*249. **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री प० ला० बारूपाल : **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री तन सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री यशपाल सिंह :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री न० प्र० यादव : **श्री बागड़ी :**

श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने दुर्भिक्ष की स्थिति दूर करने के लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को अधिक अनाज तथा चारा भेजने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) इन दोनों राज्यों को अनाज का अतिरिक्त कोटा देने के लिए प्रबन्ध कीए गए हैं। परन्तु राज्य सरकारों ने केन्द्र से चारा अभी नहीं मांगा है।

उर्वरकों के मूल्य निर्धारित करना तथा उनका वितरण करना

*250. श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है जो किसानों को उर्वरकों के वितरण तथा उनके भावों की जांच करने के लिये स्थापित की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री दी० चं० शर्मा) : (क) और (ख) : उर्वरक सबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय मछली विपणन निगम

*251. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिंमतसिंहका :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पैं० बैकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय मछली विपणन निगम बनाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो यह कब तक अपना काम आरम्भ कर देगा, और

(ग) इसके कौन कौन सदस्य होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) (क) जी हां। भारत सरकार ने 29 सितम्बर, 1965 को केन्द्रीय मात्स्यकी निगम लि० जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा, के नाम की एक कम्पनी रजिस्टर्ड की है।

(ख) आशा है कि इस निगम के इस महीने के अन्त में काम प्रारम्भ कर देने की सम्भावना है।

(ग) निगम के निदेशकों के बोर्ड में 14 सदस्य होंगे जो कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग के प्रतिनिधि हैं।

देसी गेहूं की सप्लाई

252. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और पंजाब में सरकार द्वारा प्रबन्धित अथवा लाइसेंस प्राप्त दुकानों उचित मूल्य की दुकानों पर केवल आयात किया गया गेहूं ही बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों में देसी गेहूं क्यों नहीं बेचा जा रहा है; और

(ग) इन दुकानों पर मिश्रित तथा अपमिश्रित अनाज और आटा न बिके इस बारे में क्या सावधानी रखी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) और (ख) : पंजाब में देशी तथा आयातित दोनों गेहूं उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा दिया जाता है। दिल्ली में केवल आयातित गेहूं का आटा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दिया जाता है।

पंजाब गेहूं की दृष्टि से अधिशेष राज्य है और उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिये तथा कमी वाले राज्यों को देने के लिये देशी गेहूं खरीदा है। पंजाब में जनसंख्या के कम आय वाले वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये उचित मूल्य की दुकानों पर कुछ आयातित गेहूं भी दिया जाता है। दिल्ली कमी वाल राज्य है और जन संख्या के ऊंची आय वाले वर्गों के लिये व्यापारिक मार्ग से पंजाब से गेहूं की सप्लाई प्राप्त करता है। दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से जो आयातित गेहूं का आटा वितरित किया जाता है वह मुख्यतः जनसंख्या के कम आय वाले वर्गों के लिये होता है। दिल्ली में जब सांविधिक राशन व्यवस्था लागू होगी तब वितरण के तरीके में भी परिवर्तन होने की सम्भावना है।

(ग) उचित मूल्य की दुकाने जो आयातित गेहूं बेच रही हैं वे इसके साथ ही साथ देसी गेहूं नहीं बेच सकती हैं। खाद्यान्नों की किस्म का नियन्त्रण खाद्य अपमिश्रण निवारण आदि नियम के द्वारा किया जाता है। दोनों राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन दुकानों का बराबर निरीक्षण किया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का सेवा विस्तार कार्यक्रम

***253. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विस्तार कार्यक्रम क्या है और 1965-66 तथा 1966-67 में यह किन किन क्रमों में पूरा किया जायेगा; और

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार विदेशों में कुछ कार्यालय खोलने का है और यदि हां, तो इसमें क्या औचित्य है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कारपोरेशन ने 1965-66 के दौरान दो कारवेल विमानों को खरीदने और चार्टर पर दो फांकर फ्रेण्डशिप विमान प्राप्त करने की योजना बनाई है। कारपोरेशन 1966-67 के दौरान एक फांकर फ्रेण्डशिप प्राप्त करेगा और चार्टर पर लिए दो विमानों के स्थान पर दो और फ्रेण्डशिप विमान खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है। उनकी 1966-67 में सहायक मार्गों पर चलाने के लिए छः एफ-27/अवरो किस्म के विमान और छः विमान खरीदने की भी योजनाएं है। वे एयर इंडिया से एक बोइंग विमान चार्टर पर लेने या एक और कारवेल विमान खरिदने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

(ख) कारपोरेशन का विदेशों में बिक्री कार्यालय खोलने का प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है।

बेरोजगारी बीमा योजना

*254. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री काजरोलकर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री महम्मद कोया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी बीमा योजना लागू करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) क्या कुछ मालिकों ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अभी नहीं। योजना पर अभी तक विचार हो रहा है।

(ख) और (ग) : 30 और 31 अक्तूबर, 1965 को नयी दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 23 वें सत्र के सामने यह योजना रखी गयी थी। कामगारों के प्रतिनिधियों ने सिद्धांत रूप में साधारणतया इस विचार का स्वागत किया था। नियोजकों के प्रतिनिधियों ने योजना के अध्ययन के लिये और समय दिये जाने की इच्छा प्रकट की थी। योजना को स्थाई श्रम समिति के सामने रखे जाने का निर्णय किया गया था, क्योंकि आवश्यक ब्यौरे पर विचार किया जाना था।

Prices of Sugarcane

*255. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether sugarcane price has been fixed;

(b) if so, the basis therefor;

(c) the quantity of sugar likely to be produced this year;

(d) whether it is a fact that the mills will again find it difficult to procure sugarcane at the present sugarcane price; and

(e) if so, the steps being taken in regard thereto?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) The basic minimum price of sugarcane fixed is the same as in 1964-65 *i.e.* Rs. 5·36P. per quintal linked to a recovery of 10·4 per cent or less with provision for increase in price at the rate of 4 paise per quintal for every 0·1 per cent increase in recovery over 10·4 per cent.

(c) It is too early to give any reliable estimate of sugar production during this year at this stage.

(d) There is no cause for such a presumption.

(e) Does not arise.

उर्वरकों का आयात

*256. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरकों तथा उर्वरकों का उत्पादन करने के लिये आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए काफी विदेशी मुद्रा मांगी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों को आरम्भ करने का है, जिनकी उपज अधिक उर्वरकों के प्रयोग से ही अधिक हो सकती है और यदि हां, तो वे फसलें क्या हैं; और

(ग) नई प्रणाली के रूप में विशेष कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5152/65।]**

दिल्ली में राशन व्यवस्था

*257. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री बासप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिंमत सिंहका :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डे :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन व्यवस्था लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : दिल्ली में 1-12-65 से सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का विचार है। यह राशन-व्यवस्था सभी शहरी क्षेत्रों में जो नई दिल्ली नगरपालिका समिति, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमा में हैं तथा कुछ शहरी गांवों में लागू होगी।

आरम्भ में राशन कार्डों से गेहूं, गेहुं की बनी वस्तुएं, चावल और शर्करा वितरित की जाएगी।

सरकार खाद्यान्न खरीदने, संग्रह करने और दुकानदारों तथा अधिक मात्रा में उपभोग करने वाले जैसे होटल आदि को खाद्यान्न देने के प्रबन्ध करेगी।

निजी विमान सेवायें

*258. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में माल तथा यात्री यातायात के लिये निजी विमान सेवाओं को कार्य करने की अनुमति दी गई है;

(ख) ऐसी विमान सेवाओं के क्या नाम हैं और यदि उन्हें इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कोई सहायता देती है तो उसका ब्यौरा क्या है और वे किस वर्ष से कार्य कर रही हैं; और

(ग) एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा इन सेवाओं को अपने हाथ में न लेने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : निम्नलिखित निजी एयरलाइनें उनको जारी किये गये असूचित परमिटों की शर्तों के अधीन उनके नाम के आगे दी गयी तारीखों से असूचित विमान सेवाएं चला रही हैं :

एयरलाइन का नाम	तारीख जब से विमान सेवाएं चला रहीं हैं
1. एयर सर्वे कं० आफ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड	1-10-1946
2. एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड	25-9-1954
3. भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	23-2-1954
4. कम्बाटा अविएशन (प्रा०) लिमिटेड	26-8-1963
5. जमौयर कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड	8-7-1948
6. कलिंग एअरलाइन्स (प्रा०) लिमिटेड	13-2-1958
7. कस्तूरी एंड सन्ज लिमिटेड	23-10-1963

उपर्युक्त एयरलाइनों में से किसी को भी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा सहायता नहीं दी जा रही है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भी, जब कभी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होती है और सेवाएं लाभप्रद होती हैं, असूचित विमान सेवाएं चलाता है।

Demurrage for Unloading of Wheat

*259. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had to pay demurrage for not unloading the wheat imported from U.S.A. in time in the months of May and June, 1965;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the reasons for not unloading the wheat in time?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 5.93 lakhs. However, despatch amounting to Rs. 2·85 lakhs was also earned on these ships in this period reducing the nett demurrage to Rs. 3·08 lakhs.

(c) Demurrage was incurred for the following reasons :—

(i) Owing to the heavy congestion and consequent berthing delay at all the Indian ports resulting from the arrival of a large number of ships in quick succession after they had sailed from U.S. Ports where they were held up due to the longshoremen strike lasting about two months.

(ii) On some occasions, clearance from docks could not keep pace with discharge from ships owing to the unprecedented heavy arrivals and this resulted in slow discharge from ships.

(iii) At the minor ports the discharge which takes place in stream, in barges, was slow as the available number of barges was insufficient compared to unusual heavy arrival of foodgrains.

(iv) On the West Coast where most of the demurrage was incurred monsoonish weather conditions hampered discharging operations.

निराश्रित महिलाओं के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम

*260. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में विधवाओं तथा अन्य निराश्रित महिलाओं के लिये नए संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरम्भ करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस कार्य के लिये पंजाब में कोई स्कूल खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो ये स्कूल किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1965 तक की कालावधि में 73 नये संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। इनके अतिरिक्त उक्त कालावधि में 36 और पाठ्यक्रम मंजूर किये गये हैं तथा 1964-65 में आरम्भ किये गये 106 पाठ्क्रम जारी रखे गये हैं।

(ख) सरकार ने स्वयं इस प्रयोजन के लिये कोई स्कूल नहीं खोले हैं क्योंकि संक्षिप्त पाठ्क्रमों की योजना स्वैच्छिक कल्याण संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) पंजाब में संक्षिप्त पाठ्क्रम चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पते निम्न विवरण में दिये गये हैं।

क्रम संख्या	संगठन का नाम और पता	पाठ्यक्रम की अवधि
1.	श्री भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी, जिला गुड़गांव .	1964-66
2.	ग्रामीण महिला/बाल स्वैच्छिक कल्याण संगठन, सिद्वान खुर्द, जिला लुधियाना।	यथोपरि
3.	विद्यापीठ शिक्षा संस्था, मंडी, गुरदासपुर . . .	यथोपरि
4.	नारी निकेतन, नाकोदर रोड, जलंधर शहर .	यथोपरि
5.	एस० जी० एस० खालसा हायर सेकेन्डरी स्कूल, आनंदपुर साहब, जिला होशियारपुर।	यथोपरि
6.	सिख कन्या महाविद्यालय, फिरोजपुर शहर .	1965-67
7.	कन्या गुरुकुल हायर सेकेन्डरी स्कूल, डाकखाना खानपुर कलां, जिला रोहतक।	यथोपरि
8.	लड़कियों के लिये देव समाज कालेज, अम्बाला शहर	यथोपरि
9.	ए० एस० हाई स्कूल, पुण्डरी (करनाल) . . .	यथोपरि

पाकिस्तान द्वारा विमान उड़ानों में बाधा

*261. **श्री प्र० के० देव :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष आरंभ होने के बाद से पाकिस्तान विभिन्न एयरलाइनों के भारत आने वाले तथा भारत से जाने वाले विमानों की उड़ानों में कोई बाधा डालता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की बाधा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : भारत आने वाले कुछ विमान पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा कराची में रोके गये हैं और उनमें से डाक और सामान उतारा गया है। उतारे गये सामान और डाक का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 51.53/65।]**

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एयरलाइनों को तुरंत यह सलाह दी गयी कि वे स्वयं अपने ही हित में कराची से होकर आने वाली अपनी सेवाओं में भारत के लिए लाया जाने वाला कोई भी सामान और डाक न ले जायें।

उप-चुनाव

*262. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट :**

श्री जसवन्त मेहता :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण की दृष्टि से स्थगित किये गये विभिन्न राज्य विधान-मण्डलों तथा लोकसभा के उप-चुनाओं को कराने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब इन चुनावों के कब होने की संभावना है?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। सरकार ने विभिन्न राज्य विधान मंडलों और लोक सभा के लिए उन उप-निर्वाचनों को कराने के मामले में कोई निश्चय नहीं किया है जो पाकिस्तानी आक्रमण के कारण स्थगित कर दिये गये थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Control on Sugar

*263. **Shri Basumatari :** **Shri Kapur Singh :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Bishwanath Roy :**
Shri Heda : **Shri Himatsingka :**
Shri C. K. Bhattacharyya : **Shri Rameshwar Tantia :**

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the production of sugar has gone up during 1964-65;

(b) if so, to what extent;

(c) whether Government propose to lift the control on sugar; and

(d) the steps taken by Government to promote its exports?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) From 25·69 lakh tonnes in 1963-64 to 32·60 lakh tonnes in 1964-65.

(c) No, Sir.

(d) Exports of sugar are being stepped up from 2·15 lakh tonnes proposed earlier to 3 lakh tonnes in 1965-66.

निर्वाचन व्यय

*264. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यय को कम करने के तरीकों का अध्ययन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस के आधार पर सरकार का क्या निर्णय है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां। निर्वाचन व्यय कम करने का प्रश्न निर्वाचन आयोग के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

सेतुसमुद्रम् परियोजना

*265. **श्री मुथिया :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की तकनीकी समिति ने सेतुसमुद्रम् परियोजना के आर्थिक तथा नौ-परिवहन सम्बन्धी पहलुओं पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी पहलू पर भी विचार किया गया है;

(ग) क्या नहर के लिये स्थान के चुनाव के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) क्या चौथी योजना में यह परियोजना क्रियान्वित की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) : सेतुसमुद्रम् परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यनिर्धारण करने के लिये फरवरी 1965 में एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति की पहली बैठक में यह निश्चय किया गया था कि परियोजना का वास्तविक प्राक्कलन करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण, समुद्र और तट पर ट्रायल बोरिंग, अनरेखक अध्ययन इत्यादि करना आवश्यक है। उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित पूरे समय के लिये एक मुख्य इंजीनियर और एक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। अलग से एक इंजीनियरी परिमंडल भी स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न सर्वेक्षण करने के अलावा ये अधिकारी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वित होने की पद्धतियों का और जरूरी मशीनों के प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगायेंगे।

उपरोक्त अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद परियोजना के मुख्य इंजीनियर रिपोर्ट और परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करेंगे। इसमें कुछ समय लगेगा।

जहां तक परियोजना के आर्थिक पहलू का संबंध है यह बहुत कुछ होने वाले उद्व्यय पर और नहर को व्यवहृत करने वाले जहाज किस सीमा तक देयता सहन कर सकते है, निर्भर करता है।

अभी तक रक्षा मंत्रालय ने परियोजना के बारे में प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूछ ताछ नहीं की है।

नहर के लिये स्थिति निश्चयन के बारे में ठीक संरेखण मौजूदा तकनीकी जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर मालूम हो सकेगा।

अतएव संविस्तृत परियोजना प्राक्कलन, जो तैयार किये जा रहेहैं, प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजना पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

मूंगफली के मूल्य

*266. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

General Elections

*267. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Maurya :
Shri P. C. Borooah :
Shri D. C. Sharma :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vasudevan Nair :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Kapur Singh :
Shri H. N. Mukerjee :
Shri R. S. Pandey :
Shri D. D. Puri :
Shri Kajrolkar :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the 'Patriot' dated the 12th October, 1965 that Government propose to hold the General Elections in the middle of the next year;

(b) if so, how far that news is correct; and

(c) the reasons for doing so?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is no proposal under consideration of Government to hold the next General Elections before the scheduled time.

उर्वरकों का संभरण

629. **श्री कोल्ला वेंकैय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 के पूर्वार्ध में राज्यों के लिये नियत रासायनिक उर्वरकों की अवशिष्ट मात्रा उन्हें सितम्बर, 1965 की समाप्ति से पहले दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष सितम्बर, 1965 की समाप्ति तक विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में खाद दी गई;

(ग) 1965-66 की तीसरी तिमाही के लिए विभिन्न राज्यों का कितना अभ्यंश आवंटित किया गया है;

(घ) तीसरी तिमाही में अभ्यंश में से कितनी मात्रा में उर्वरक दिये गये हैं; और

(ङ) यदि किसी राज्य को संभरण नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) : अप्रैल से सितम्बर, 1965 तक और 1965-66 की तीसरी तिमाही के लिये राज्य सरकारों को दिये गये रासायनिक उर्वरक की मात्रा और तीस सितम्बर, 1965 तक तथा अक्टूबर 1965 के दौरान दी गई मात्रा का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण संभापटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5154/65]**

(ङ) कमी के मुख्य कारण उस प्रकार हैं :—

(1) अमरीका में नाविकों (लांग शोर मैन) की हड़ताल जिसकी वजह से अमोनिया सलफेट देर से पहुंचा।

(2) दुनिया में उर्वरकों की कमी के कारण वर्ष के पहले भाग में पर्याप्त संभरण की व्यवस्था सम्भव नहीं थी।

(3) बिजली में कटौती किये जाने के कारण फर्टलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर में उत्पादन में कमी हुई।

(4) हीराकुड से बिजली और कोक ओवन गैस के अपर्याप्त सम्भरण के कारण रुड़केला में भी उत्पादन कम हुआ।

(5) अनाज के काफी आयात के कारण बन्दरगाहों में भीड़ की वजह से माल उतारने के काम में देर हुई।

(6) बन्दरगाहों और कारखानों के लिये माल डिब्बों की सप्लाई में समय समय पर कमी और सड़क से उर्वरक ले जाने की रियायत का पूरा पूरा फायदा उठाने के मामले में राज्य सरकारों की कठिनाइयां।

केरल में छोटे पत्तन

630. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कालीकट, बेपुर, बड़ाकरा और बलीपट्टम के छोटे पत्तनों के विकास के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या योजनाकाल समाप्त होने से पहले सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय आयोजना के केन्द्रीय क्षेत्र में कालीकट और बेपुर पत्तनों के लिए निम्न राशियां निर्धारित की गयी है :—

कालीकट	10 लाख रुपये
बेपुर . . .	20 लाख रुपये

बाडागारा या कालीपट्टम पत्तनों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

चूंकि छोटे पत्तन राज्य सरकारों के कार्यकारी नियंत्रण में है अत: योजनाओं को कार्यान्वित करने में व्यय की प्रगति मुख्यत: राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। ज्ञात हुआ है कि कालीकट और बेपुर पत्तनों के सुधारने के काम का एक भाग तीसरी आयोजना के अन्त तक पूरा हो जाएगा और शेष कार्य जारी रहेगा।

केरल में अन्तर्देशीय जलमार्ग

631. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने केरल में अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिये कितनी रकम निर्धारित की है;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या योजनाकाल समाप्त होने तक शेष राशि खर्च हो जायेगी;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय परिव्यय के अन्तर्गत आने वाली योजनायें मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और

(ङ) क्या-क्या महत्वपूर्ण योजनायें इसमें शामिल की गई हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) केरल राज्य में अन्तर्देशी जल परिवहन की योजनाओं के लिये केन्द्रीय तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ख) मार्च 1965 तक राज्य सरकार द्वारा 30.07 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

(ग) सम्भवत: राज्य सरकार तीसरी योजना अवधि के अन्त तक शेष राशि का अधिकांश भाग खर्च कर देगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना में सन्निहित कुछ महत्वपूर्ण योजनायें ये हैं : बादागारामाही नहर का निर्माण; इलाथुर कल्लाई और चावेरा नहरों में सुधार ।

केरल के लिये चावल का सम्भरण

632. **श्री अ० क० गोपालन** क्या : **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल को ग्यारह लाख टन चावल देने का आश्वासन दिया है जबकि पिछले वर्ष 9 1/2 लाख टन चावल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितना चावल दिया जा चुका है;

(ग) शेष चावल कब दिया जायेगा;

(घ) इसमें से कितना चावल मद्रास से दिया जायेगा; और

(ङ) कितना चावल आन्ध्र प्रदेश से दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ङ) : केन्द्रीय सरकार ने केरल को आश्वासन दिया है कि उनकी अनौपचारिक राशन व्यवस्था की सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी । किसी भी स्रोत विशेष से सप्लाई करने के लिये कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गयी है । अक्तूबर के अन्त तक केरल को 7.74 लाख मीट्रिक टन चावल दिया जा चुका है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदीम जातियों का कल्याण

633. **श्री सिद्धया** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1965 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा करने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। ऐसा एक प्रस्ताव है, परन्तु राष्ट्रीय आपातकाल के कारण सम्मेलन की तिथी निश्चित नहीं की गई है।

(ख) सामान्यतः पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अब तक अपनाई गई नीतियां तथा कार्यक्रम तथा भविष्य में अपनाई गई नीतियों तथा कार्यक्रमों पर चर्चा की जायेगी।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति

634. **श्री सिद्दय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने अब तक किन-किन राज्यों का दौरा किया है;

(ख) क्या समिति की प्रश्नावलियां राज्यों की सभी प्रादेशिक भाषाओं में छपवा ली गयी थीं और समिति द्वारा राज्यों का दौरा करने से पहले राज्यों को भेज दी गयी थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) महाराष्ट्र राज्य तथा दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र।

(ख) समिति व्दारा जारी की गई सामान्य प्रश्नावलि का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है तथा उसकी साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां समिति के राज्य का दौरा करने के पहले उस राज्य में वितरित कर दी गई है।

हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

635. **श्री सिद्दया** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा 1 मई, 1965 को की गई सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड ने 1 मई, 1965 की हुई अपनी बैठक में जो सिफारिशें की थीं उनको संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को लागू करने के लिये भेज दिया गया है। इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है।

अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956

636. **श्री राम हरख यादव** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को गुप्त रूप से उक्त प्रोग्राम तथा वैधानिक उपबन्धों के प्रभावी परिणामों के प्रति होने वाले कुकृत्य को रोकने के लिए कार्यवाही करने की सलाह दी है; और

(ग) क्या इस मूल्यांकन के फलस्वरूप इस अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट सलाह नहीं दी गई है। परन्तु अधिनियम को लागू करने के दौरान वर्तमान कुकृत्यों को रोखने के लिए कार्यवाही करने की आशा है।

(ग) यद्यपि कोई अनुमान नहीं लगाया है परन्तु अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

अखिल भारतीय बंजारा सेवक संघ

637. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बंजारा सेवक संघ की मांगों के बारे में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : इस संघकी मांग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची बदलने के बारे में हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में परिवर्तन करने वाली सलाहकार समिति में की गई सिफारिशों के आधार पर इसपर विचार किया जा रहा है।

अनाज व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे

638. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में 1 अप्रैल, 1965 से अब तक अत्यावश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत जमाखोरों, चोर-बाज़ारियों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कितने मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में दोष-सिद्ध हुआ है; और

(ग) प्रत्येक मामले में किस प्रकार की तथा कितनी सज़ा दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : भाग (क) तथा (ख) के बारे में उपलब्ध जानकारी देनेवाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखीये संख्या एल० टी०-5155/65/]** भाग (ग) तथा अन्य दोनों भागों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पशुधन का बीमा

639. **श्री सिद्देश्वर प्रसाद :**
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुधन के बीमे के प्रश्न का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन से क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञों की यह राय है कि ऐच्छिक पशु बीमा को प्राथमिक आधार पर चालू किया जा सकता है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में पशु बीमा लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

किसानों को ऋण

640. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों को धन देने की व्यवस्था की गई थी ताकि वे उपान्त एवं उपान्त से नीचे के किसानों, भूमिहीन किसानों आदि को उनकी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर पर्याप्त ऋण दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था का कहां तक उपयोग किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की विशेष अप्राप्य ऋण आरक्षित निधियों के लिये सीधे अनुदान मंजूर किए हैं, ताकि उन्हें उपान्त एवं उपान्त से नीचे के किसानों, भूमिहीन किसानों आदि को उनकी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर पर्याप्त ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य सरकारों को इन अनुदानों के 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इस बात की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है कि कहां तक सीधे अनुदान की योजना ने उस उद्देश्य को प्राप्त किया है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की शीघ्र ही मिलने की आशा है।

व्यापारिक फसलों की खेती

641. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल सिंचित भूमि में से राज्यवार कितने प्रतिशत भूमि पर क्रमशः 1 अप्रैल, 1950 तथा 1 अप्रैल, 1965 को गेहूं, चावल, गन्ना, कपास तथा तिलहन की खेती हो रही थी;

(ख) सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि पर अनाज की खेती करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सिंचाई वाले क्षेत्रों में व्यापारिक फसलों की खेती के लोकप्रिय होने के यदि कोई कारण हैं, तो क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) गेहूं, चावल, गन्ना, कपास तथा तिलहनों के सिंचाई वाले क्षेत्रों तथा 1949-50 तथा 1962-63 में सिंचाई वाले क्षेत्र की प्रतिशतता दिखाने वाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखीये संख्या एल० टी०-5156/65।]** 1962-63 के बाद के वर्षों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि चुने हुए सिंचाई वाले इलाकों के अतिरिक्त और फसल बोयें। ऐसी नई सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुछ ज़मीन में खेती करने के लिये जमीन को तैयार किया जाये। उठाऊ सिंचाई के प्राप्त पानीको उठाने के लिए बिजली तथा डीज़ल के पम्पों का इस्तेमाल किया जाये जिससे रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसल का क्षेत्रफल बहुत बढ़ाया जाये। अधिक अनाज देने वाली धान तथा गेहूं (ताइचुंग नेटिव-1, सोनारा-64 तथा लारमा टोजो) तथा वर्ण संकर मक्का, ज्वार तथा बाजरा अदि की खेती बढाना।

(ग) सिंचाईवाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक फसलों तथा अन्य ऐसी ही फसलों की खेती में दिलचस्पी मुख्यतः इस कारण से है कि इसके लिए पानी सामान्यतया ठीक प्रकार से मिलता रहता है तथा उर्वरक बीज आदि में जो कुछ उनका धन लगता है वह उनको काफी वापस मिल जाता है। इन कारणों से तथा क्योंकि इनके मूल्य भी अच्छे मिलते है, सभी किसान सिंचाई वाले क्षेत्रों में उनकी खेती करते हैं।

समाज सेवा के लिये महिला स्वयंसेवक दल

642. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज सेवा के लिये आपात काल में एक देशव्यापी महिला स्वयंसेवक दल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी इस समय सदस्य संख्या क्या है; और

(ग) इस संगठन ने क्या-क्या काम हाथ में लिये है अथवा निकट भविष्य में करने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं। परन्तु केन्द्रीय नागरिक परिषद ने आखिल भारतीय आधार पर 'महिला ऐच्छिक सेवा' नामक एक संगठन बनाने का निर्णय किया है।

(ख) महिला ऐच्छिक सेवा अभी बनाई गई है परन्तु इसकी अभी सदस्य संख्या अधिक नहीं है।

(ग) प्रस्तावित कार्यकलापों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

'महिला' स्वयंसेवक सेवा के सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे (युद्ध के दिनों में)

1. **चिकित्सा** : फर्स्ट एड, सहायक नर्सिंग, अटैन्डैन्ट, नर्सिंग आदि,
2. **संचारन** : टेलिफोन तथा वायरलेस आपरेर
3. **परिवहन** : मोटर तथा एम्बुलैन्स ड्राइवर
4. **कल्याण तथा सुविधायें** : अनुरोध करने पर विस्थापित व्यक्तियों तथा सैनिकों के लिए कल्याण तथा सुविधाओं की व्यवस्था
5. **कैंटीन** : सैनिकों के लिए चल तथा अचल तथा खाद्यान्नों का अभिकरण
6. निष्क्रमणार्थियों के लिए आपातकालीन कार्य
7. विश्राम गृह तथा अवकाश शिबिर सैनिकों, तथा अन्य लोगों के परिवारों के लिए
8. **शिक्षा** : अफवाहों आदि को रोकने के लिए
9. सैनिकों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम
10. घरेलू बागबानी तथा मुर्गीपालन आदि को प्रोत्साहित करना
11. सिनैलिंग वाच एण्डवार्ड, यातायात नियंत्रण आदि
12. सिविल डिफैंस प्राधिकारियों के लिए आमंत्रित कार्य जैसे फायर फायटिंग, सतर्कता आदि शांतिकाल में 'महिला' [स्वयंसेवक सेवा, महिला ऐच्छिक ब्यूरो के रूप में काम करेगी तथा जहां आवश्यक होगा स्वयंसेवक भेजेगी।

पर्वतीय क्षेत्र तथा कमी वाले क्षेत्र

643. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा कमी वाले क्षेत्रों के विकास के लिये अब तक कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) ऐसे क्षेत्र कहां कहां पर अधिक हैं; और

(ग) क्या राज्यों से कहा गया है कि वे चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये ऐसे क्षेत्रों के विकास की योजनाएं भेजे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तीसरी योजनावधि में पर्वतीय क्षेत्रों तथा कमीवाले क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के अलग शीर्ष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों तथा कमीवाले क्षेत्रों (संभवतया सूखे वाले क्षेत्र) निम्नलिखित राज्यों में अधिक हैं :

पर्वतीय क्षेत्र

जम्मू तथा काश्मीर, नेफा, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, मद्रास तथा पश्चिम बंगाल ।

कमीवाले क्षेत्र

आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तथा मैसूर ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनायें। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाने के लिये विभिन्न मंत्रालयों में कई कार्यकारी दल बनाये गये हैं। इन दलों के काम का समन्वय करने के लिए योजना आयोग ने एक स्टीयरिंग समिति बनाई गई है ।

कृषि विश्वविद्यालय

644. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कर दिये गये हैं;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) किन-किन राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके लिये कितनी राशि नियत की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): दूसरी योजनावधि में उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय के लिए 190 लाख रुपये से अनधिक अनावर्त्तक व्यय स्वीकार किया गया था । तीसरी योजनावधि में सात और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। जिन राज्यों में ये विश्वविद्यालय स्थापित हैं तथा जिनको केन्द्र सरकार ने अनुदान दिए हैं, के बारे में निचे बताया गया है :—

राज्य	स्वीकृत अनुदान रुपये
1. पंजाब	25,00,000
2. उडीसा	15,54,279
3. राजस्थान	15,38,000
4. आंध्र प्रदेश	11,39,540
5. मध्य प्रदेश	98,800
6. पश्चिम बंगाल	5,00,000
7. मैसूर	कोई नहीं

(घ) जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम

645. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा करवाये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम अभी ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों के पोषाहार स्तर को उत्तम तथा ऊंचा बनाने में अभी तक सफल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख): व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का नवीनतम सर्वेक्षण योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने किया है, जिन्होंने आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यों, जहां कि यह कार्यक्रम, पर्याप्त अर्से से चल रहा है, में 1964 के अन्त में द्रुत रूप से वर्तमान मूल्यांकन किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से शैक्षणिक है, तथापि इसके अन्तर्गत चुने हुए खण्डों और ग्रामों में जरूरतमंद वर्गों के लिए अनुपूरक भोजन की भी व्यवस्था है। पोषाहार शिक्षा के बारे में सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस कार्यक्रम की अवधि में पोषाहार सम्बन्धी चेतना तथा ज्ञान में सुधार हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि अनुपूरक भोजन के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा में संतोषजनक प्रगति हुई है; यद्यपि उत्तर प्रदेश में भोजन मुख्य रूप से दूध के वितरण तक ही सीमित है।

(ग) जैसी कि कार्यक्रम मूल्यांकन संघटन की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई है--अर्जित अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार करने के अन्य प्रशासनिक और संगठनात्मक उपायों के अतिरिक्त, अब इस कार्यक्रम को पहले की तरह कार्यान्वित न करके चौथी योजना में नियमित योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जिसके लिए राज्य स्तर पर समन्वित बजट बनाए जाएंगे।

चावल का आयात

646. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री कपूर सिंह :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अगस्त, 1965 को पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर आक्रमण किये जाने के बाद भारत ने विदेशों से अब तक कुल कितना चावल खरीदा है; और

(ख) प्रत्येक देश से कितना-कितना चावल खरीदा गया है और कितना मूल्य दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : 5 अगस्त, 1965 से अब तक थाईलेंड से 53,500 मीट्रिक टन चावल खरीदने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और संयुक्त अरब गणराज्य से 3,700 मीट्रिक टन चावल आयात करने के लिये एक सौदा पूरा हुआ है। यह बताना जनहित में नहीं होगा कि थाईलेंड और संयुक्त अरब गणराज्य से किस भाव पर चावल खरीदा गया है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

647. **श्री सिद्दय्या :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने वर्ष 1962-63 के प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण संसद् के चालू सत्र में सभा पटल पर रखा जायगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : सामान्यतया अगले वर्ष के प्रतिवेदन पर सभा में विषय उठाये जाने से पहले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जानेवाली कार्यवाही का उस वर्ष का विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है ।

हमने 1962-63 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों समेत अपेक्षित जानकारी विभिन्न अधिकारियों से मांगी गई है तथा इस प्रतिवेदन पर की गई अथवा की जानेवाली कार्यवाही का विवरण उचित समय पर सभा के समक्ष पेश किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के सम्बन्ध में गोष्ठी

648. **श्री सिद्दय्या :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जनवरी, 1964 में हुई अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के संबंध में हुई गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने क्रियान्वित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : इस बारे में स्थिति सभा पटल पर रखे गये विवरण में निदर्शित की गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5157/65।]**

चीनी कारखाने

649. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्यवार कितने चीनी के कारखाने हैं;

(ख) चीनी के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी चीनी चाहिए; और

(ग) विदेशों को निर्यात करने के लिए चीनी का पर्याप्त उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1964-65 के क्रशिंग मौसम में विभिन्न राज्यों में 198 चीनी के निम्नलिखित कारखाने चालू थे :—

क्रम संख्या	राज्य	चालू कारखाने
1.	उत्तर प्रदेश	72
2.	बिहार	29
3.	पंजाब	8

क्रम संख्या	राज्य	चालू कारखाने
4.	पश्चिम बंगाल	1
5.	आसाम	1
6.	राजस्थान	2
7.	मध्य प्रदेश	5
8.	उड़ीसा	2
9.	महाराष्ट्र	32
10.	गुजरात	3
11.	मद्रास	12
12.	मैसूर	8
13.	पांडीचेरी	1
14.	आन्ध्र प्रदेश	19
15.	केरल	3
	जोड़	198

(ख) और (ग): तीसरी योजना के लिए देश के खपत तथा निर्यात की आवश्यकताओं के लिए चीनी के लक्ष्य 35.6 लाख मीट्रिक टन निश्चित किए गए थे। संभावना है कि देश में खपत तथा निर्यात की आवश्यकताओं के लिए चौथी योजना के लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निश्चित किये जायेंगे। अतिरिक्त चीनी उत्पादन क्षमता का लाइसेंस दिया जा रहा है तथा चीनी उत्पादन के लक्ष्य पूरे करने के लिए गन्ना विकास कार्य किए जा रहे हैं।

नारियल जटा कारखानों के मजदूर

650. **श्री उमानाथ** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नारियल जटा बोर्ड ने उन नारियल जटा कारखानों को, जिनमें तीन अथवा अधिक मजदूर कार्य करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर यह सिफारिश की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य आधार यह है कि जिन कोरे नारियल जटा कारखानों में 20 से कम व्यक्ति नौकर हैं उनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू किया जाये।

(ग) इस समय यह संभव नहीं है कि 20 से कम व्यक्ति जिन कारखानों में नौकर हैं उनमें अधिनियम लागू न हो। परन्तु अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है जिससे उद्योगों में प्रचलित वास्तविक स्थिति में ऐसे कारखानों में इसको लागू करने के प्रश्न को लिया जा सके।

खाद्य वस्तुओं में पोषक तत्व

651. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य वस्तुओं अर्थात् चावल आदि में पालिश करने के द्वारा तथा परिष्करण के द्वारा पोषक तत्वों के होने वाले नाश को रोकने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : धान कुट्टन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेन्स देना) नियम, 1959 के नियम 7 के अनुसार, (कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर) मिलों को चावल से पांच प्रतिशत से अधिक अथवा तीन प्रतिशत से कम भूसी उतारने के लिये मना किया गया है। राज्य सरकारों को हाल ही में यह सलाह दी गई है कि वे पालिश करने सम्बन्धी उपबन्ध ठीक तौर पर लागू करें और पालिश की डिग्री को चार प्रतिशत तक ही सीमित रखें ताकि पोषक तत्वों को होने वाली हानि कम से कम हो सके। सरकार ने हाल ही में आधुनिक ढंग की सात चावल मिलें खोली है जिनमें ऐसी अच्छी मशीनें लगी हुई है जिनसे बड़े अच्छे तरीके से चावल उबाला जा सकता है जो अधिक पौष्टिक होता है।

फलों, सब्जियों आदि जैसी अन्य खाद्य वस्तुओं के परिष्करण से पोषक तत्वों की अधिक हानि नहीं होती है। फल उत्पाद आदेश, 1955, जिसके नियमानुसार यह परिष्करण किया जाता है, उसमें पोषक तत्वों की सुरक्षा के लिये उचित व्यवस्था की गई है।

परिसीमन आयोग

652. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : परिसीमन आयोग ने पंजाब में संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा कर दिया है और अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 जुलाई, 1965 में प्रकाशित कर दी गई है इस अधिसूचना की एक प्रति 17 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर भी रखी गई थी।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है परिसीमन आयोग ने अपनी प्रस्थापनाओं के प्ररूप पर सहयोजित सदस्यों के साथ 7 से लेकर 14 अक्तूबर, 1965 तक, लखनऊ में चर्चा की। ये प्रस्थापनाएं जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही भारत के राजपत्र और राज्य राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी। आयोग इन आपत्तियों और सुझावों पर एक या अधिक सार्वजनिक बैठकों में विचार करेगा और तत्पश्चात आदेश को अन्तिम रूप देगा जो भारत के राजपत्र तथा राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आदेश की एक प्रति तब सभा पटल पर रखी जायेगी।

खाद्य पालीटेकनीक

653. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री कपूर सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 31 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित खाद्य पालीटेकनीक कब तक स्थापित होने की संभावना है तथा किन-किन स्थानों पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : वर्ष 1965-66 में प्रस्तावित खाद्य पालीटेकनिक स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। ये (1) लखनऊ (उत्तर प्रदेश), (2) कलमेसरी (केरल), (3) बंगलौर (मैसूर), (4) अहमदाबाद (गुजरात) और (5) पंजिम (गोआ) में स्थापित किये जाएंगे। केन्द्र सं० (1) पर शीघ्र ही पाठ्यक्रम शुरू होने की आशा है जब कि केन्द्र सं० (2) और (3) पर आगामी वर्ष के शुरू में आरम्भ हो सकते हैं। केन्द्र संख्या (4) और (5) के लिये भूमि अर्जन के बारे में बात-चीत चल रही है और भवन आदि तैयार होते ही पाठ्यक्रम शुरू कर दिये जाएंगे।

हैलीकाप्टर की दुर्घटना

654. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 31 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1186 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीरोजपुर जिले (पंजाब) के रव्योवाली गांव में कपास के खेतों में कीट-नाशक दवाई छिड़क रहे एक हैलीकाप्टर की जो दुर्घटना हुई थी क्या उस के कारणों के बारे में जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : दुर्घटना की अभी जांच की जा रही है।

मद्रास बन्दरगाह में विस्फोट

655. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 जून, 1965 को मद्रास बन्दरगाह में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : सरकार को अभी भी प्रतिवेदन नहीं मिला है।

ट्रैक्टरों का आयात

656. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 'अधिक अन्न उपजाने' के व्यापक अभियान के अन्तर्गत और अधिक भूमि में खेती करने के लिए बड़े अथवा छोटे ट्रैक्टरों का आयात करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन ट्रैक्टरों को आयात की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1964 में लखनऊ तथा हरदोई जिले में चसार भू-सुधार तथा भू-संरक्षण फार्मों में खेती करने के लिये अमरीका से तीन केटरपिलर डी-4 ट्रैक्टर आयात करने हेतु एक लाख पचास हजार रुपये की विदेशी मुद्रा की मांग थी।

ऐसा अनुमान लगाया गया था कि देश में बने पहियें वाले ट्रैक्टरों से यह काम चल सकता है। इस बात को तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह पचास एच० पी० के जेतर आदि उच्च अश्वशक्तियुक्त तथा पहिये वाले ट्रैक्टरों का प्रयोग करे।

राष्ट्रीय खाद्य नीति

657. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किन्दर लाल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 14 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य नीति पर विचार करने के लिए संसद के सब दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां। आपातकालीन खाद्य योजना के समाहार तथा वितरण पहलुओं पर विचार करने के लिये 6 नवम्बर, 1965 को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा संसद् के सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी थी। ऐसी ही एक अन्य बैठक खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा 9 नवम्बर, 1965 को बुलायी गई थी जिसमें आपातकालीन खाद्य योजना के उत्पादन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया था।

(ख) दोनों बैठकों का संक्षेप से मसौदा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5158/65।]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेनियल वाल्काट के भाग निकलने से सम्बन्धित जांच समिति का प्रतिवेदन

658. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री डेनियल वाल्काट के भाग निकलने से सम्बन्धित जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में 21 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन को चार्ज-शीट किया गया था, की गई अनुशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अभी चल रही हैं।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

659. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन** मंत्री दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में 14 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों का क्या परिणाम रहा, जो न्यायालयों में विचाराधीन थे तथा जिन की तहकीकात की जा रही थी ;

(ख) अवशिष्ट मामलों में कितने ड्राईवरों को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त थी;

(ग) क्या यह राजनयिक उन्मुक्ति केवल कुछ विदेशी दूतावासों के ड्राईवरों को ही प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो वे कौन से हैं; और

(ङ) इस का आधार क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) न्यायालय में विचाराधीन दिखाये गये पिछले तीन मामलों में से एक में गाड़ी के ड्राइवर का दोष सिद्ध हो गया है और उसपर 150 रुपये जुर्माना किया गया। शेष दो मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उन आठ मामलों में से जिन्हें पिछली बार जांच किये जाने के अन्तर्गत बताया गया था, 2 मामले नत्थी कर दिये गये क्योंकि उसकी कोई खोज नहीं की जा सकी। एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शेष पांच मामलों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

(ख) 21।

(ग) से (ङ): ग्राही राज्य के अपराधिक, गैर अपराधिक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से सविशेषाधिकार संस्थाओं के केवल सविशेषाधिकार व्यक्तियों ही को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है। यदि ड्राइवर ग्राही राज्य में राष्ट्रीय रिहायशी हो अर्थात भारतीय राष्ट्रिक हो तो उसे राजनयिक उन्मुक्ति नहीं मिलती है।

चने के दाम

660. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में चने के दामों में बहुत अन्तर है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पशुओं के चारे, जैसे ज्वार, के दामों में इतना अधिक अन्तर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो चने तथा ज्वार के दामों में इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पशुओं के चारे के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली ज्वार की खपत प्रायः उसी राज्य में हो जाती है जहां वह पैदा होती है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य में कम ही भेजी जाती है और इस लिये उसके मूल्यों में बहुत अन्तर होने की कम ही सम्भावना है। दूसरी ओर चना एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्यों के खाने के काम आता है और विभिन्न राज्यों में इस वस्तु के मूल्यों में अन्तर इस लिये होता है क्योंकि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में वह खपत से अधिक होता है और महाराष्ट्र, मद्रास आदि जैसे अन्य राज्यों में, जिनमें इसकी बहुत खपत होती है, वहां यह कम होता है। मूल्यों में अन्तर परिवहन लागत, परिवहन के साधन तथा सप्लाई और खपत वाले राज्यों के बीच फासला होने के कारण होता है। तथापि मूल्यों में अन्तर बहुत अधिक नहीं होता है क्योंकि खपत से अधिक पैदा करने वाले राज्यों से कम पैदा करने वाले राज्यों में चने की सप्लाई एक सरकार से दूसरी सरकार के माध्यम से की जाती है।

राजस्थान में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें

661. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सभी स्थानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्यों और इसके बारे में राजस्थान सरकार तथा जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। हाल के पाकिस्तानी हमले के दौरान इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को अपनी आई-सी-449/450 दिल्ली-आगरा-जयपुर-उदयपुर विमानसेवा को 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर, 1965 तक बन्द करना पड़ा। दूसरी आई-सी-123/124 बम्बई-अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली विमान सेवा निर्बाध रूप से चलती रही।

(ख) राजस्थान सरकार इस सेवा के बन्द होने से निःसन्देह चिन्तित थी जो कि अब फिर चालू कर दी गयी है।

सीमावर्ती सड़क विकास योजना

662. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से आसाम तक एक सीमावर्ती सड़क बनाने का कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : देश के उत्तरी सीमान्त के निकट क्षेत्रों की आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिय उत्तर प्रदेश में बरेली से आसाम में अमीनगांव तक एक आनुषंगिक सड़क का निर्माण भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया है।

2. मार्ग का संरेखण ऐसा होगा जो निम्न नगरों से गुजरेगा :—

बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, गोपालगंज, पीपर कोठी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पुरनिया, अरारिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, गलगलिया, सिलीगुड़ी, बाराडिगा, नगारकाटा, गोयरकाटा, डालगांव, मदारीहाट, हशीमारा, राजभटखवा, अलीपुर दुआर, भलका, नलबारी, रंगिया और अमीनगांव।

इस के अलावा निम्न चार सड़कें भी बनाई जायेगी :—

1. कसिया से पदरौना (उ०प्र०)
2. सगौली से बेटियाह (बिहार)
3. मुजफ्फरपुर से दरभंगा (बिहार) और
4. अरारिया से फारबेसगंज और मरीचा (बिहार)

3. पूरे मार्ग पर गाड़ी जाने की दोहरी गली होगी और वर्ग 70 बोझ ले जाने के पुल होंगे। अपने संबद्ध राज्य क्षेत्रों में संबद्ध राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का कार्य किया जा रहा है और इसकी सम्पूर्ण लागत की पूर्ति भारत सरकार करेगी।

केन्द्रीय पण्य समितियां

663. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय के अधीन नौ केन्द्रीय पण्य समितियों में से कितनी समितियां भंग कर दी गई हैं;

(ख) इन नौ समितियों में से कितनी समितियां (एक) अधिनियमों, (दो) संकल्पों तथा (तीन) अन्यथा स्थापित की गई थीं;

(ग) क्या भविष्य में प्रत्येक पण्य समिति के स्थान पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित विकास परिषदों में विधान-मण्डलों के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पांच।

(ख) इन नौ समितियां में से चार समितियां विधान मण्डल अधिनियमों तथा शेष पांच सरकारी संकल्पों के अन्तर्गत बनाई गई थीं।

(ग) और (घ) : स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित विकास परिषदों में विधानमण्डलों के सदस्यों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तथापि, यदि ये सदस्य उत्पादकों आदि के प्रतिनिधि के रूप में निकाय में नहीं लिये जाते हैं, तो ऐसे लोगों के हित का संरक्षण करने के लिये जिनका प्रतिविधान नहीं हुआ है, केन्द्रीय सरकार रक्षित शक्तियों के अन्तर्गत अतिरिक्त सदस्य नामज़द कर सकती है। फिरभी, प्रथम विकास परिषद् में विधान-मण्डलों के सदस्यभी सहित होंगे,। भूतपूर्व तथा वर्तमान पण्य समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को इस परिषद् के सदस्यों के रूप में ले लिया जायेगा।

ग्राम स्वयंसेवक दल

664. **श्री ब० कु० दास :**
श्री श्रीनारायण दास :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आपात काल के सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों में ग्राम स्वयंसेवक दल के संगठन, कार्य-करण तथा सदस्य-संख्या का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आपात काल में सक्रिय तथा प्रभावी कार्य के निमित्त उन्हें अच्छी तरह संगठित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे ग्राम स्वयंसेवक दल को बढाएं एवं मज़बूत करेंऔर इसके सदस्यों को स्थानीय रक्षा, जन-शिक्षा तथा उत्पादन के क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य सौंपे। समुचित प्रशिक्षण के तरीके, जिनमें हथियारों के प्रयोग में यथासंभव प्रशिक्षण भी शामिल है, भी सुझाए गए हैं।

Colourisation of Vanaspati

665. **Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made in the matter of colourisation of vanaspati;

(b) whether Government have been able to find out some suitable colour which can be mixed in vanaspati; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) The Committee of Experts appointed by the Government for intensifying the researches for finding a suitable colour for vanaspati has completed its work and submitted a report which is under examination.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

666. **श्री बासप्पा :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित नियम बनाये गये हैं; और

(ग) नियमों में क्या महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था होगी, जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी अनुसन्धान संस्थाओं पर, जिनमें केन्द्रीय पण्य समितियां भी सम्मिलित होंगी, नियंत्रण करेगी।

(ख) जी, हां। वे, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी संस्था द्वारा 24 सितम्बर, 1965 को हुई उनकी बैठक में स्वीकार कर लिये गये थे और उन्हें सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले दिन से लागू कर दिया जायेगा।

(ग) नियमों में ये महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं :

(एक) शासी निकाय का पुनर्गठन करना ताकि उसमें अधिकतर वैज्ञानिक और कृषि में रुचि लेने वाले अथवा कृषि का ज्ञान रखने वाले लोग हों;

(दो) सलाहकार निकाय और (क) कृषि अनुसन्धान; (ख) पशु विज्ञानों सम्बन्धी अनुसन्धान; (ग) कृषि शिक्षा; और (घ) कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यकीय तथा विपणन अनुसन्धान के लिए अलग से एक-एक अर्थात् चार समितिओं का गठन करना;

(तीन) ऐसे महानिदेशक की नियुक्ति करना जो पारंगत वैज्ञानिक हो; और

(चार) परिषद् द्वारा अपने सचिवालय, अनुसन्धान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना तथा देखभाल करना।

"सी आइलैंड" कपास

667. **श्री बासप्पा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में "सी आइलैन्ड" कपास की खेती कितने क्षेत्र में होती है;

(ख) प्रत्येक वर्ष कपास का कितना उत्पादन होता है; और

(ग) क्या और अधिक क्षेत्र में इस की खेती होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) 1963-64 और 1964-65 में मैसूर राज्य में "सी आइलैण्ड कपास" की क्रमशः 3,096 हेक्टेअर्स और 2,964 हेक्टेअर्स भूमि पर खेती हुई ।

(ख) 1963-64 और 1964-65 में क्रमशः 1432 और 1544 गांठों का उत्पादन हुआ ।

(ग) राज्य में और अधिक भूमि पर इसकी खेती करने के लिये प्रयास किया जा रहा है ।

मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ

668. **श्री बासप्पा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि बंगलौर-मैसूर-मरकारा-मंगलौर सड़क और बंगलौर-मैसूर-ऊटकमंड सड़क को राष्ट्रीय राजपथों में शामिल कर लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : बंगलौर-मैसूर-उटकमंड सड़क को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग घोषित करने के लिए मैसूर सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । किन्तु उस राज्य सरकार ने कुछ समय पहले बंगलौर-मैसूर-मरकारा-मंगलौर सड़क को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग तंत्र में शामिल करने का सुझाव दिया था । इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं था क्योंकि मौजूदा राष्ट्रीय मुख्यमार्ग तंत्र के विस्तार के लिए फिलहाल धन उपलब्ध नहीं है ।

अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की सड़कें

669. **श्री बासप्पा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को अन्तर्राज्य और आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिये कार्यक्रम तैयार करने की मंत्रणा दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी नहीं । तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, सन, 1960 में राज्य-स्तर की राज्य सड़कों के विकास और आर्थिक महत्व के लिये राज्य सरकारों से केन्द्रीय सहायता पाने के विचारार्थ प्रस्ताव मांगे गये थे । इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य सरकार ने भी 4.37 करोड़ रुपये की लागत का एक कार्यक्रम भेजा है जिसको बाद में उन्होंने संशोधित कर 1.57 करोड़ रुपये लागत का किया । इस संशोधित कार्यक्रम का विस्तृत विवरण संलग्न है ।

कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
1. चितापुर से यादगीर तक एक सड़क का निर्माण . .	28.00 लाख रुपये
2. भाग सोलंपेट से कुरीकोटे पर चिनचोली से गुमर्ग तक सड़क निर्माण	28.00 ,,
3. मौलूरघाट होते हुये (40 मील) श्रिंगेरी से कारकल्ला तक सड़क का निर्माण	30.00 ,,
4. कोलेगाल तालुक (21 मील) में चोदाहाली से लालावेटा तक सड़क का सुधार करना	19.00 ,,
5. मंगलौर वाजपायी सड़क में मारवूर के निकट गुरुपुर नदी के ऊपर पुल का निर्माण	11.07 ,,
6. जिला बीजापुर में कोलापुर के निकट कृष्णा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण	40.00 ,,
कुल योग .	156.95 लाख रुपये

संलग्न विवरण में दिये गये कामों में भारत सरकार ने राज्य सरकार को कोलार पर कृष्णा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल के निर्माण पर प्रारंभिक खोज की कीमत को पूरा करने के लिये धन देना मंजूर कर लिया है। इस के निर्माण के सवाल पर चतुर्थ योजना में विचार किया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार को सूचित भी किया है कि मालाघाट होते हुये श्रिंगेरी से कारकला सड़क पर निर्माण कार्य के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता देने में कोई आपत्ति नहीं है। आर्थिक कठिनाइयों और आपत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता के कारण दूसरे कामों के लिये आर्थिक सहायता देना संभव न हो सका।

Scarcity of Rice in Delhi

670. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that good quality of rice is not available in open market in Delhi;

(b) whether it is also a fact that traders are reluctant to bring out their stocks in the market because of the fact that market price is low; and

(c) the steps being taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कैरावील विमान के फ्यूल पम्प

671. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

श्री अ० ना० विद्यालंकार :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राल्स रायस कम्पनी के विशेषज्ञों ने कैरावील विमानों के फ्यूल पम्पों के खराब हो जाने के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : अगस्त, 1965 के माह के दौरान कारवेल विमानों के ईंधन पम्पों के खराबी के कारण काम न करने के कारणों की जांच से यह पता चला है कि पम्पों में खराबी उनकी सिल्वर प्लेटेड सतह पर जंग लग जाने के कारण आयी थी। यह जंग दूषित ईंधन इस्तेमाल करने की वजह से लगा था।

कृषि योजनायें

672. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा अन्य मोटे अनाजों जैसे महत्वपूर्ण खाद्यान्नों की फसलों के लिए अखिल भारतीय आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बहुत सी समन्वित योजनाओं की जोरदार क्रियान्विति के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अनुसन्धान सम्बन्धी समन्वित योजनाओं की मांग स्वीकार कर ली है।

(ग) चावल और मक्का से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित योजनायें पहले ही काम कर रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण फसलों से सम्बन्धित समान योजनाओं को चौथी पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष में लिये जाने की सम्भावना है।

विमान परिचारिकाओं के रूप में चैकोस्लोवाकिया की बालायें

673. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने चैकोस्लोवाकिया की बालाओं को विमान परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी, हां। एयर इण्डिया की उड़ाने प्रेग को लन्दन होते हुए न्यूयार्क से जोड़ती हैं। न्यूयार्क और प्रेग के बीच काफी चेक यात्री आते जाते हैं, जिनमें से अधिकांश यात्री केवल चेक भाषा बोलते हैं। अपनी उड़ानों पर इस प्रकार के यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि वे चेक भाषा बोलने वाली विमान परिचारिकाएं नियुक्त करे।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

674. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों का प्रभावी कार्य-संचालन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या क्या निर्णय किये गये;

(ग) उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिये किस प्रकार की पर्याप्त ऋण सुविधायें प्रदान की गई हैं ताकि वे बाजार के लेन-देन में अधिक भाग ले सकें और मूल्यों में स्थिरता लाने में योग दे सकें;

(घ) क्या निकट भविष्य में और अधिक उपभोक्ता थोक भण्डार खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक उनके खोले जाने की संभावना है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को पर्याप्त सरकारी समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि वे आम जनता को अत्यावश्यक पदार्थ निर्बाध रूप से सुलभ करते रहें और कीमतें कम कर सकें।

(ग) यह निर्णय किया गया था कि भारत सरकार थोक उपभोक्ता भण्डारों द्वारा ली गई समस्त बैंक पेशगियों के 25 प्रतिशत की गारंटी देगी। यह महसूस किया गया था कि इस गारन्टी से भण्डार बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए बैंकों से पर्याप्त ऋण तथा पेशगियां ले सकेंगे।

(घ) और (ङ) : चौथी योजना अवधि में नए थोक भण्डार स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

तेपिओका की खेती

675. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक क्षेत्र में तेपिओका की खेती किये जाने की संभाव्यताओं के सम्बन्ध में पूर्ण खोज तथा जांच कर ली है;

(ख) 1961 से 1965 तक के वर्षों में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) किन किन राज्यों में तेपिओका की खेती करने के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं तथा किन किन राज्यों में अच्छे परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या गेहूं और चावल के पोषक तत्वों की तुलना में तेपिओका में विद्यमान पोषक तत्वों की जांच करने के लिए कोई वैज्ञानिक अन्वेषण किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे "आपातकालीन खाद्योत्पादन आन्दोलन" के अन्तर्गत तेपिओका की खेती करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अधिक उर्वरक डाल कर इसका उत्पादन बढ़ायें।

(ख) 1960-61, 1961-62 और 1963-64 में तेपिओका के उत्पादन में कोई वृद्धि नही हुई। पिछले वर्षों की तुलना में 1963-64 के उत्पादन में दस लाख तेरह हजार टन की वृद्धि हुई। 1964-65 के आंकड़े अभी उपलब्ध नही हुए हैं।

(ग) तेपिओका की खेती पहाड़ी इलाकों तथा हिमालय के निचले हिस्सो को छोड़कर लगभग भारत के सभी इलाकों में हो सकती है। तेपिओका की खेती करने के लिये उड़ीसा में दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में एक प्रयोगात्मक केन्द्र खोलने का विचार है।

(घ) जी, हां। तेपिओका की उष्मीय अर्हा गेहूं और चावल से कुछ कम होती है परन्तु गेहूं और चावल की तुलना में इस में प्रोटीन बहुत कम होता है। तथापि, तेपिओका में विटामिन सी काफी होता है जो चावल और गेहूं में विशेषकर नही होता। मैसूर में केन्द्रीय औद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, तथा खाद्य विभाग में विस्तार से किये गये विस्तृत परीक्षण से पता चलता है कि 75 प्रतिशत गेहूं का आटा, 17 प्रतिशत तेपिओका और 4 प्रतिशत खानेवाला मूंगफली का आटा मिलाने से जो आटा बनता है वह गेहूं के आटे की तुलना में पौष्टिक होता है।

विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

676. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए बनाई गयी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या तकनीकी कर्मचारियों का कोई केन्द्रीय पुंज बनाया गया है, जो सघन कृषि क्षेत्रों के बारे में योजना बनाने, संगठन करने तथा शीघ्रता लाने में राज्यों की सहायता करेगा;

(घ) यदि हां, तो कहां पर तथा किन राज्यों में; और

(ङ) इस समिति ने प्रशिक्षण में किस प्रकार से सुधार किया है, ताकि वह साधारण किसान के लिये वास्तविक रूप से लाभदायक हो सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिये राष्ट्रीय समिति द्वारा यह योजना कार्यान्वित की गई है :—

(एक) राज्य तथा जिला स्तर की विस्तार प्रशिक्षण समितियां स्थापित करना।

(दो) सघन कृषि क्षेत्रों के राज्य/जिला स्तर के विशेषज्ञों तथा प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन तथा वर्कशापों का संगठन करना।

(तीन) प्रत्येक सघन कृषि क्षेत्र जिलों तथा समूचे राज्य के लिये विभिन्न अवस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना तथा विशेषज्ञों द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना।

(चार) विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न फसलों के लिये "पैकेजेस आफ प्रैक्टिसेस" का पुनर्विलोकन करना।

(पांच) विस्तार कार्यकर्ताओं (एक्सटेन्शन वर्कर्स) तथा कृषकों के लिये विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आरम्भ करने के लिये प्रशिक्षण तथा पाठन सहायता प्रदान करना।

(ग) और (घ) : इसने तकनीकी कर्मचारियों का कोई केन्द्रीय पुंज नहीं बनाया है, जो सघन कृषि क्षेत्रों के बारे में योजना बनाने, संगठन करने तथा शीघ्रता लाने में राज्यों की सहायता करेगा। तथापि इसके प्रत्येक राज्य के लिये सम्पर्क दल तथा विभिन्न फ़सलों के "पैकेज आफ प्रैक्टिसेस" से सम्बन्ध रखने के लिये विभिन्न उपसमितियां तथा उपदल हैं।

(ङ) प्रशिक्षण सिद्धान्त रूप से देने के बजाय व्यावहारिक ढंग से देने के लिये बल दिया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये एक्सटेंशन वर्कर्स के प्रशिक्षण में सुधार करने तथा जिला और ब्लाक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रशिक्षण में सुधार हुआ है। जहां व्यावहारिक रूप से प्रदर्श तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है वहां किसानों के प्रशिक्षण में सुधार हुआ है।

विधि स्नातक

677. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विधि स्नातकों ने ऐडवोकेट अधिनियम, 1964 को लागू किये जाने का विरोध किया है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालयों में ऐडवोकेट के रूप में वकालत करने के लिये पात्र बनने से पहले उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। किन्तु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि जिन विधि स्नातकों ने अपनी परीक्षा 1965 में पास की है उनको राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा विहित कोई प्रशिक्षण लेने और परीक्षा पास करने से छूट दी जानी चाहिए।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है और भारत की विधिज्ञ परिषद् से परामर्श किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति

678. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति के बारे में लखनऊ में अक्तूबर, 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) भावी खाद्य नीति और कानपुर से शुरूआत करके महत्वपूर्ण शहरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने के बारे में करार हो गया है।

Civil Vehicles to meet Defence Requirements

679. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether the present arrangements of requisitioning services of civil vehicles to meet defence requirements during the emergency have proved adequate; and

(b) whether Government propose to bring forward any legislation in this regard?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes.

(b) No.

डकोटा विमानों का बदलाव

680. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 14 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अनेक वर्षों से चलाये जाने वाले डकोटा विमानों को बदलने की आवश्यकता स्वीकार कर लिये जाने पर भी उन्हें न बदलने के क्या कारण हैं;

(ख) इन विमानों के स्थान पर उपयुक्त विमान लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है; और

(ग) इन डकोटा विमानों को कब तक बदलना निगम के लिए संभव हो सकेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कारपोरेशन द्वारा डकोटा विमानों को बदलने की आवश्यकता को कुछ वर्ष पूर्व स्वीकार कर लिया गया था। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण बदलने का कार्य धीमा रहा।

(ख) और (ग) : कारपोरेशन ने, डकोटा विमानों को बदलने के लिये, एवरो 748 सीरीज़ ii विमान खरीदने का आर्डर दे दिया है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बदलने का कार्य 1968 में पूरा हो जाने की संभावना है।

बम्बई पत्तन से न उठाया गया माल

681. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन पर सात वर्षों से माल पड़ा हुआ है, जो उठाया नहीं गया है;

(ख) उस पत्तन पर एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए माल का ब्यौरा क्या है तथा वह कितने मूल्य का है;

(ग) क्या अन्य पत्तनों पर भी माल वर्षों से पड़ा हुआ है जो उठाया नहीं गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक पत्तन पर एक वर्ष से अधिक समय से कितना माल पड़ा हुआ है; और

(ङ) पत्तनों से तुरन्त माल को लदवाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ) : कुछ जब्त किया गया माल जो सन 1958 में आया था और जिसमें 7 तेल से चलने वाले ट्रैक्टर और 778 बिजली के इनसुलेटर क्रेटस शामिल हैं बम्बई पत्तन में बिना निकासी किये ही पड़े हैं। सम्बन्धित सीमा शुल्क अधिकारी जो जब्त किए गए माल की निकासी करने से सम्बन्धित है, उसके अन्तिम निपटान के लिए कोशिश करते आ रहे है।

मूल रूप से ट्रैक्टर को आयात करने वाली पार्टी ने पंजाब हाईकोर्ट में रिट पेटीशन दर्ज की थी जो अभी भी विचारार्थ पड़ी है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मामले को अन्तिम रुप से फैसला होने तक पंजाब उच्च-न्यायालय को सामान के निपटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। दूसरे मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों ने सामान का नीलाम करना चाहा किन्तु बोली कम पड़ने के कारण नीलाम बोली को वापिस ले लिया। वे उस सामान को बेचने के लिए एक सरकारी विद्युत अन्डरटेकिंग के साथ सौदा कर रहे है।

यह ज्ञात हुआ है कि जब्त किए गये माल के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में जैसे इस्पात की चादरों के बण्डल, बिजली के तार के बण्डल, मोटर के पुर्जे, नैलोन के तागे, इस्पात के पाइप, केमिकल रबर का सामान, मशीन, ड्रम, डाइज़, लारी के पहिए, साइकिल के रिम आदि जसी वस्तुए एक साल से भी अधिक समय से बम्बई पत्तन पर बिना निकासी के पड़े हैं। प्रत्येक किस्म के सामान की मात्रा और कीमत का विस्तृत ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं है। कुछ सामान जिस में सामान्य आयात की हुई चीजें, इस्पात और अन्य माल भी शामिल है कलकत्ता पत्तन पर बिना निकासी के पड़ा हुआ है। दूसरे बड़े पत्तनों में बिना निकासी किये सामान की मात्रा नगण्य है।

पत्तन अधिकारियों ने माल की शीघ्र निकासी के लिए दो प्रमुख उपाय लागू कर दिये है। इन में एक विलम्ब शुल्क की वसूली को दृढ़ता से लागू करना है ताकि कोई पार्टी पत्तन का प्रयोग गोदाम के रूप में न करे। दूसरा, समय समय पर बिना निकासी के पड़े सामान को नीलाम करने की व्यवस्था है। किन्तु जब्त किए गये सामान के निपटान करने की जिम्मेदारी सीमा शुल्क अधिकारियों की है जिन्हें माल के निपटान के लिए व्यवस्था करनी होती है। पत्तन अधिकारी सीमा शुल्क अधिकारियों को जब्त किए गये माल की शीघ्रता से निकासी करने की आवश्यकता पर और सीमा शुल्क प्रक्रिया निर्धारण करने पर बल देते रहे हैं ताकि पत्तनों पर देरी न हो। जहां तक अन्य बिना निकासी किये गए सामान का सम्बन्ध है पत्तन अधिकारी समय समय पर उसको नीलाम करने की व्यवस्था करते है। परन्तु कभी कभी बोली बहुत कम होती है।

सरकार पत्तनों पर बिना निकासी पड़े सामान की स्थिति को ध्यान से देख रही है और यदि उस की निकासी की दिशा में शीघ्र सुधार न हुआ तो उसके लिए कुछ विशेष कानूनी साधनों जैसे बिना निकासी वाले सामान की नीलाम करने के बजाय उसे बिक्री करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

अमरीका से चावल

682. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को मिलने वाले बकाया 40,000 टन चावल की सप्लाई करने के लिए अभी तक आज्ञा नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका सरकार से कहा गया है कि वह पाकिस्तान हो कर भारत में चावल भेजने के स्थान पर पी० एल० 480 व्यवस्था के अन्तर्गत भारत को अतिरिक्त चावल की सप्लाई सीधे ही करे, और यदि हां, तो उस के बारे में क्या उत्तर मिला है; और

(ग) पाकिस्तान होकर भारत आने वाले 40,000 टन चावल की सप्लाई न होने के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिए और क्या वैकल्पिक कार्रवाई की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान सरकार को शेष मात्रा के निर्यात करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है अथवा नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) देश की समस्त आवश्यकताओं के संदर्भ में चावल आयात करने के प्रबन्ध किये जाते हैं और पाकिस्तान से 40,000 टन चावल न प्राप्त होने से जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं।

सामान्य माल पर अतिभार

683. श्री क० ना० तिवारी : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **परिवहन** मंत्री 7 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अमरीका-भारत-श्रीलंका-बर्मा आउटवर्ड कान्फ्रेंस बम्बई के मार्ग से भारत आने वाले सामान्य माल पर अतिभार लगाने का विचार त्यागने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण बताये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। अतिभार लगाने का विचार छोड़ दिया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के बेकार खड़े विमान

684. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के भिन्न-भिन्न प्रकार के कितने विमान बेकार खड़े हैं;

(ख) बेकार खड़े विमान कितने प्रतिशत हैं;

(ग) कितने विमान आयात किये जाने वाले पुर्जों के न होने के कारण बेकार खड़े हैं;

(घ) उनकी मरम्मत के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ङ) उन्हें उड़ने योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास केवल एक विमान।

(ख) 1.6 प्रतिशत।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हैदराबाद में खड़े हुए एक विमान की आवश्यक मरम्मत की जा रही है।

विमान सेवायें

685. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 के पहले दस महीनों में इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन तथा एयर इण्डिया की कितने प्रतिशत उड़ानें विभिन्न हवाई अड्डों से निर्धारित समय से 15 मिनट से अधिक देरी से हुई, अथवा विमान 15 मिनट से अधिक देरी से पहुंचे ; और

(ख) ऐसे विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एयर कारपोरेशन नियम, 1954 के अधीन, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया अपनी अनुसूचित सेवाओ में होने वाली क्रमश: आधा घण्टे और 2 घण्टे से अधिक की देरियों का रिकार्ड रखते हैं। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित सेवाओं में जनवरी से जुलाई, 1965 के महीनों के दौरान देर से होने वाली रवानगियों (30 मिनट से अधिक) का प्रतिशत क्रमश: 11.0, 9.0, 8.8, 7.0, 8.5, 12.7 और 15.4 है। इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की अनुसूचित सेवाओं में अगस्त से अक्तूबर, 1965 तक होने वाली आधे घण्टे से अधिक देरियों और एयर इंडिया की अनुसूचित सेवाओं में जनवरी से अक्तूबर, 1965 तक होने वाली दो घण्टे से अधिक की देरियों के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और यथासमय सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे। कारपोरेशन विमानों के देर से आने के रिकार्ड नहीं रखते हैं।

(ख) देरियों के मुख्य कारण (i) यांत्रिक और इंजीनियरी, (ii) खराब मौसम, और (iii) आनुषंगिक हैं।

"लेबर बैंक"

686. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए देश में "लेबर बैंकों" का पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) पिछले दो महीनों में इस कार्यक्रम में लोगों ने क्या उत्साह दिखाया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : प्रत्येक सबल शरीर व्यस्क के प्रति मास एक दिन की न्यूनतम दर से निशुल्क श्रमदान (या उसके बराबर का धन) पर आधारित रक्षा श्रम बैंक, चीनी हमले के समय शुरू की गई ग्राम स्वयंसेवक दल की योजना का अविभाज्य अंग है। वर्तमान सन्दर्भ में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे स्थानीय रक्षा, जन-शिक्षा और उत्पादन के क्षेत्रों में ग्राम स्वयंसेवक दल की गतिविधियों को बढ़ावा दें और उन्होंने ऐसा करना स्वीकार भी कर लिया है।

ग्राम पंचायत

687. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों ने आपात काल में महत्वपूर्ण कार्य किया है;

(ख) इन पंचायतों ने सैनिक कार्रवाईयों में सहायता देने के लिए क्या क्या कार्य किये हैं; और

(ग) नई परिस्थितियों के सन्दर्भ में इन पंचायतों के कार्यक्रम को किस प्रकार नया रूप दिया गया है तथा इनको कितना अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) पंचायतों ने जो काम किए उनमें साम्प्रदायिक सामंजस्य एवं जनता का मनोबल बनाए रखना और रेलों की पटरियों, बिजली तथा तार लाइनों, सड़कों, पीने के पानी के कुओं, पानी की पाइप लाइनों, पुलों तथा सिंचाई के साधनों की सुरक्षा शामिल हैं। उनमें से कुछेक ने पाकिस्तानी छाताधारी सैनिकों और तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ने में भी सहायता दी।

(ग) पंचायतों ने समय की आवश्यकता के अनुसार अपने कार्यक्रम में सुधार किया। उन्हें कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी सांविधिक रूप से नहीं दी गई है।

कराची होकर चलने वाली विमान सेवायें

688. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराची होकर चलने वाली सब विमान सेवाओं को सलाह दी गई है कि उनके हित में यही उचित है कि वे भारत आने वाली कोई डाक अथवा सामान कराची होकर न लायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्देश का क्या प्रभाव हुआ है और विमान सेवाओं ने कहां तक इसका पालन किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एयरलाइनों को दिये जाने वाले निदेश का काफी सन्तोषजनक रूप से पालन हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारत के लिए आने वाले सामान को उतारने की तबसे केवल तीन घटनाएं हुई हैं।

कराची में के० एल० एम० के विमान से माल उतारना

689. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री यशपाल सिंह :

श्री हेडा :

श्री ओंकारलाल बेरवा :

श्री कपूर सिंह :

श्रीमती मैमूना सुलतान :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पाकिस्तान ने कराची में के० एल० एम० के एक विमान से तार, कपड़े के नमूने और डाक उतार ली; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए एयरलाइनों को उनके ही हित के लिए यह सलाह दी गयी थी कि वे कराची से होकर गुजरने वाली अपनी सेवाओं में भारत के लिए आने वाला सामान और डाक न लाएं।

उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों पर धन का लगाया जाना

690. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाईयों पर अधिक धन लगाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के लिये चतुर्थ योजना में निम्नलिखित राशियां लगाने का विचार है :—

रुपये करोड़ों में

	सरकारी	गैर-सरकारी	कुल
(एक) नाइट्रोजनीय उर्वरक	176.3	130.00	306.30
(दो) फॉस्फेटी उर्वरक		20.00	20.00
(तीन) कीटनाशक . . .	2.0	10.00	12.00

ऊपर दिये गये आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि चतुर्थ योजना के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

पटसन की खेती

691. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन पैदा करने वाले सभी राज्यों ने, पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप उदार बनाये जाने का लाभ उठाया है;

(ख) किन किन राज्यों से वित्तीय सहायता ली है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योजनाओं में कहां तक प्रगति हुई है तथा उसका क्या परिणाम निकला है और यदि कुछ राज्यों ने योजना से लाभ नहीं उठाया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के राज्यों से पटसन के लिये अच्छी किस्म के गलाने वाले तालाबों के लिये प्राप्त योजनाएं 1965-66 में क्रियान्वित करने के लिये अनुमोदित कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में इस योजना पर खर्च का अनुमानित केन्द्रीय भाग 54,750 रुपये हैं जो कि मध्याकालीन ऋण और सहायता के रूप में क्रमशः 41,062.50 रु० और 13,687.50 रु० होगा। जहां तक बिहार और उड़ीसा की राज्य सरकारों का संबंध है उनसे 1965-66 के दौरान खर्च के अनुमान देने के लिये कहा गया है।

(ग) जिन राज्यों की योजनाओं को पहले से ही स्वीकार कर लिया गया था उनसे योजना की प्रगति का ब्योरा मांगा गया है। पश्चिम बंगाल ने अभी तक अपनी अन्तिम योजना नहीं भेजी है। आसाम न कहा है कि उसे केन्द्रीय सहायता स्वीकार्य नहीं है।

कानूनी सहायता

692. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जरूरतमन्द तथा निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता तथा कानूनी परामर्श देने की व्यापक व्यवस्था लागू करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार जरूरतमन्द तथा निर्धन व्यक्तियों के लिये न्यायालय की फीस को कम करने तथा कानूनी सहायता का समाजीकरण करने का है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : कानूनी सहायता (जिसके अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को कानूनी परामर्श देना भी है) की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतएव जरूरतमन्द और निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता तथा परामर्श देने और न्यायालय की फीस कम करने और ऐसी कानूनी सहायता का समाजीकरण करने की एक व्यापक व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल जोधपुर विमान सेवा

693. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भोपाल और जोधपुर के लिये विमान सेवा चालू करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को यह बात बताई गई है कि गलत अवधारणा और योजना के कारण ही इनमें से कुछ विमान सेवाओं को आरम्भ नहीं किया गया था अथवा उन्हें चलाना वाणिज्यिक दृष्टि से ठीक नहीं पाया गया था; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन का एक समिति नियुक्त करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन का दिल्ली-लखनऊ-भोपाल-नागपुर मार्ग पर 1-1-1966 से प्रयोगात्मक आधार पर एक वाइकाउण्ट सेवा चलाने का प्रस्ताव है। जोधपुर को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

रेगिस्तान विकास बोर्ड

694. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :

श्री डा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगिस्तान विकास बोर्ड बनाने की योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो बोर्ड की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : रेगिस्तान विकास बोर्ड स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। हां, आपात को देखते हुए इसकी क्रियान्विति को कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ेगा क्यों कि इस परियोजना से शीघ्र लाभ नहीं होगा।

सामाजिक विधान का समाज शास्त्रिय अध्ययन

695. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में भारत में सामाजिक कानूनों का समाजशास्त्र की दृष्टि से विशिष्ट अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या इसको समान रूप से पूरे देश में लागू किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी । नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय जहाजरानी निगम

696. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री मुथिया :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम का विचार कोई बड़ी विस्तार योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उससे पंजी परिव्यय और "क्रेडिट टनभार" में कितनी वृद्धि होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) 21 जहाजों के अतिरिक्त जिन में 2,26,500 कुल टन के तीन निर्माणाधीन खुला माल वाहक भी शामिल है, निगम ने लगभग 1,70,000 कुल टन के 18 जहाजों को प्राप्त करने का निश्चय किया है और जिस के लिये सरकारी मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित (21+18) जहाजों के लिये पूंजी में वृद्धि की सीमा लगभग 57.78 करोड़ रुपया होगी । आस्थगित भुगतान की शर्तों पर या ऋण का प्रबन्ध कर के जिस टनभार को प्राप्त करने का प्रस्ताव है वह 2,98,000 कुल पंजीकृत टन होगा ।

साल में धान की दो फसलें

697. **श्री मरंडी :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री उटिया : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में साल में धान की दो फसलें पैदा करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी साल में दो फसलें पैदा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बिहार सरकार ने सूचना दी है कि उसने एक कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग एक लाख एकड़ भूमि में धान की दूसरी फसल उगाई जा सकती है ।

(ख) और (ग) : कुछ राज्यों में अर्थात गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में दूसरी फसल उगाने का विचार है बशर्ते कि सिंचाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों । गजरात में एक प्रारम्भिक जांच की गई है । केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदश, मैसूर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल म दो और तीन फसलें उगाई जा रही हैं ।

वर्ष में गेहूं की दो फसलें

698. **श्री मरंडी :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री उटिया : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन किन राज्यों में वर्ष में गेहूं की दो फसलें पैदा करने के प्रयोग किये गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक वर्ष में गेहूं की फसलें उगाने के तजर्बे देश के गेहूं पैदा करने वाले सभी मुख्य राज्यों में किये जा रहे हैं जैसे कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि ।

(ख) सिंचाई वाले क्षेत्रों में जल्दी उगने वाली और बीमारी न लगने वाली गेहूं की किस्मों के साथ विशेषत: शर्द ऋतु में दो फसलें उगाने में काफी सफलता मिली है ।

एरियाना अफगान एयरलाइन्स के काबुल जाने वाले विमान का दिल्ली लौटना

699. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

श्री बसुमतारी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काबुल जा रहे एरियाना अफगान एयरलाइन्स का एक यात्री विमान, जिस में भारतीय यात्रा कर रहे थे, पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अपने अन्तव्य स्थान की ओर जाने की अनुमति न दिये जाने के कारण 7 अक्टूबर, 1965 को दिल्ली लौट आया था;

(ख) क्या विमान को लाहौर में उतरने के लिये कहा गया था; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एरियाना अफगान सेवा को, जोकि 7-10-65 को लाहौर होती हुई काबुल के लिये वापिसी उड़ान पर थी, लाहौर के हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा, काबुल रवाना होने से पहले लाहौर में उतरने के लिए कहा गया । विमान भटिण्डा तक उड़ने के बाद दिल्ली वापिस आ गया क्योंकि विमान में भारतीय सवारियां और माल था । नागर विमानन के महानिदेशक ने लाहौर के हवाई अड्डा अधिकारियों को 7-10-65 को निर्देश करते हुए एक संकेत भेजा कि अगर उनको लाहौर से काबुल जाने के लिए सीधा मार्ग मंजूर नहीं था तो उन्हें एरियाना एयरलाइन्स को इसके बारे में पहले बता देना चाहिये था । चुँकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने, विमान के मुल्तान के रास्ते होकर जाने की शर्त पर उसे पाकिस्तान में बिना उतरे पाकिस्तानी सीमा पर से उड़ान करने की आज्ञा दे दी थी, इसलिये नागर विमानन के महानिदेशक ने भटिण्डा और मुल्तान के बीच सीधी उड़ान करने की आज्ञा दे दी । दूसरे दिन अर्थात 8-10-65 को एरियाना अफगान सेवा ने इस नये मार्ग पर से काबल के लिए उड़ान की ।

पाकिस्तान के नागर विमानन के महानिदेशक ने 9-10-65 को एक नोटम जारी किया जिसमें उन सभी सेवाओं को, जो पहले पश्चिमी पाकिस्तान होकर जाती थीं, कराची या लाहौर में उतरने के लिये कहा गया । इसके परिणामस्वरूप, एरियाना अफ़गान सेवाएं काबुल और दिल्ली के बीच लाहौर होकर चल रहीं हैं, जहां विमान को पाकिस्तान के नागर विमानन के महानिदेशक की शर्तों के अनुसार उतरना पड़ता है ।

Legislation for Curbing Social and Economic Crimes

700. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the Law Commission has recommended the enactment of any legislation for curbing social and economic crimes; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of law (Shri Jaganatha Rao) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

Corruption

701. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) in what respect Government have sought the advice of the Law Commission on the recommendations of the Santhaman Committee for eradicating corruption, and

(b) whether any advice in this regard has been tendered so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) A proposal to include certain social and economic offences in the Indian Penal Code in pursuance of the recommendations of the Santhanam Committee has been referred to the Law Commission for its consideration.

(b) No, Sir.

बैतुल में लगुड़-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र

702. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री चांडक :
श्री महेश दत्त मिश्र :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री वाडिवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री 31 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतुल में एक सरकारी लगुड़-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस बीच महाराष्ट्र राज्य में चन्द्रपुर में लगुड़ निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है।

लगुड़-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र

703. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री चांडक :
श्री महेश दत्त मिश्र :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लट्ठे बनाने (लौगिंग) के चार सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्थानों का चुनाव कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं; और

(ग) इन स्थानों को चुनने में किन बातों को ध्यान में रखा गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तीन लगुड़ निर्माण केन्द्रों को स्थापित करने के स्थान अब तक चुने गये हैं।

(ख) उत्तरी भाग : देहरादून
दक्षिण भाग : कौम्बेटूर
मध्य भाग : चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

(ग) लगुड़ निर्माण केन्द्रों को चुनने में निम्न बातों को ख्याल में रखा गया है :—

(एक) केन्द्र तक रेल तथा सड़कों का होना और केन्द्र पर आवश्यक स्थान तथा अन्य सहायक सुविधाओं का उपलब्ध होना।

(दो) परियोजना में अन्तर्गत लगुड़ निर्माण में प्रशिक्षण देने के लिये आस पास के वन की किस्मों की उपयुक्तता।

(तीन) विभाग द्वारा जिन वनों में काम किया जा रहा है उनका काफी बड़े क्षेत्र में उपलब्ध होना जिससे कि आधुनिक लगुड़ निर्माण तकनीकी ज्ञान को काम में लाया जा सके।

(चार) वन कालिजों की कक्षाओं के लिये केन्द्र के पास उपयुक्त सुप्रबन्धित वन क्षेत्रों की उपलब्धता।

चमड़ा सामान उद्योग

704. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में बाटा शू कम्पनी की बड़ी संख्या में शाखायें खुल जाने से चमड़े का सामान बनाने वाले ग्रामोद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पडा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन उद्योगों के संरक्षण के लिये कोई उपाय करने का विचार कर रही है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार को ऐसी स्थिति का पता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कीड़ों की रोकथाम

705. श्री रा० गि० दुबे : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज के भण्डारों में कीडा लगने को विकिरण (रेडिएशन) द्वारा रोकने के अध्ययन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस प्रणाली के प्रयोग के परिणामों का पता लगाने के लिए किसी राज्य के परामर्श से कोई परीक्षण किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अनाज के भंडारों में कीडा लगने को विकिरण (रेडिएशन) द्वारा रोकने पर देश में कोई काम नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

'जो खाओ सो उपजाओ' आन्दोलन

706. श्री बसुमतारी : **श्री कपूर सिंह :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के कहने पर राजधानी में 'जो खाओ सो उपजाओ' आन्दोलन आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) राजधानी में जल्दी उगने वाले फल और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिये दिल्ली प्रशासन ने निम्न कदम उठाये हैं :—

1. उत्पादन के लिये आवश्यक विभिन्न वस्तुओं का संभरण करना जैसे कि पौद, उर्वरक और कीटनाशक, खैबर पास, अन्नपुर्णा (जनपथ), कृषि भवन और लाजपत भवन में चार विक्रय डिपो स्थापित किये गये हैं । इन डिपोओं पर उत्पादन की आवश्यक वस्तुए छोटे छोटे पैकेटों में 'न नफा न नुकसान' के आधार पर बेची जा रही हैं ।

2. प्रारम्भिक ज्ञान देने और बीज, पौढ और उर्वरकों आदि के संभरण को बनाये रखने के लिये दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों के लिये 20 मालियों का एक दल नियत किया गया है ।

केरल में उगाही प्रणाली

707. श्री मुहम्मद कोया :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक समान स्तर पर उगाही करने का आदेश दिया गया है;

(ख) क्या इसका कुछ लोगों पर, जिनका उत्पादन कम है, प्रतिकुल प्रभाव पडा है; और

(ग) क्या ऐसे लोगों को कोई छूट दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : केरल में धान की उगाही एक मान के अनुसार की जाती है जिसका संबंध इस बात से है कि कोई कृषक कितनी भूमि में काश्त करता है। दो एकड़ या इससे कम भूमि वालों को उगाही से पूरी छूट दी गई है। दूसरे मामलों में जहां कि काश्तकार, फसल के न होने, सुखे, बाढ़, कीटाणु द्वारा अथवा अन्य किन्हीं परिस्थितियों में जो काश्तकार के नियन्त्रण के बाहर हों, निर्धारित मान के अनुसार न दे सकता हो, तेहसीलदार अथवा ताल्लुक संभरण अधिकारियों को उगाही में कमी करने का अधिकार दिया गया है ।

केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

708. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केरल में तनूर परप्पनानगडी, कुट्टयी परवन्ना और चालियम में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : निम्न उपाय किये गये हैं :–

(एक) अधिक शार्क पकड़ने के लिये घुमने वाले जंजीर के हकों का निर्माण किया गया है ।

(दो) मछली पकड़ने के काम को और अच्छा करने के लिये कृत्रिम रेशें के जाल काम में लाये जा रहें हैं ।

(तीन) यन्त्रोकृत नौकाओं के चलाने में 17 अधिकारों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

(चार) 5 यन्त्रोकृत नौकाएं दी गई है ।

(पांच) ये केन्द्र तिरुरंगाडी, तानुर और तिरुर खंडो के अधीन आते हैं और प्रत्येक खंड मत्स्य विस्तार अधिकारियों की सहायता से मछली पालन को अधिक ध्यान दे रहा है ।

(छः) पांच प्रारंभिक उत्पादन मछिमारे सहकारी समितियां बनाई गई हैं जिनके कुल सदस्य लगभग 800 हैं ताकि गहरे और दूर के समुद्र में मछलियां पकड़ी जा सकें। इन समितियों को नाइलोन (8,820 रु०), नौकाएं (9,250 ०) और मछली पकडने के एकक (12,400 रु०) की खरीद के लिये तानूर और तिरुरंगाडी में ऋण दिये गये हैं ।

(सात) कूटाई और पारावन्ना में मछली पकड़ने के दो सहकारी एककों को चालू करने के लिये तानुर खंड को 25,000 रु० दिये गये हैं और ये एकक 31-12-1965 से पहले चालू हो जायेंगे ।

(आठ) मछलियों की बढ़ी हुई मात्रा को सफाई से रखने के लिये तानुर में 5 टन बर्फ और 40 टन कोल्ड स्टोरेज में संयंत्र स्थापित किये गये हैं। ये संयंत्र 26-9-65 से काम करने लग गये है ।

इन्दौर हवाई अड्डा

709. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री चाण्डक :
श्री पाराशर :
श्री महेश दत्त मिश्र :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 14 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर हवाई अड्डेपर धवन मार्ग (रनवे) का विकास कार्य अब पूरा हो गया है;

(ख) क्या बंबई से इंदौर तक विमान सेवा फिर से चालू हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह सेवा भोपाल तक कब तक चालू की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) आगे विचार करने पर कारपोरेशन ने इस सेवा को इन्दौर से भोपाल तक न बढ़ाने का निर्णय किया है। कारपोरेशन ने, फिर भी, 1 जनवरी, 1966 से दिल्ली–लखनऊ–भोपाल–नागपुर मार्ग पर सप्ताह में चार बार की एक वाइकाउन्ट सेवा चलाने की योजना बनायी है जोकि कलकत्ता–नागपुर–बम्बई की वाइकाउण्ट सेवा से सम्बद्ध होगी।

राशन व्यवस्था

710. **श्री काजरोलकर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चालू की गई राशन व्यवस्था योजना के अन्तर्गत अनाज देने के लिये एक सी मात्रा नियत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वयस्क के लिये मासिक कोटा कितना निर्धारित किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : कानूनी रुप से राशन वाले सभी क्षेत्रों में प्रति प्रौढ़ प्रति सप्ताह लगभग 2 किलो ग्राम का न्यूनाधिक एकसमान राशन निर्धारित करने का विचार है। कानूनी रुप से राशन व्यवस्था अभी कलकत्ता, मद्रास और कौम्बतूर में लागू की गई है। कलकत्ता में 19,00 ग्राम और मद्रास और कौम्बेतूर में 2000 ग्राम प्रति प्रौढ़ प्रति सप्ताह का राशन है।

Persons Trained in Social Security Measures

711. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the number of persons trained so far in social security measures; and

(b) the expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) 4890 persons have been trained as Gram Sevika, Balsevikas etc. Apart from this, ten officers of the Social Security Department and its subordinate organisations have been trained abroad under various I.L.O./ United Nations Assistance Schemes.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Prices of Foodgrains

712. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make a technical analysis for knowing the reasons for continuous rise in the prices of foodstuffs; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The Government are maintaining statistics on production, market prices, market arrivals and demands, stock position, market sentiments etc. On the basis of this information, the various factors responsible for fluctuation in prices are analysed on a continuing basis and the price situation is kept under constant watch and review. The Government have recently set up Agricultural Prices Commission to provide advise on a continuing basis on agricultural price policy and price structure. The terms of reference of the Agricultural Prices Commission include the review of the developing price situation and making appropriate recommendation as and when necessary within the frame-work of the overall price policy.

Tubewell Accessories

713. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of tubewell accessories belonging to the Central Government are lying for the last six months in Ramdevra village Jaisalmer District; and

(b) if so, the reasons for the delay in sinking the tubewells there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). No material belonging to the Exploratory Tubewells Organisation under the Ministry of Food & Agriculture is lying at Ramdevra village in Jaisalmer District. There is also no proposal to construct a tubewell thereby that Organisation.

गुरदासपुर जिले में सड़क संचार-व्यवस्था

714. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पाकिस्तानी आक्रमण को देखते हुये गुरदासपुर जिले में सड़क संचार व्यवस्था को आधुनिक और नवीनतम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस कार्य के लिये कितनी रकम मंजूर की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गुरदासपुर जिले में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मुख्य मार्ग और राज्य सड़कों की देखभाल में उपयुक्त कार्यवाही की है और सेनाओं की आवश्य-

कताओं को पूरा करने के लिये उनकी टूटफूट की मरम्मत की है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के अलावा सड़कों के सुधार की 50 प्रतिशत लागत पूरी करने के लिये सहमत हो गई है।

(ख) कार्य हाथ में ले लिया गया है लेकिन अनुमानों की जांच की जा रही है।

आसाम में फ्लाइंग क्लब

715. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असैनिक फ्लाइंग क्लबों के जरिये आसाम के नवयुवकों और नवयुवतियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक हवाई-अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) गौहाटी के हवाई अड्डा अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे असम फ्लाइंग क्लब के लिए एक विमान क्षेत्र के निर्माण के लिए उस क्लब द्वारा बतायी गयी जगहों का निरीक्षण करे और सरकार को एक रिपोर्ट भेजें।

जयपुर तथा उदयपुर के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की डकोटा विमान सेवा

716. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री मधु लिमये :

क्या **असैनिक उडड्यन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से जयपुर और उदयपुर के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कोई नई विमान सेवा आरंभ की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : दिल्ली से जयपुर और उदयपुर को, सेवा, परिचालन सम्बन्धी स्थिति के कारण, थोड़े समय के लिए एक डकोटा विमान से चलाई गई थी। कारपोरेशन ने 25-10-65 से इस मार्ग पर फ्रेण्डशिप विमान चलाना फिर से आरम्भ कर दिया है ।

कृषि विकास

717. **श्री काजरोलकर :**

श्री कृष्णपाल सिंह :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रायोजित कृषि विकास संबंधी विश्व निर्देशक योजना के संबंध में विश्व के नेताओं की सलाहकार नामिका (पैनल) के रोम में 11 से 18 अक्टूबर, 1965 तक हुए प्रथम सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं; और

(ख) भारत की ओर से उन्होंने क्या भाग लिया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : तालिका किन्हीं अन्तिम निष्कर्षों पर नहीं पहुंची। यह वास्तव में एक सलाहकार ग्रुप था जिसने योजना के संभावित क्षेत्र और इसकी तैयारी के तरीकों पर चर्चा की। इस सलाहकार तालिका के सदस्यों को देश भर से नहीं बुलाया गया था बल्कि उनके कृषि संबंधी नियोजन के अनुभव के आधार पर बुलाया गया था। खाद्य तथा कृषि मंत्रीने तालिका को विकासशील समाजों में कृषि की विशेष समस्याओं और अभिव्यक्त विश्व योजना की तैयारी से उनके संबंध का विश्लेषण दिया।

केरल में उल्लेयीरी पुठयांजली सड़क

718. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कम्जिकोड जिले में पोराक्कत्तेरी पुल यातायात के लिये कब खोला गया था;

(ख) पुल पर कितनी रकम खर्च हुई;

(ग) उल्लेयीरी पुठियांजली का निर्माण पहले कब हुआ था; और

(घ) पुल बन जाने के तुरन्त बाद सड़क को चौड़ा कर के उसे पक्का क्यों नहीं किया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 4 अप्रैल, 1964।

(ख) 6,07,000 रुपये ।

(ग) और (घ) : प्रश्न के (ग) भाग में उल्लिखित सड़क का सही नाम पुथियायन्गदी-उल्लेरी सड़क है। यह केरल राज्य में एक स्थानीय सड़क है। राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से यह निश्चित रूप से मालूम किया गया है कि यह जिला बोर्ड की एक पुरानी सड़क है जिसको 1962 में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। धन की कमी के कारण इस सड़क का सुधार राज्य सरकार ने नहीं किया है। किन्तु राज्य के मुख्य इंजीनियर ने सूचित किया है कि सड़क के पुथियायन्गदी–पोराक्कात्तेरी भाग के सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रशासनिक मंजूरी लेने के लिए वे अब कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि सड़क का पोराक्कात्तेरी पुल और उल्लेरी के बीच का भाग राज्य की चौथी आयोजना के प्रस्ताओं में शामिल किया गया है।

कृषि ऋण

719. **श्री हेडा** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 512 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक काश्तकारों को 70 प्रतिशत कृषि ऋण देने के के कार्यक्रम पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई ठोस योजना का प्रस्ताव है तो वह क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : 29 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 1965 तक बम्बई में हुए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों और सहकारिता मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में 650 करोड़ रुपये तक के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण, जिनके चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा वितरित किए जाने की सम्भावना है, के अस्थायी कार्यक्रम पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया। यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के निर्धारण और ऋण ढांचे द्वारा साधनों के सम्भावित जुटाव को देखते हुए अनुमानों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। आशा है कि नवम्बर और दिसम्बर, 1965 में होने वाली आगामी वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान प्रत्येक राज्य के कार्यक्रम को ठोस रूप दिया जाएगा।

बच्चों को गोद लेने का कानून

720. **श्री हेडा** : क्या **विधि** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों को गोद लेने के कानून को वर्तमान स्थिति के अनुकूल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

अगरतला हवाई अड्डा

721. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा हवाई हमलों के कारण अगरतला हवाई अड्डे को हानि पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या हानि हुई है ; और

(ग) इसका हवाई अड्डे में असैनिक उड्डयन सेवा पर क्या प्रभाव पड़ा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : पाकिस्तान विमानों द्वारा हवाई अड्डे पर बमबारी करने के कारण कुछ इमारतों को सामान्य नुकसान पहुंचने के अलावा कुछ उपस्करों को भी नुकसान पहुंचा।

(ग) हवाई हमलों से, इस प्रकार, हवाई अड्डे में नगर विमान सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन, चूंकि हवाई अड्डा दुश्मन के क्षेत्र से छोटे हथियारों से की जाने वाली गोलाबारी के रेंज के अन्तर्गत था इसलिये विमान सेवाएं थोड़े समय के लिए बन्द कर दी गयीं।

वनों का विकास

722. **श्री वारियर** :

श्री दाजी :

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास कार्यक्रमों में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। पुनरीक्षित योजना व्यय में जो कि 51.78 करोड़ रु० है। 48.70 करोड़ रु० खर्च होने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विनविज्ञान की विकास योजनाओं में चतुर्थ योजना में देश की लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इसके उत्पादन को बढ़ाने के उपायों पर जोर देने का प्रस्ताव किया गया है। उनमें से अधिक महत्व पूर्ण योजनाएं पारम्परिक तथा जल्दी उगाने वाली

किस्मों को उगाने की है ताकि उद्योगिक प्रयोजनों और ईंधन के लिये लकड़ी मिल सके, लगुड निर्माण के आधुनिक तरीकों को काम में लाया जा सके, अति क्षय को कम किया जा सके और वनक्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

वन संसाधनों के सर्वेक्षण की योजना भी महत्व की है।

(घ) चतुर्थ योजना में वनविज्ञान के विकास के लिये लगभग 150 करोड़ रु० की राशि का अस्थायी रुप से प्रस्ताव रखा गया है।

खाद्य विभाग के फेटीरिया सहकारी स्टोर्स लिमिटेड

723. **श्री दाजी :**

श्रीमती बिमला देवी :

क्या **सामुदायिक** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विभाग के फेटीरिया सहकारी स्टोर्स, नई दिल्ली की परिसमापन कार्यवाही अन्तिम रूप से बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या परिसमापन अधिकारी अथवा उप रजिस्ट्रार ने इस सहकारी स्टोर के सदस्यों को गत छः वर्ष में हुई घाटे तथा उसे पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कर दिया है;

(ग) क्या इस घाटे के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अभी नहीं। देय की वसूली अभी की जा रही है।

(ख) से (घ) : गत छः वर्षों में कोई घाटा नहीं हुआ है। ये 1958 तक के संचित व्यापारिक घाटे और कुछ परिसमापक द्वारा उपलब्ध पुराने माल के बेचने से हुए घाटे थे, जिनकी कीमत किताबी कीमत से कम प्राप्त हुइ थी। अतः किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका है।

उर्वरकों का सम्भरण

724. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेषकाल **में** अनाज तथा अन्य कृषि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का विचार कितना धन तथा किन योजनाओं पर खर्च करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, जो कि तृतीय योजना का अन्तिम वर्ष भी है, केन्द्रीय तथा राज्यों के क्षेत्रों के लिये कृषि कार्यक्रमों के लिये अब तक 223 . 99 करोड़ रु० का व्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें से 163. 50 करोड़ की राशि लघु सिंचाई, मिट्टी संरक्षण, उर्वरक, कीटनाशक, सुधरे हुए बीजों की योजनाओं के लिये और अन्य कृषि उत्पादन योजनाओं के लिये है जिसमें अनुसन्धान, शिक्षा तथा प्रशिक्षिण, विपणन आदि शामिल हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

725. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश करने में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) समिति ने अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया है। अब यह प्रतिवेदन तैयार कर रही है जिसके शीघ्र ही पेश किये जाने की संभावना है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Welfare of Families of Scheduled Castes in Rajasthan

726. **Shri P. L. Barupal :**

Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Social Security** be pleaced to state :

(a) the amount proposed to be spent on the Welfare of the families of Scheduled Castes in Rajastan during the year 1965-66;

(b) the items on which this amount will be spent; and

(c) the other arrangements made for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in addition to the above provision ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) Rs. 22·32 lakhs.

(b) The schemes on which the amount will be spent generally include scholarships, hostels, aid to voluntary Agencies, settlement on land, cottage industries, legal aid, housing and house-sites, drinking water wells etc.

(c) In addition to the exclusive benefits which the Scheduled Castes would derive from the above provision, the benefits from the general sector of the Plans and those from the reservation of seats provided for them in services and technical institutions etc. would also accure to them. Similar benefits are also available to Scheduled Tribes.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

727. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री बृजराज सिंह :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) उनका कारणवार ब्योरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 8006।

(ख) दिल्ली प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं का कारणवार-ब्यौरा सूचित करने वाले आंकड़े नहीं रखता है। फिर भी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के लिये निम्न मुख्य तथ्य जिम्मेदार हैं :—

(1) दुस्साहस और लापरवाही से मोटार चलाना।

(2) ओवरस्पीड चलाना।

(3) ड्राइवरों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन।

(4) पैदल राहियों और साइकिलवालों द्वारा लापरवाही।

(5) मोटार गाड़ियों में यांत्रिक खराबी।

(6) सड़क की सतह का खराब होना और खराब रितु की दशायें जैसे कुहरा, धुलिभरी आंधी, भारी वर्षा, इत्यादि।

संकर ज्वार

728. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जलगांव (महाराष्ट्र) में संगवी बद्रकी गांव के एक किसान द्वारा संकर ज्वार के बारे में किये गये नये प्रयोग के बारे में पता है, जो नब्बे दिन में पैदा होती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रयोग के लिये अपनाये गये तरीके का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

कृषि परियोजनाओं के लिये कनाडा से सहायता

729. **श्री बृजराज सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दीजी :
श्री वाडीवा :
श्री बड़े :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री शिवदत्त उपाध्यक्ष
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की सरकार ने सरकार की किसी बड़ी वन अथवा कृषि परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहयता देने की कोई पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का किन परियोजनाओं के लिये उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या कनाडा की सहायता के लिए की गयी परियोजनाओं में चम्बल घाटी को कृषि योग्य बनाना भी शामिल किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऐसी कोई पेशकश नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जरी कशीदाकारी (सोने का तार) का पुराना उद्योग

730. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज़री कशीदाकारी (सोने का तार) के बहुत पुराने उद्योग को फिर से चलाने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो हजारों बेकार और आंशिक रूप में काम करने वाले कुशल कारीगरों को रोजगार दिलाने के लिये ज़री उद्योग के अतिरिक्त और किन-किन रोजगार साधनों का पत्ता लगाया जा रहा है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि तांबा और सोने की कमी के कारण जरी उद्योग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

गुजरात में, जहां जरी उद्योग केन्द्रित है, उद्योग को तांबे का तार देने की पद्धति चालू है और वह काम सफलतापूर्वक चल रहा है। क्योंकि राज्य में तांबे का आवंटन इस उद्योग की आवश्यकतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय से केवल जरी उद्योग के लिये 400 टन का वार्षिक विशेष आवंटन करने की प्रार्थना की गयी है।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रस्थापित किये जाने के फौरन बाद जरी का धागा बनाने वालों को 50 ग्राम सोना खरीदने की अनुमति दी गयी। इस समय ज़री का धागा बनाने वालों को 1960, 1961 और 1962 में सोने की औसत वार्षिक सिद्ध खपत का 50 प्रतिशत मिलता है। स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन ज़री का निर्यात करने वालों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सोना देने को सहमत हो गया है।

ज़री के निर्यात के संवर्द्धन की योजना के अन्तर्गत, निर्माता-निर्यातक अपने निर्यात किये गये ज़री के सामान के नौतल-पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत तक तांबा और कुछ अन्य कच्चा माल आयात कर सकते हैं।

(ख) हाल ही में सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि ज़री उद्योग में लगे कुछ श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। इसकी जांच पडताल की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन द्वारा विमानों के किराये में कमी

731. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन अमरीका और यूरोप, अफ्रीका तथा मध्यपूर्व के बीच सभी उड़ानों के विमान किराये कम करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत को तथा भारत से होने वाली उड़ानों पर यह समझौता लागू नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामलें में भारत ने कोई कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन यातायात सम्मेलन की सितम्बर/अक्तूबर, 1965 में बरमूडा में हुई बैठक में जिन विमान कम्पनियों का प्रतिनिधित्व किया गया उनके बीच, उत्तरी और मध्य अटलांटिक के पार, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में सैर के लिए और ग्रुपों में विमान यात्रा करने के लिये किराये में कमी करने के बारे में एक प्रयोगात्मक करार हुआ। लेकिन सेवा की शर्तों पर मतैक्य न होने के कारण ये किराये अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किये जा सके।

(ख) यह सही नहीं है कि किराये में की जाने वाली कमी भारत के लिए/भारत से की जाने वाली उड़ानों पर लागू नहीं होती है। एयर इंडिया के कहने पर, भारत के लिए/भारत से की जाने वाली उड़ानों के विशेष किरायों में भी यह कमी करना स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कृषि नीति सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी

732. श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में अक्तूबर, 1965 में हुई कृषि नीति सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशें क्या है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) "खाद्यानों के समर्थक मूल्य निर्धारित करने" के बारे में वल्लभ विद्यानगर में 15 से 17 अक्तूबर, 1965 तक एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी में समर्थक मूल्य निर्धारित करने के बारे में विभिन्न मामलों और खाद्य नीति के सम्बन्ध उपायों पर विचार किया गया। सरकार को सरकारी तौर पर गोष्ठी की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है। तथापि यह समझा जाता है। कि सिफारिशें मुख्यतः समर्थक मूल्यों का स्वरुप और कार्य, उनको निर्धारित करने के लिये सम्बन्धित आंकडे और इन आंकडों के प्रयोग में होने वाली कठिनाईयों के बारे में हैं। गोष्ठी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बिक्री के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का समाहार करने की आवश्यकता और राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाने के महत्व पर बल दिया गया।

(ख) खाद्य नीति बनाते समय उपरोक्त (क) में निर्देशित बातों को ध्यान में रखा गया है।

कलिंग एयरलाइन्स के डकोटा का दुर्घटना-ग्रस्त होना

733. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अक्तूबर, 1965 को या उसके आगे-पीछे आसाम में मोहनबाडी के पास कलिंग एयरलाईन्स का एक डकोटा विमान गिर गया था;

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे/जख्मी हुए; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : कलिंग एयरलाइन्स का एक डकोटा विमान 17 अक्तूबर, 1965 को मोहनबाड़ी के पूर्व में लगभग 23 मील की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके परिणामस्वरूप विमान में बैठे सभी 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

(ग) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

Production of Coarse Grains

734. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to implement some schemes in Rajasthan with a view to increase the production of coarse grains;

(b) if so, whether they will be in private or in public sector;

(c) the amount likely to be spent thereon; and

(d) the estimated increase in production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d). Government are not contemplating the implementation of any production scheme in Rajasthan to increase the production of coarse grains in general. However, they propose to start two research schemes to tackle problems of a fundamental nature for the improvement of jowar and bajra and also to develop hybrid varieties of these crops with a view to increase production.

Buses Captured in Lahore Sector

735. Shri Madhu Limaye :
Shri D. D. Puri :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether eight Pakistani buses captured in Lahore sector are being given to the Bombay Municipal Corporation; and

(b) if so, the amount for which these buses are proposed to be sold to the Bombay Municipal Corporation ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No.

(b) Does not arise.

सहकारी फार्म

736. श्री दे० द० पुरी:
श्री मधु लिमये :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितने सहकारी फार्म स्थापित किये गये हैं; और

(ख) उनके क्षेत्रफल, उत्पादन तथा सरकार द्वारा उनको दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अगस्त, 1965 के अन्त तक 5,873 समितियां।

(ख) (1) क्षेत्र : 5.92 लाख एकड़।

(2) 1961-62 से 1964-65 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता : 4.11 करोड़ रुपये।

(3) यद्यपि 5,873 समितियों में से प्रत्येक के बारे में उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी हाल ही में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रो० गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति ने किया था, जिसने 35 अग्रगामी परियोजनाओं में 165 समितियों के कार्यकरण का अध्ययन किया। उत्पादन के बारे में समिति के निष्कर्ष रिपोर्ट के अध्याय 11 के पैराग्राफ्स 11.69 से 11.76 में दिये गए हैं। रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

भारतीय पर्यटन निगम

737. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन निगम बन जाने से पर्यटकों के आने में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिये निगम का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : पर्यटकों की उन सुविधायें की व्यवस्था के लिये जो पहिले उपलब्ध नहीं थी भारतीय निगम स्थापित किया गया है। इन सुविधाओं में ये बातें भी शामिल है : कुछ दुकानों की स्थापना करना, जिनमें आयात की गई जरूरी वस्तुएं जैसे तंबाकू का सामान, फोटोग्राफी का सामान तथा कोस्मेटिक आदि विदेशी पर्यटकों को विदेशी मुद्रा के बदले में बेचे जाएंगे ; सायंकालीन मनोरंजन की व्यवस्था, विशेष स क परिवहन का प्रबन्ध। ये सुविधाएं अंत में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने में मदद देंगी। इसके अलावा निगम उच्चतर श्रेणी की प्रचार सामग्री का प्रकाशन करेगा और एक सुयोग्य संस्था द्वारा उसको बेचने की व्यवस्था करेगा। इस निगम ने कुछ ही महीने पूर्व काम करना शुरू किया। इसलिये अभी इसके परिणामों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। चुँकि यह एक दीर्घकालीन योजना है इसलिये अभी इसके वांच्छित परिणाम प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) इस वर्ष के बजट में 36 लाख रुपयों (25 लाख रुपए भारतीय पर्यटन निगम के लिए और 11 लाख रुपये भारतीय ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग के लिए जो इसकी शाखा है) की व्यवस्था की गई है। दूसरे वर्ष के लिए आवश्यक आर्थिक प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

विशाखापट्टणम् पत्तन

738. **श्री कोल्ला वेंकेय्या** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापट्टनम पत्तन में सामान्य माल के घाटों (बर्थ) के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उसमें कोई विलम्ब हुआ है यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) दो सामान्य माल गोदियों के निर्माण से संबंधित कार्य की लागत 77.09 लाख रुपया है जिसमें से 44 लाख रुपये का काम किया जा चुका है जो सम्पूर्ण कार्य 57.1 प्रतिशत है।

(ख) अप्रैल 1964 तक सम्पूर्ण कार्य पूरा हो जाना चाहिये था। देरी का कारण चार गोदियों के निर्माण के लिये लगाये गये ठेकेदारों का धीमा कार्य करना था।

Oil Extraction from Rice Chaff

739. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the Central Food Technological Research Institute, research is being carried out for extracting oil from rice chaff; and

(b) if so, the results of the research made so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes; research on extraction of oil from rice bran has been carried out at the Central Food Technological Research Institute, Mysore.

(b) The results of the experiments carried out, are as follows :

(i) Method of extraction of oil from rice bran has been standardised.

(ii) A pneumatic drier has been designed for the drying and stabilising of rice bran against free fatty acid development.

(iii) An air classifier for removing husk from bran and reducing silica content has also been designed.

सामुदायिक विकास खंड

741. **श्री रा० बरूआ** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया है कि सामुदायिक विकास खंडों को सामाजिक सेवाओं के लिये आवंटित किया गया धन कृषि विकास के लिये प्रयोग किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया जा चुका है कि प्रथम अवस्था सोपान में आनेवाले सामुदायिक विकास खण्डों को 12 लाख रुपये के कुल आयोजन उपबन्ध (स्कीमेटिक प्रोविजन) में से कृषि विकास के लिए रखी गई धनराशि 4.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये कर दी जानी चाहिए। प्रथम अवस्था अथवा द्वितीय अवस्था के खण्डों के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि जिन सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था, संस्थानों की स्थापना और कार्यक्रमों की शुरूवात की जा चुकी है, उन्हें चलाए रखने की पर्याप्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सुविधा कार्यक्रमों की धनराशि तथा खण्ड मुख्यालयों के खर्च में से कृषि विकास के लिए आनुपातिक राशि हस्तांतरित की जानी चाहिए। उत्तर अवस्था 2 के खण्डों को कृषि उत्पादन के लिए अधिक राशि राज्य सरकारों को अपनी निधि में से देनी है।

दिल्ली में खेती

742. **श्री बासप्पा :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि वह खाली पड़ी वह सारी भूमि उसके मालिकों को खेती करने के लिये वापिस दे दे जो उसने बृहद-योजना के अन्तर्गत विकसित करने के लिये अर्जित की थी और जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के पास अर्जित किये जाने के बाद कितनी भूमि बेकार पड़ी है और पुराने मालिकों को कितनी भूमि खेती के लिए लौटाई जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली प्रशासन ने अर्जित की हुई वह भूमि जिसकी उस प्रयोजन के लिये तत्काल आवश्यकता नहीं है जिसके लिये यह अर्जित की गयी थी, रबी की खेती के लिये देने का फैसला किया है। यह भूमि उन व्यक्तियों को दी जायगी जिनके पास वह उसके अर्जन से पूर्व थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली विकास प्राधिकार की लगभग 5000 एकड़ भूमि खेती के लिये दे दी गई है। इसमें से लगभग 50 प्रतिशत भूमि अच्छी खेती योग्य है। इस प्रयोजन के लिये भूमि उप-आयुक्त को सौंप दी गयी थी जिन्होंने 8-11-65 तक लगभग 4735 एकड़ भूमि किसानों को दी। इसमें से केवल 579 एकड़ भूमि में वास्तव में खेती की गयी है।

इस बात का पता लगाया जा रहा है कि भूमि के अर्जन के बाद दिल्ली प्रशासन के पास कितनी भूमि बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई है।

भूमि सर्वेक्षण

743. **श्री मलाइछामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का भूमि-सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब और किस बारे में आरम्भ किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अखिल भारत भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन और राज्य भूमि सर्वेक्षण संगठनों द्वारा काफी समय से भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। वर्तमान सर्वेक्षण केवल बडी नदी खाटी परियोजनाओं के जलाशयों और राज्य सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं द्वारा विकास के लिये प्रस्तावित कुछ क्षेत्रों के बारे में किया जा रहा है। चौथी योजना में भूमि सर्वेक्षण कार्य को गहन कृषि जिला कार्यक्रम क्षेत्रों, गहन कृषि क्षेत्रों और विशेष विकास क्षेत्रों में भी बढाया जायगा।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

744. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961–62, 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में नवम्बर से मार्च, अप्रैल से जुलाई तथा अगस्त से अक्तूबर के महीनों में दिल्ली दुग्ध योजना ने प्रतिदिन औसतन कितने दूध की सप्लाई की थी;

(ख) दिल्ली में अनुमानतः प्रतिदिन कितनी खपत है;

(ग) योजना की क्षमता क्या है; और

(घ) इस वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों में दूध की सप्लाई बढाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटलपर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5159/65।**]

बडनेरा स्टेशन के ऊपर रेल-व-पुल सड़क

745. श्रीमती विमला देशमुख : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि "ट्रंक रूट" नं० 6 का रेल-व-सड़क का पुल जो बडनेरा स्टेशन के ऊपर है यातायात के लिये बहुत छोटा है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये है; और

(ग) क्या पुल को पुनः बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि उससे अधिक यातयात हो सके ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह लोक सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) फिलहाल पुल को पुनः बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अमरावती में से होकर जाने वाली ट्रंक सड़क

746. श्रीमती विमला देशमुख : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरावती नगर में से होकर जाने वाली ट्रंक सड़क का मार्ग बदलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ताकि वह नगर के बाहर से होकर जाये;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार ने प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और प्रस्तावित बाहरी सड़क के संरेखण के लिये सुझाव दिया। इस मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधियों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थान का निरीक्षण कर लेने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जायेगा। उसके बाद निर्माण कार्य की योजनायें और अनुमान तैयार किये जायेंगे।

सहकारी चीनी कारखाने

747. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी चीनी कारखानों से कहा है कि वे अपने उपोत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करें;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत ऐसे आदेश जारी किये जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये ऐसे सहकारी कारखानों को यदि कोई सहायता दी जा रही है तो वह क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जोकि भारत सरकार का एक सांविधिक निगम है, ने इस बारे में राज्य सरकारों को सुझाव दिया है ।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सहकारी चीनी कारखानों की सलाह से उपोत्पाद उद्योगों, जैसे (1) सीरे से पावर ऐल्कोहाल बनाना, (2) चिप बोर्डस/हार्ड बोर्डस बनाना और (3) खोई से कागज़ बनाना, के लिए प्रस्ताव तैयार करें ।

(ग) सहायता का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है । उपोत्पाद उद्योग की पुँजीगत लागत को देखते हुए, सम्बधित राज्य सरकार कारखाने को अंशपुंजी-अंशदान के रूप में सहायता दे सकती है । जहां इस प्रकार का सरकारी अंशदान राज्य की स्वीकृत सहकारी योजना का एक अंग ही है वहां राज्य सरकार अन्तर्ग्रस्त राशि के 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता की हकदार होगी ।

बेलगांव हवाई अड्डा

748. श्री मोहसिन : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगांव हवाई अड्डे को केवल प्रतिरक्षा कार्यों के लिये रिज़र्व रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हुबली में एक असैनिक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि फार्म

749. श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान में और बड़े फार्म स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) इन पर कितना धन व्यय होगा तथा अनाज का अनुमानत: कितना उत्पादन बढ़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बडे कृषि फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस बारे में अन्तिम निर्णय राजस्थान नहर के लिये उपनिवेश नीति के बारे में निर्णय करने के बाद किया जायेगा। इस प्रक्रम परिव्यय और अधिक खाद्य उत्पादन के बारे में कोई अनुमान करना संभव नहीं है ।

Bridge over Ganga at Buxar or Ghazipur

750. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 158 on the 24 thAugust, 1965 and state :

(a) whether Government have explored the possibility of constructing a bridge over Ganga at Buxar or Ghazipur; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). As explained in reply to the Starred Question No. 158 referred to above, in order to facilitate the consideration of suitability of investment for the proposed bridge, the Directorate of Transport Research in the Ministry of Transport were asked to carry out a cost-benefit study of constructing this bridge at either of the two sites suggested for it at Ghazipur and Buxar. The investigations have been completed and necessary information collected. In order to finalise the report, the officers concerned in the Ministry of Transport recently visited Bihar and Uttar Pradesh to have some further discussions with the officers concerned in those States. In the light of those discussions, some further information is awaited from the Government of Uttar Pradesh. The Directorate of Transport Research will finalise their report as soon as the required additional information is received from the Government of Uttar Pradesh and the matter will thereafter be considered further.

Forbesganj-Darbhanga Road in Bihar

751. Shri Yogendra Jha : Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to construct a collateral road linking Forbesganj with Darbhanga in Bihar State;

(b) if so, the site where a bridge is proposed to be constructed over the river Kosi; and

(c) whether this road will be completed within the scheduled time ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). The current progarmme for the development of a lateral road connecting Bareilly in Uttar Pradesh with Amingaon in Assam along the northern border of the country includes the development of the route along Muzaffarpur Begusarai, Purnea and Araria and the construction of the link roads from Muzaffarpur to Darbhanga and from Araria to Forbesganj and on to Maricha. It is proposed to develop a direct route from Darbhanga to Forbesganj only as a second stage work after a detailed survey has been carried out to determine the alignment of this direct route. This survey work is in hand.

The alignment of the portion of the link road between Forbesganj and Maricha has not yet been finalised as it would depend on the site for the proposed bridge over the river Kosi. The bridge site is under investigation and as soon as it is finalised the alignment of the road betwee Fnorbesganj and Maricha/Dagmara will also be finalised. The link road from Araria to Maricha/Dagmara will be completed according to schedule

Border Roads

752. Dr. Ram Manohar Lohia : Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the amounts of grants paid to State Governments during 1964-65 and 1965-66 respectively for the construction of roads along the Rajasthan-Pak and Gujarat-Pak borders;

(b) the particulars of the roads along with their respective mileage for which the above grants were paid and the time by which these roads were scheduled to be completed;

(c) the progress made so far in the construction of these roads;

(d) whether Government of India have decided to take over the work of construction of roads in Jaisalmer and Barmer Districts of Rajashan directly under the supervision of their Ministry; and

(e) if so, when the said decision was taken and the progress made in the work so far?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The amounts of grants *paid* to State Governments during 1964-65 for the construction of roads along the Rajasthan-Pak and Gujarat-Pak borders are as under :

Name of State	Grant paid during 1964-65
	Rs.
Gujarat	1,00,000
Rajasthan	1,00,000

No. payments have yet been made for the year 1965-66.

(b) and (c): It is not in the public interest to disclose the information.

(d) and (e): The matter is under the consideration of the Government of India.

भारतीय बाल कल्याण परिषद्

753. श्री जं० ब० सिं० विष्ट : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने, सरकार को पहले सूचित करके, अपने बालसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि से वित्तीय सहायता मांगी थी;

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम के लिए पहले ही सहायता दे चुकी थी और उसने परिषद् द्वारा इस दोहरी सहायता मांगने पर आपत्ति की है; और

(ग) क्या परिषद् के दो पदाधिकारियों ने मांगी गई सहायता के बारे में विभिन्न बयान दिये हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग मे उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने अपने मौजूदा बालसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि को एक नोट भेजा था जिसमें वे बातें भी बतायी गयी थी जिन पर 'युनिसेफ' सहायता कर सकता है।

(ख) सरकार इस कार्यक्रम के लिये पहले से ही वित्तीय सहायता दे रही है और इस बारे में सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37

754. श्री रा० बरुआ : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसकी कोई गणना की गई है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 पर कितना यातायात होता है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या बागा-राह 129/5 एफ० से काकोडोंगा 179/5 एफ० तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 को चौड़ा तथा सुदृढ़ बनाने के अनुमान के लिये वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) क्या इस सड़क पर काकोडोंगा पुल के वर्षा से पहले बन कर पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

1963 में राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 37 के कुछ विशिष्ट स्थानों पर यातायात-गणना की गई थी और मील 107 पर प्रतिदिन 1077 टन और मील 82 पर प्रतिदिन 3386 टन आवागमन पाया गया।

(ख) मील 129/5 पर बगरई और मील 179/5 पर काकोडोंगा के बीच के सड़क के भाग को चौडा करने और मजबूत करने के प्राक्कलन की जांच की जा रही है और शीघ्र ही निश्चित किया जाएगा।

(ग) काकोडोंगा पर नये पुल के अगस्त 1966 तक पूरा हो जाने की आशा है। आगामी वर्षाऋतु से पूर्व ही इसके यातायात के योग्य बन जाने की संभावना है।

उर्वरक का प्रयोग

755. श्री रामपुरे :
श्री कनकसबै :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जो यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों को दिए गए उर्वरक किसानों को निश्चत मूल्यों पर दिये जाते है तथा कोई बिचौलिया मुनाफा नहीं लेता; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : निम्नलिखित नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक भारत में केवल केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा खरीदे जाते हैं और केवल वह ही इसका आयात करता है :

1. सल्फेट ऑफ अमोनिया।
2. उरिया।
3. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट।
4. कैल्शिलम अमोनियम नाइट्रेट।

ये नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक राज्य सरकारों को माल भेजने वाले स्टेशन पर रेल-पर्यन्त-निशुल्क समान दरों पर दिये जाते हैं, इसका भाडा रेल चलने के स्थान तक भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जिनको उर्वरक दिये जाते हैं वे इसको किसानों को बेचते समय उर्वरक की किस्म पर निर्भर करते हुए 'पूल मूल्य' में निश्चित वितरण लाभ जमा कर सकते हैं। इस वितरण लाभ में राज्य सरकार द्वारा किया गया प्रशासनिक व्यय, निकट तम रेल्वे स्टेशन से परिवहन शुल्क, ब्याज, विभिन्न स्तरों पर अधिकृत व्यापारियों को कमीशन आदि शामिल है। इस प्रकार किसानों से लिये जाने वाले मूल्य भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिये जाते हैं। राज्य सरकारों इन मूल्यों का स्थानिय भाषाओं में भी व्यापक प्रचार करती है।

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 के अधीन राज्य सरकारों को उन व्यापारियों के विरूद्ध, जो अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य ले, कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं। अपराधियों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत दण्ड दिया जायगा।

केन्द्रीय पूल द्वारा अमोनियम फोसफेट और अमोनियम क्लोराइड़ का भी आयात किया जा रहा है और निश्चित 'पूल मूल्य' पर उसका वितरण किया जा रहा है ताकि इन उर्वरकों को भारत में इनके उत्पादन के लिये कारखाने स्थापित किये जाने से पूर्व लोकप्रिय बनाया जा सके और इनके लिये एक मंडी बनायी जा सके। जिन राज्य सरकारों को ये उर्वरक दिये गये हैं उनको इससे निश्चित वितरण लाभ जोड कर ये उर्वरक बेचने को कहा गया है। इन दो उर्वरकों की थोडी सी मात्रा का भारत स्थित कारखानों में भी उत्पादन किया जा रहा है। वे इनको अपने वितरकों द्वारा सीधे अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित कारखाना-मूल्य पर राज्य सरकारों को बेचते हैं। इन उर्वरकों के किसान मूल्यों पर कानूनी रूप से नियंत्रण नहीं किया गया है क्योंकि इन के मूल्य समान नहीं होते और क्योंकि इन उर्वरकों के देशीय उत्पादकों को मुक्त बाजार में माल बेचने की अनुमति होती है।

फोसफेट युक्त उर्वरक और पोटासयुक्त उर्वरक का निर्माताओं/आयातकों द्वारा सीधे अथवा राज्य सरकारों के अधिकरणों के जरिये वितरण किया जाता है। तथापि, इन उर्वरकों के कारखाना/जेटी/गोदाम मूल्य सरकार द्वारा बातचीत के बाद निर्धारित किये गये है।

थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी जैसे बिचौलिये, जो अधिकांश सहकारी समितियां हैं, उर्वरकों के वितरण के लिये अत्यावश्यक हैं और उनको अपने खर्चे पूरे करने और विनियोजन पर उचित लाभ के लिये पर्याप्त कमीशन देना होता है।

हल्दानी में भाण्डागार

756. श्री कृ० चं० पन्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हल्दानी में, निकटस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनाज जमा करने के लिए एक भाण्डागार बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भाण्डागार का निर्माण कब तक हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों का फालतू भण्डार बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में अनाज के बारे में बार-बार होने वाली कठिनाई को दूर किया जाये?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्थानीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये उचित केन्द्रों पर खाद्यान्नों का समीकरण भंडार बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि केन्द्रीय सरकार अपने पास खाद्यान्नों के उपलब्ध स्टाक से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन करती है।

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय स्थान

757. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय स्थानों को आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्वतीय स्थानों पर निवास स्थान अपर्याप्त तथा महंगे है।

(ग) क्या उपर्युक्त पहाड़ी सैरगाहों में सरकार का विचार उचित व्यय वाले मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिये होटले बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं; तो क्या पर्यटन विभाग का विचार ऐसे गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओं को ऋण देने का है जो मध्यमवर्ग के पर्यटकों के लिये होटल बनाने के इच्छुक है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। होटलों के स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता औद्योगिक वित्त निगम और या राज्य वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध है।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के शेडों में गेहूं का सड़ना

758. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1965 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" (कलकत्ता) में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एक हजार टन गेहूं कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के दो शेडों में पड़ा सड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, हां। बुहारन से एकत्रित लगभग 30 मीट्रिक टन गेहूं 379 बोरियां कुछ समय के लिये कलकत्ता बन्दरगाह के शेडों में पड़ा रहा था। यह बुहारन माल हालदिया बन्दरगाह से नावों पर लाये गए गेहूं की विभिन्न प्रेषणों से गिरा था। यहां कलकत्ता पहुंचने से पहले जहाज से बोझा उतारा जाता है क्योंकि पत्तन आयुक्तों ने यह जानने में काफी समय लगाया कि ये माल किस प्रेषण

विशेष का है, इसलिये बुहारन माल की सुपुर्दगी नहीं दी गयी थी। किराया दायित्व निर्धारण करने के प्रश्न पर भी कुछ समय लगा। इन मात्राओं की सुपुर्दगी ले ली गयी थी और खाद्य विभाग के तकनीकी अधिकारियों ने इस स्टाक की जांच-पडताल की। सामान्य सुधार के बाद ये स्टाक मानव उपभोग के योग्य और निर्गम के लिए घोषित किया गया है। इस स्टाक को साफ करने और सुधारने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद ये स्टाक दिया जाएगा।

लापता भारतीय जहाज

759. **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई से फारस की खाड़ी के बसरा पत्तन को एक महीना पहले गये पांच भारतीय जहाजों में से चार अभी तक लापता हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो वे कहां तथा किस स्थिति में पाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : बंबई से फारस की खाड़ी के पत्तनों के लिये जो भारतीय जहाज गये थे उनमें से किसी के भी लापता होने की सूचना नहीं मिली है। किन्तु सौराष्ट्र पत्तनों से जो जहाज गये थे उनमें से पांच जहाजों के लापता होने की सूचना मिली है। इनमें से दो का कुवैत में पता चला है जहां वे खजूर लाद रहे हैं और दो कराची में पाये गये हैं जहां उन्हे पाकिस्तान ने रोक लिया है। एक जहाज अभी भी लापता है और उसकी खोज की जा रही है।

लघु सिंचाई योजनायें

760. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने शीघ्र फल देने वाली लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए हैं तथा कौनसी योजनायें आरम्भ की है;

(ख) सरकार ने इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी राशि मंजूर की है;

(ग) इन अनुदानों की क्या शर्तें है; और

(घ) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप खाद्य-उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत सरकार तीसरी पंच-वर्षीय योजना में देश के छोटे सिंचाई साधनों के तेजी से विकास पर बड़ा जोर दे रही है। अक्तूबर, 1962 में आपातकाल की उद्घोषणा के फलस्वरूप, छोटी सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण पडताल और क्रियान्विति में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और इस गति को बनाये रखने के लिए समय समय पर राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता दी गयी है। टैंकों के नवीकरण, मौजूदा कुओं को खोदनें और गहरा करने, नलकूप बनाने, नदियों और झरनों आदि से लिफ्ट सिंचाई

आदि की योजनाओं के बारे में जिनसे सस्ती और निश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, कार्यक्रम को बढाने में प्राथमिकता दी जा रही है। छोटे सिंचाई कार्यों की क्रियान्विति और संधारण के तकनीकी स्तर को सुधारने के लिये तकनीकी संगठन को सुदृढ करने, छोटे कार्यों के लिये उपयुक्त विशेष डिजाइन बनाने के बारे में विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

1964 तक कच्चे कुओं, कच्चे कुओं को खोदने और गहरा करने और टैंकों के नवीकरण की योजनाओं पर 25 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती थी और कुहलों पर 50 प्रतिशत की राज-सहायता दी जाती थी और इस राज-सहायता को केन्द्र और राज्य बराबर बराबर वहन करते थे। लिफ्ट सिंचाई योजनाओं जैसे नलकूप और पम्प-सेट को प्रोत्साहित करने के लिये मार्च, 1965 में यह निर्णय किया गया कि इन योजनाओं के लिये भी 25 प्रतिशत राज-सहायता दी जाय जिसको केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर बराबर वहन करेंगे। सामुदायिक पक्के कुओं को भी अगले वित्तीय वर्ष 1966-67 से 50 प्रतिशत राज-सहायता दी जायगी जिसको केंद्र और राज्य बराबर बराबर वहन करेंगे।

हाल में नदियों और झरनों पर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाने के लिये एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। लिफ्ट सिंचाई की राज्य योजनाओं को भी 1966-67 से 12 1/2 प्रतिशत केन्द्रीय राज-सहायता दी जायगी। पम्प-सेटों और नलकूपों के विद्युतीकरण के क्षेत्र में एक विशेष आन्दोलन आरम्भ किया गया है। राज्य विद्युत बोर्डों को उन क्षेत्रों में, जहां नलकूप और पम्प-सेट योजनाओं की काफी गुंजायश है, बिजली की लाइनें बढाने के लिये अतिरिक्त धन दिया जा रहा है ताकि वे बिजली से चलाये जा सकें। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय अगले वर्ष 1.4 लाख अतिरिक्त पम्प-सेटों का विद्युतीकरण करने की योजना बना रहा है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें छोटी सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना का परिव्यय, 1961-64 के दौरान वास्तविक व्यय, 1964-65 में प्रत्याशित व्यय और 1965-66 में आवंटनों (अतिरिक्त आवंटन समेत) के बारे में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5160/65।]**

(ग) राज्यों को सूचित कर दिया गया है कि छोटी सिंचाई कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता पृथक से रखी गयी है और वह अन्य कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिये नहीं है। यदि इस कार्यक्रम के लिये कुल पुनरीक्षित परिव्यय, जो समय समय पर सहमत परिव्यय को शामिल करके बनता है, खर्च नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सहायता की मात्रा कुल पुनरिक्षित परिव्यय की तुलना में किये गये वास्तविक परिव्यय में कमी के अनुपात में कम कर दिया जायेगा।

(घ) यह प्रत्याशा है कि छोटी सिंचाई योजनाओं से 128 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने के तीसरी योजना के लक्ष्य से ज्यादा पूरा हो जायगा जिसमें से अनुमान है लगभग 80 प्रतिशत भूमि में खाद्यान्न का उत्पादन होगा। क्योंकि खेती मिली जुली होती है अतः यह अनुमान लगाना कठिन है कि उत्पादन के किसी एक पहलू के इस्तेमाल से खाद्यान्न के उत्पादन में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है। तथापि मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि छोटी सिंचाई योजना से लाभान्वित हर अतिरिक्त एकड़ भूमि में औसतन लगभग 1/5 टन प्रति एकड़ अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होता है।

दिल्ली-नागपुर विमान सेवा

762. **श्री दे० शि० पाटिल:** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और नागपुर के बीच विमान सेवा बन्द कर देने के क्या कारण है; और

(ख) औरंगाबाद होकर बम्बई और नागपुर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने के क्या कारण है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) रात्रिकालीन वायु-डाक सेवा दिल्ली और नागपुर के बीच अभी भी चल रही है लेकिन वह डकोटा विमानों द्वारा चलाई जा रही है और उसमें यात्री नहीं ले जाये जाते। रात्रि वायु-डाक सेवा को वाइकाउण्ट विमानों द्वारा चलाना निम्न-लिखित कारणों से बन्द कर दिया गया :—

(i) रात्रि वायु-डाक सेवा से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ही कम थी।

(ii) रात्रिकालीन वायु-डाक सेवा पर डकोटा विमानों को चलाना पड़ा ताकि चालक रात्रिकालीन विमान चालन का अनुभव प्राप्त कर सके जिससे डकोटा विमानों पर कमांड इन्डोर्समेन्ट के लिये योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इस सुविधा के बिना पायलटों को डकोटा कमाण्ड इन्डोर्समेन्ट के लिए प्रशिक्षण देने में काफी देरी लग जायेगी और इसका देश में विमान परिचालनों पर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, पर्यटन विभाग की प्रार्थना पर, बम्बई से औरंगाबाद तक एक डकोटा विमान सेवा चला रहा था और यह सेवा, महाराष्ट्र सरकार से शार्ट-फाल गारंटी के अन्तर्गत नागपुर तक बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने बम्बई-औरंगाबाद मार्ग के लिये नागर विमानन विकास निधि से आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय राजपथ का नेफा तक बढ़ाना

763. श्री रिशांग किशिंग : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार आसाम में तेजपुर-उत्तर लखीमपुर होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ को नेफा के पांच जिलों तक बढाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर होकर जो सड़क जाती है वह उत्तरी ट्रंक सड़क का एक भाग है जो आसाम में एक राज्य सड़क है और राष्ट्रीय मुख्यमार्ग नहीं है। इसकी आखरी हद मुरगोनसेलेक है। अतः राष्ट्रीय मुख्यमार्ग का नेफा तक बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है।

नेफा में सड़कें

764. श्री रिशांग किशिंग : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार नेफा के सभी डिवीजनल हैडक्वार्टरों के बीच अनेक पार्श्व सड़कों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : नेफा में नई सड़कों के निर्माण के लिये और मौजूदा सड़कों और रास्तों में सुधार के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में 180 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। तीसरी पंच वर्षीय योजना में निम्न बातों पर जोर दिया गया है: (1) विभागीय हेडक्वार्टरों को मिलानेवाली सड़कों का निर्माण, (2) पुलों और पुलियों का निर्माण, (3) मोटरवाली सड़कों पर रोड़ी डालना और सतह को काला करना, और (4) आराम घरों और अन्य वैसी ही सड़क के किनारे की इमारतों का निर्माण।

आसाम के राजपाल को नेफा में सड़क के निर्माण कार्य के लिये 15 लाख रुपये की लागत के पृथक कार्य के लिये प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति देने का अधिकार दे दिया गया है, अतः योजना के अन्तर्गत अधिकांश निर्माण कार्यों को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। दी जा रही है।

भारतीय बाल कल्याण परिषद्

765. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में, प्रत्येक वर्ष में पृथक्-पृथक् भारतीय बाल कल्याण परिषद् को बाल कल्याण कार्यों के लिये कितनी रकम आवंटित की थी;

(ख) भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा कितनी संस्थायें चलाई जाती हैं और प्रत्येक संस्था पर कितना कितना खर्च किया जाता है;

(ग) क्या इन संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा प्रति वर्ष की जाति है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में सड़क विकास योजनायें

766. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य सरकार को राज्य में सड़क विकास योजना के लिए 1965–66 में क्या और कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए उस राज्य की वास्तविक मांग क्या थी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के अलावा जो केन्द्रिय दायित्व है, राज्य को आर्थिक या अन्तर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों के और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता दी हुई सड़कों के विकास और निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

उड़ीसा की राज्य सरकार की मांग और 1965–66 में विभिन्न प्रकार की सड़कों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस राशि की व्यवस्था की गई है वह नीचे दी जाती है :—

(रु० लाख में)

सड़कों का वर्गीकरण	1965–66 के लिये राज्य सरकार की मांग	1965–66 के लिये राशि की व्यवस्था
राष्ट्रीय मुख्य मार्ग . .	323.44	268.46
आर्थिक या अन्तर्राज्य महत्व की राज्य सड़कें	6.32	2.65
केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा सहायता की गई सड़कें	26.89	19.78
योग	356.65	290.89

"बायॉ-गैस प्लांट"

767. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बायॉ गैस प्लांट" के बारे में अनुसंधान कार्य करने के लिए 1965-66 में अब तक देश में कुल कितने अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हे; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : नया केन्द्र 1965 में स्थापित किया गया था। तथापि, देश में "बायॉ गैस प्लांट" के बारे में समस्याओं पर निम्नलिखित छः केन्द्र कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं :—

1. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ।
2. लोक स्वास्थ अनुसंधान संस्था, नागपुर ।
3. गोबार गैस अनुसंधान केंन्द्र, अजीतमल ।
4. एन० आर० डी० सी० अनुसंधान गैस संयंत्र, कानपुर और बम्बई ।
5. कोरा ग्राम उद्योग केन्द्र, बम्बई ।
6. वेल्लूर मट, कलकत्ता ।

उड़ीसा में बनाई गई खादी

768. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक उड़ीसा में कितनी खादी बनाई गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अब तक इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : सूचना प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्थानीय विकास कार्य

769. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 23 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में स्थानीय विकास कार्यों के लिए राज्यवार राशि नियत करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में इसी प्रयोजन के लिए उड़ीसा को कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : वर्ष 1965-66 के बजट प्राक्कलनों में स्थानीय विकास कार्यों के लिए रखी गई 316.00 लाख रुपये की सम्पूर्ण राशि इस बीच राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को नियत कर दी

गई है। उड़ीसा को 18.00 लाख रुपए की राशि नियत की गई है। प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र को नियत की गई राशि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–5161/65।]**

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

Alleged firing by police on the labourers of a brick kiln in Delhi on the 15th November, 1965, resulting in injuries to two labourers.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : यदि आप अनुमति दें तो मैं इस के बारे में कल शाम को एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा। मुझे तथ्य प्राप्त हो रहे है और यदि आप चाहें तो मैं इस समय घटना के बारे में संक्षेप में बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय कल विस्तृत वक्तव्य देना चाहते है वह कल दे सकते हैं।

सभा-पटल रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत भारतीय विमान (पांचवां संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1426 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–5150/65।]**

केरल पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :–

(एक) अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 266/65 जो दिनांक 29 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (आयोजना तथा प्राक्कलन) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 308/65 जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल पंचायत (लेखे) नियम, 1965 दिये गये है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–5151/65।]**

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION RE : INTERNATIONAL SITUATION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 15 नवम्बर, 1965 को श्री स्वर्णसिंह द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाए ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस प्रस्ताव पर विचार करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर विचार के लिये समय बढ़ाया जायेगा तथा इस प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री कब बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री शायद आज साढ़ेचार बजे बोलेंगे और वैदेशिक कार्य मंत्री कल वादविवाद का उत्तर देंगे ।

श्री बाकरअली मिर्जा (वारंगल) : अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने हमारी विदेश नीति में पुनर्विचार करने के बारे में विचार व्यक्त किये हैं । उनके इन विचारों से स्पष्ट है कि वे गुटनिर्पेक्षता की नीति का परित्याग कर किसी गुट में शामिल होना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि अब गुटनिर्पेक्षता की नीति छोड़ने का समय नहीं है । आज फ्रांस तथा ब्रिटेन जैसे गुटों वाले राष्ट्र गुटनिर्पेक्षता की नीति अपनाने की बात सोच रहे हैं । आज एक गुट वाले देश रूस और चीन के बीच में मतभेद पैदा हो गया है । विश्व के देशों की स्थिति को देखते हुए हमें किसी गुट में रह कर किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है । हमारी गुटनिर्पेक्षता की नीति देश के लिये काफी लाभदायक साबित हुई । इससे हमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिली है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस नीति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान को गुट में रहने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । यह ठीक है कि अमरीका ने पाकिस्तान को सेबर जेट बिमान, पैटन टैंक तथा अन्य हथियार दिये किन्तु अमरीका पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सका । पाकिस्तान दूसरों पर निर्भर रहने के कारण आत्मविश्वास खो बैठा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की विदेश की नीति को गलत बताते हुए कहा है कि कोई भी देश हमारा मित्र नहीं रहा है । इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज विश्व में कोई भी देश स्पष्ट रूप से किसी झगड़े में जानबूझ कर नहीं पड़ना चाहता है । हम देख चुके हैं कि गुटों में रहने के बावजूद भी स्वेज नहर के मामले में ब्रिटेन का किसी ने साथ नहीं दिया । वियतनाम के मामले में फ्रांस अमरीका का खुले तौर पर विरोध कर रहा है और ब्रिटेन इस मामले से बचने की कोशिश कर रहा है । अब संसार के देश हमारी गुट निर्पेक्षता की नीति को अच्छी तरह समझने लगे हैं । यदि हमारा कोई है ही नहीं तो सुरक्षा परिषद् ने हमारे पक्ष में संकल्प कैसे पारित कर दिया ? सुरक्षा परिषद् में कोई भी देश पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सका । मित्रता तो हमारे द्वारा अपनाये गये रवैये पर निर्भर करती है न कि किसी गुट में शामिल होने पर ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें अपने मित्र बनाने चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा देश एक विशाल देश है । अतः हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए ताकि दूसरे देश हमारे मित्र बनने का प्रयत्न करें । इससे हमारे देश का महत्व बढ़ेगा ।

रोडेशिया के मामले में सही नीति अपनाई है । वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा अफ्रीकी-एशियाई संगठन का समर्थन करने के लिये दिया गया वचन सराहनीय है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की आलोचना की है । इंग्लैंड ने इयान स्मिथ को पहले सूचित कर दिया था कि रोडेशिया द्वारा एकपक्षीय घोषणा किये जाने पर वह रोडेशिया में बलप्रयोग नहीं करेगा । इस प्रकार

[श्री बाकरअली मिर्जा]

पहले दी गई सूचना के परिणामस्वरूप इयान स्मिथ को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये उत्साह मिला। ब्रिटेन द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय करना संसार के देशों की आंखों में धूल डालने की बात है। जब अदन तथा ब्रिटिश गिनी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है तो वैसी ही कार्यवाही रोडेशिया के विरुद्ध क्यों नहीं की जानी चाहिए। जब सारे संसार के यहूदियों को इकट्ठा करके इजराइल में रखा गया है तो रोडेशिया के चन्द गोरे लोगों को उनकी मातृभूमि वापिस क्यों नहीं भेजा जाता। उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना ही काफी नहीं हैं। कुछ देश इसके बावजूद भी उससे आर्थिक सम्बन्ध पूर्ववत बनाये हुए है--यहां तक कि इंग्लैंड, जो आर्थिक प्रतिबन्ध का समर्थक है, रोडेशिया को भेजे जाने वाले तेल को प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिये तैयार नहीं है। मैं रोडेशिया के मामले में भारत के रवैये का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

अब मैं विदेशों में प्रचार के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि भारत की अपेक्षा पाकिस्तान की विदेश में प्रचार की व्यवस्था अधिक प्रबल है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के गुट वाले देश, विशेष रूप से इंग्लैंड बी० बी० सी० द्वारा, पाकिस्तान के पक्ष में बहुत अधिक प्रचार करते हैं। विदेशों में हमारे दूतावास उपलब्ध अपने सीमित साधनों से सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे पास इस समय शक्तिशाली कुछ ट्रान्समिटरों की कमी है जो भविष्य में पूरी होने वाली है। जिससे हमारी प्रसारण व्यवस्था काफी अच्छी हो जायेगी और हमारे कार्यक्रम सुदूर स्थानों पर सुने जा सकेंगे। हमारी वर्तमान प्रचार व्यवस्था काफी संतोषजनक है। अतः इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

हमें सदा निश्चित दृढ़ रवैया अपनाना चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि काश्मीर के सम्बन्ध में हमने निश्चित, स्पष्ट तथा दृढ़ रवैया अपनाया। हमारे रवैया का प्रायः सभी देशों में अनकूल प्रतिक्रिया हुअी। स्वर्गीय नेहरू एशिया में शान्ति चाहते थे। इसी लिये वे पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। इसका अर्थ पाकिस्तान तथा अन्य देशों ने कुछ गलत लगाया जिससे काश्मीर की समस्या अभी तक बनी रही। जब हम यह कह चुके हैं कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके बारे में हम किसी प्रकार की बात करने के लिये तैयार नहीं है, तो अन्य देश अब हमारी बात अच्छी तरह समझ कर हमारा समर्थन करने लगे हैं। हमें हमेशा शान्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें युद्ध मनोवृत्ति को उभारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि पाकिस्तान समझौते की बातचीत करना चाहता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इसके साथ साथ देश की अखंडता के लिये हमें अपने रवैये पर डटा रहना चाहिए।

श्री फ्रैंक अन्थनी (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, आज हमें यहां पर अपने वीर योद्धा जवानों में अपना विश्वास व्यक्त करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। चीनी आक्रमण के समय कुछ हमें त्रुटियों के समय नेफा में जो हार सहन करनी पड़ी थी उसे हमारे जवानों ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में अपनी वीरता दिखा कर धो दिया है। इसके अतिरिक्त आज हमारे जवानों ने युद्ध क्षेत्र में तथा देश की जनता ने हमारी धर्मनिर्पेक्षता का विश्व में मस्तक उंचा कर दिखाया है। अब हमारे लिये यह आवश्यक है कि भविष्य में भी हम इसी नीति पर चल कर अपनी अखंडता बनाये रखें। हाल के संकट में हमने जिन परिस्थितियों का सामना किया और जिस ढंग से शौर्य और एकता का परिचय दिया है उन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। हम में किसी प्रकार की आत्मतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आज तक हम व्यावहारिक और यथार्थवादी नीति पर नहीं चलते थे। चीनी आक्रमण तथा बाद में पाकिस्तानी आक्रमण हमारे लिये वरदान सिद्ध हुई क्योंकि इनसे हमारी आखें खुल गई और हम

यथार्थवाद को समझने लगे हैं। आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के दबावों का सामना करना है। यह ठीक है कि हम भावुक तथा संवेदनशील हैं। किन्तु हमें अपने रवैये का निर्धारण निष्पक्ष रूप से करना चाहिए और उस पर सदा दृढ़ रहना चाहिए।

अब मैं हाल के संघर्ष में भारत के प्रति ब्रिटेन के रवैये के बारे में कुछ कहूंगा। ब्रिटेन ने भारत के प्रति जो दुरंगी उपनिवेशवादी नीति का प्रदर्शन किया है वह अत्यन्त निन्दनीय है। पाकिस्तान ने भारत के प्रति जो हठधर्मी दिखाई है उसका कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई पाकिस्तान को इसके लिये उत्साहित वाली नीति है। ब्रिटेन का प्रभुत्व प्रायः समाप्त हो गया है और इसी लिये वह इस प्रकार की नीति अपना कर पड़ौसी देशों में अशान्ति बनाये रखना चाहता है। ब्रिटेन के प्रति हमारी नाराजगी चाहे कितनी ही उचित क्यों न हो, किन्तु यदि इस नाराजगी की मनोवृत्ति से हम राष्ट्र मंडल छोड़ देंगे, तो हमारी यह कार्यवाही राजनीतिज्ञता तथा परिपक्वता के अभाव का द्योतक होगी। भारत की मूल नीति अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावकारी कार्य करने की होनी चाहिए ताकि हम उसमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकें। जहां तक राष्ट्र मंडल छोड़ने का सम्बन्ध है, हमें ब्रिटेन के रवैये के कारण उसे नहीं छोड़ना चाहिए। राष्ट्र मंडल केवल ब्रिटेन ही नहीं है और न ही वह अधिकांशतः श्वेत लोगों का है। राष्ट्रमंडल के 22 सदस्य देशों में से 14 अश्वेत हैं जिनमें से 9 अफ्रीकी तथा 5 एशियाई देश हैं। अब भारत का उद्देश्य यह होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल की नीतियों और रवैये में परिवर्तन किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि राष्ट्रमंडल के अश्वेत सदस्य देश राष्ट्रमंडल के रवैये और नीतियों के निर्धारण में मुख्य भाग लें। राष्ट्रमंडल विभिन्न सदस्य देशों में होना चाहिए और उसकी अध्यक्षता पारी पारी से सदस्य देशों द्वारा की जानी चाहिए। कनाडा इसके लिये पहले ही सुझाव दे चुका है। भारत यह सुनिश्चित करने में भाग ले सकता है कि राष्ट्रमंडल के अफ्रीकी तथा एशियाई सदस्य देश एक प्रबल शक्ति बनकर ब्रिटेन को रोडेशिया के सम्बन्ध में अपने बचनों से पीछे हटने से रोकें।

ब्रिटेन आत्मनिर्णय और मध्य युग की तानाशाही का नाप लेकर पाकिस्तान के समर्थन में शरारतपूर्ण अधिवक्ता का कार्य कर रहा है। हमें ब्रिटेन को स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहिए कि पहले वह रोडेशिया तथा अदन में आत्मनिर्णय कराये, तब कहीं वह दूसरों से आत्मनिणय की बात करे। ब्रिटेन को पख्तूनिस्तान में आत्मनिर्णय की बात का समर्थन करना चाहिए। ब्रिटेन को कहा जाए कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को न्यूनतम मानवीय अधिकार तो दे। आज पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार कर रहा है वह न केवल ब्रिटेन को ही अपितु समस्त संसार को मालूम है।

अब मैं अमरीका के साथ भारत के सम्बन्धों के विषय में कहूंगा। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत के प्रति अमरीका का रवैया निराशाजनक रहा। अमरीका भारत को एक भिखारी की दृष्टि से देखता है और हम पर राजनैतिक दबाव डालना चाहता है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रत्येक विकासोन्मुख देश के लिए अपने देश के विकास में विदेशों से सहायता लेना अनिवार्य होता है। यहां तक कि ब्रिटेन जैसा देश भी बहुत कुछ अमरीका पर निर्भर रहता है, किन्तु अमरीका ब्रिटेन और भारत को रंग-भेद की दृष्टि से सहायता देता है। अतः हमें कम से कम अन्य देशों की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए।

अमरीका को यह महसूस करना चाहिए कि एशिया में साम्यवाद के फैलाव को रोकने की इच्छा से उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से इस उपमहाद्वीप का संतुलन बिगड़ गया है। अमरीका इस बात का दावा करता है कि उसने चीन के साम्यवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए थे किन्तु पाकिस्तान ने उनमें से एक भी हथियार साम्यवाद के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया। इसके विपरीत इन हथियारों का भारत के विरुद्ध प्रयोग किया गया। इस प्रकार अमरीका ने पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को बनावटी रूप से बहुत बढ़ा कर उसे सैनिक लालसा, धार्मिक घृणा और मतान्धता का शिकार बना दिया। अमरीका को यह भी महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे धर्म-निरपेक्षता के आधार को दुर्बल बनाना चाहता है।

[श्री फ्रैंक अन्थनी]

आज पाकिस्तान चीन के साथ साठ-गांठ कर रहा है। ये दोनों ही देश लोकतन्त्र के विरोधी हैं। अमरीका तथा ब्रिटेन चाहे जो कार्रवाई करें किन्तु वे चीन तथा पाकिस्तान की बढ़ती हुई साठ-गांठ को नहीं रोक सकते। चीन तथा पाकिस्तान भारत की अर्थ व्यवस्था तथा लोकतन्त्र की जड़ को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अत: वे कभी न कभी भारत पर आक्रमण करेंगे, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चाहे अमरीका का यह इरादा भले ही न हो किन्तु वह पाकिस्तान को भारत में लोकतन्त्र की जड़ को कमजोर करने तथा उसे समाप्त करने के लिए सहायता दे रहा है।

जहां तक रूस तथा अन्य पूर्व योरोपीय साम्यवादी देशों का सम्बन्ध है वे हमें चीन की विस्तारवादी नीति का सामना करने के लिए भी सहायता देने के लिए तैयार हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इन साम्यवादी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ होते जा रहे हैं। इसके विपरीत पश्चिमी राष्ट्र हमें सहायता देने से मना कर रहे हैं।

काश्मीर के बारे में किसी प्रकार के समझौते की बातचीत करना भारत के लिए खतरनाक है। इससे उन देशों को, जो भारत विरोधी हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को नीचा दिखाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि काश्मीर का कानूनी ढंग से भारत में विलय न हुआ हो। पाकिस्तान ने काश्मीर पर दो बार आक्रमण किया और भारत के वीर जवानों ने अपना रक्त देकर इसकी रक्षा की। इससे काश्मीर भारत की सम्पूर्ण जनता के लिए अत्यन्त प्रिय स्थान बन गया है। काश्मीर हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र, विशेषकर अल्पसंख्यकों का प्रतीक बन गया है। मैं समझता हूं कि चीन और पाकिस्तान काश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारी धर्मनिरपेक्षता की जड़ कमजोर होती है। अत: हमें एक होकर के उनका सामना करना है तथा अपनी धर्मनिरपेक्षता की जड़ को मजबूत बनाना है।

श्री महताब (अंगुल) : जब भी इस सदन में विदेश नीति पर चर्चा हुई विभिन्न दलों के सदस्यों ने विदेश नीति का पुनरीक्षण करने की मांग की। आज की चर्चा के दौरान भी इसमें परिवर्तन करने की मांग की गई है। हमारी विदेश नीति की मुख्य बात यह है कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहनशीलता तथा गुटनिरपक्षता के अनुयायी हैं। अब समय आ गया है कि हम इस बात का पता लगायें कि वर्तमान संघर्ष हमें अपनी विदेश नीति से कहाँ तक लाभ हुआ है।

काश्मीर पर हमेशा ही पश्चिमी देशों तथा रूस की दृष्टि रही। प्रथम महा युद्ध के बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने काश्मीर के तत्कालीन सरकार को चेतावनी दी थी कि रूस को काश्मीर में प्रचार करने की अनुमति न दी जाये।

अंग्रेजों की भारत की स्वाधीनता के पश्चात सदैव यही इच्छा रही कि काश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाए क्योंकि इसमें उनकी स्वार्थ सिद्धि थी, किन्तु दूरदर्शी भारतीय कूटनीति के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ नहीं। अन्ततोगत्वा, काश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया। परन्तु पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला कर दिया परिणामस्वरूप यह मामला राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया जहां वह अब तक लटका हुआ है। स्वाधीनता के पश्चात सरकार ने स्पष्टत: यह बात कही है कि काश्मीर के प्रश्न पर किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं हो सकती और यह मामला हमेशा के लिए हल हो गया है। भारत सरकार की यह एक महान सफलता है। इस सम्बन्ध में हमारी गुट-निर्पेक्ष नीति ने हमें पूर्णत: लाभ पहुंचाया है।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान युद्ध हुआ है उसके लिए नैतिक रूप से अमरीका उत्तरदायी है क्योंकि उसने भारत पर यकीन न करके पाकिस्तान को साम्यवादी देशों के विरुद्ध सैनिक सहायता दी जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच गत युद्धोपरान्त का शक्ति-संतुलन बिगड़ गया। उनकी धारणा यह थी कि पाकिस्तान को केवल किसी तत्काल संघर्ष के लिए ही नहीं अपितु उसे तीसरे

विश्व-युद्ध के लिए भी जिसमें नाभिकीय हथियारों का प्रयोग होगा, तैयार किया जा सकता है। वे इस बात को जानते थे कि इन हथियारों को भारत के विरुद्ध भी काम में लाया जा सकता है।

जहां तक काश्मीर तथा वर्तमान संघर्ष का सम्बन्ध है, भारत द्वारा अपनायी गई विदेशी नीति पूर्णतः सफल रही है और उससे हमें लाभ पहुंचा है।

श्री मसानी ने, जो राजनीति तथा राजनयिकता के प्रकांड विद्वान हैं, एक यह सुझाव दिया है कि भारत ने जापान तथा आस्ट्रेलिया जैसे अपने पड़ौसी देशों से सैनिक समझौता कर लेना चाहिए। किन्तु ऐसे समझौते किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं अपितु पारस्परिक हित के आधार पर किये जा सकते हैं। हमें पड़ौसी देशों से अपने सम्बन्ध बढ़ाने/सुधारने अवश्य चाहिए।

यह खेद की बात है कि हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्री ने हमारे पड़ौसी देशों यथा बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हमें अपने पड़ौसी देशों के साथ सम्पर्क बढ़ाना चाहिए और इस बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वहां कौन सी सरकार स्थापित है। इन देशों से सभी मामलों में अधिक सहयोग करना वांछनीय है। जापान के साथ और भी अधिक आर्थिक सहयोग किया जाना चाहिए। तकनीकी सलाह के सम्बन्ध में हमें सदैव पश्चिमी देशों की ओर नहीं देखना चाहिए। अतः हमें अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन करना आवश्यक है।

एक बात यह कही गई है कि भारत का आज कोई मित्र राष्ट्र नहीं है। किन्तु पाकिस्तान को अपने इस दावे से कि उसके कई मित्र हैं, कोई लाभ नहीं हुआ है और भारत ने तथाकथित मित्र-हीन होने पर भी कुछ खोया नहीं है।

हमने सदैव मित्रता का दृष्टिकोण अपनाया है और न कि उससे अनुचित लाभ उठाने का। हमारे साथ एसे देश होने चाहिए जो कि हमारी स्थिति तथा दृष्टिकोण समझें और हमारे तरीके पर नहीं अपितु अपने ही तरीके पर हमारी सहायता करने का प्रयत्न करें।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : जहां तक हाल ही की नई घटनाओं का सम्बन्ध है, वैदेशिक-कार्य मंत्री महोदय से यह आशा थी कि वह कम से कम सरकार की नीति सम्बन्धी मूल मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का संकेत देंगे किन्तु वह रोडेशिया तथा दक्षिणी अरब क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उल्लेख करने के अतिरिक्त युद्ध-विराम के पश्चात घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में चुप रहे हैं। मुझे आशा है कि वैदेशिक-कार्य मंत्री इन्डोनेशिया में हुई घटनाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सभा को कुछ बतायेंगे यद्यपि कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य दिया था किन्तु इस अवसर पर उन्होंने अल्जीयर्स में तथाकथित अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। यह खेद की बात है कि उक्त सम्मेलन की बठकों में भारतीय प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार की ओर से अधिकृत रूप से बोलने के लिए मंत्रिमंडल पद के किसी मंत्री को वहां नहीं भेजा गया। सितम्बर में, अरब देशों के अध्यक्षों के कॅसाब्लैंका सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी मंत्रीमंडल के किसी सदस्य को नहीं भेजा गया था। प्रेसिडेंट नासर ने इस बात को बहुत महसूस करके हमें एक पत्र लिखा था।

युद्ध-विराम के बाद विश्वराजनीति विशेषतः एशियाई राजनीति में हुई विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति के बारे में संकेत देना चाहिए। राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद करने के बारे में इस सभा में कड़े विचार व्यक्त किये गये हैं किन्तु सरकार ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में मौन धारण किये हुए है।

सरकार ने हाल ही के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अमेरीकी दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार स्पष्टतः प्रकट नहीं किये हैं। काश्मीर सम्बन्धी हमारे दृष्टिकोण पर अमरीकी विरोध सवविदित है। यदि यह ठीक है कि अमरीका अपने विचारों को हम से मनवाने के लिए दबाव डालने के लिए

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

आर्थिक सहायता का प्रयोग कर रहा है तो उस स्थिति में सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि चाहे हमें अमरीका से खाद्यान्न तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त हो अथवा नहीं, हम इस प्रकार की राजनीति के समक्ष नहीं झुकेंगे ।

देश विभाजन के समय महात्मा गांधीजीने बादशाह खां को यह आश्वासन दिया था कि यदि पाकिस्तान ने पख्तूनों पर अत्याचार किये अथवा उनकी मांग पूरी न की तो भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ देगा । यदि हम रोडशिया के अश्वेत लोगों का समर्थन कर सकते है तो फिर अपने ऐसे भाइयों का समर्थन क्यों न किया जाए जिनका नेतृत्व हमारे सबसे अग्रिम नेताओं में से एक द्वारा किया जा रहा है ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए ।
SHRI KHADILKAR *in the Chair.*]

पूर्व पाकिस्तान तथा पख्तूनिस्तान की जनता उन्हीं धर्मनिर्पेक्ष तथा राष्ट्रवादी सिद्धान्तों के लिए लड़ रही है जिनका हम प्रबल समर्थन करते है । उनकी महत्वाकांक्षाओं को पुरा करने के लिए हमें कोई अन्य सारवान कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, प्रत्येक देश की वैदेशिक नीति, आर्थिक तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीतियों में मिली-जुली एक जटिल संमिश्रण बन गई है । भारत भी इस सम्बन्ध में अपवाद नहीं है । हमें ऐसी कोई भी आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता को संकट में डालती है । भारत को विश्व में उन देशों का प्रबल समर्थक प्रतिनिधि समझा जाता है जो उपनिवेशवाद अथवा साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे है । अतः हमारी कार्य-स्वतंत्रता, वरण (चॉइस) स्वतंत्रता तथा निर्णय-स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता से और अधिक खतरनाक है । अतः मै यह अनुरोध करूंगा कि हमें अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी से, जो पाकिस्तान को शस्त्र तथा हथियार दे रहे है, आर्थिक सहायता लेनी बन्द कर देनी चाहिए ।

सुरक्षा परिषद का कार्य भी श्री भुट्टो के कार्य की भांति सराहनीय नहीं रहा है। वह किसी निर्णयात्मक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी । विश्व के कुछ ऐसे समाचारपत्रों ने, जो उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण से विचार करते है, कहा है कि काश्मीर के सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त राजनैतिक विवाद पर चर्चा व्यर्थ है और यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि वहां जनमत संग्रह कराया जाए तो यह कार्य बिल्कुल ही अप्रजातंत्रीय है और यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है अतः इसका पाकिस्तान में विलय होना आवश्यक है, तो यह निःसार तर्क है ।

यदि धर्म, वर्ण तथा भाषा को किसी राज्य का आधार मान लिया जाए तो यह विश्व केवल बहुत से देशों में ही नहीं अपितु कतिपय उप-देशों में विभक्त हो जायेगा । सुरक्षा परिषद की कार्यवाही के परिणामस्वरूप हम एक इस निश्चयात्मक नतीजे पर पहुंचे कि काश्मीर समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस पर बातचीत की जा सके और काश्मीर समस्या का सदा के लिए हल हो चुका है । मै समझता हूं कि आजाद काश्मीर भी काश्मीर की भांति हमारे देश का अभिन्न अंग है और ताकत बढ़ने पर हम उसे भी अपने अधिकार में ले लगे । शक्ति से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु सफल नहीं होती है और हमें सभी प्रकार की शक्ति यथा आर्थिक, राजनैतिक, प्रतिरक्षा तथा प्रचार की शक्ति को बढ़ाना है ।

भारत सदैव गुट-निर्पेक्ष नीति का समर्थक रहा है । किन्तु आज इस नीति में उतना बल नहीं जितना कि उसमें किसी समय पहले था क्योंकि इसके समर्थक डा० सुकार्नो तथा परम मित्र कर्नल नासिर

जैसे व्यक्ति स्वयं अपने-अपने देशों की समस्याओं से उलझ हुए है और बेन बेल्ला कही अल्जीयर्स के रेगिस्तान में है जो स्वयं अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे है। विश्व के गुट-निर्पेक्ष नीति वाले देशों के लिए केवल एक ही व्यक्ति आशा के स्त्रोत है--जो मार्शल टीटो हैं। अत: समस्य विश्व में गुट-निर्पेक्ष नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें किसी प्रकार की कार्य-योजना, प्रचार-योजना आरम्भ करनी चाहिए। हम केवल गुट-निर्पेक्ष नीति अपनाने पर ही सफल हो सकते हैं।

भारत सदा सह-अस्तित्व की बात करता रहा है। हमें श्रीलंका तथा बर्मा के राज्यहीन तथा प्रवासी लाखों लोगों को एक अच्छे पड़ौसी देश होने के नाते अपने यहां बसाना पड़ा है। नैपाल से हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं जो समय के साथ-साथ और भी अधिक सुधरेंगे किन्तु चीन के साथ हमारे सम्बन्ध कम से कम कुछ वर्षों तक के लिए तो कभी सुधर ही नहीं सकते अत: संयुक्त राष्ट्र में चीन की वकालत कतई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके दो कारण हैं--प्रथम यह कि उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थान प्राप्त हो जाने पर सुरक्षा परिषद में 'वीटो' अधिकार भी मिल जायेगा, दूसरा--चीन उस स्थिति में और भी अधिक आक्रमक बन जायेगा।

विश्व का प्रत्येक देश आज अपनी वैदेशिक नीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। किन्तु मैं विस्तार में न जाकर केवल तिब्बत के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा, चीन के बारे में कुछ करने के उद्देश्य से हमें तिब्बत के प्रति अपनायी गई नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है क्योंकि आज वहां बड़े पैमाने पर जाति-विनाश किया जा रहा है। हम वहां हर चीज चीन की मर्जी पर नहीं छोड़ सकते। इस सम्बन्ध में हमें कुछ न कुछ करना जरूरी है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Chairman, Sir, in reply to a question yesterday the Defence Minister said that the dead bodies of soldiers could not be brought into Indian territory. It is very unfortunate that China does not invariably get possession of the dead bodies but it also kidnaps our soldiers.

Now, I would like to invite your attention to the foreign policy being pursued by our Government. There is no resolution in our foreign policy. As regards the time of our foreign policy, it is desirable to revise it and make certain changes therein. We should have firm principles backed by firm action with grim determination.

We should give recognition to the Government in-exile of the Dalai Lama and help him by way of imparting training to the maximum number of Tibbatians now residing in India and Nepal for the war of liberation.

We should act in pursuance of some certain firm principle. If, in any country, a Government remains in power for a long time and that Government is strong, we should not only recognise it but establish political and diplomatic relations also with it.

As regards the Vietnam conflict, it was not desirable for our Prime Minister to speak against America and in favour of Russia. Similarly we have not done the needful in the case of East Germany. It should have been recognised by our Government irrespective of the fact that America might be annoyed by that.

Now coming to Pakistan I would like to say something about its creation or its possible liquidation.

Secondly, Miss Fatima Jinnah and her followers might also help in re-integration of India and Pakistan. The third factor coming to our aid would be Frontier Gandhi and Baluch Gandhi *i.e.* Khan Abdul Samma Khan and in this area included 1½ crores of refugees. Lastly the people themselves of Pakistan, those very people

[Dr. Ram Manohar Lohia]

who had helped in the creation of Pakistan, have been completely disappointed with what is going on there since its very inception. We have to clearly study these factors separately and then evolve our foreign policy accordingly.

It were not the Muslims of Punjab who helped in the creation of Pakistan, but the Muslims of other states who apprehended the danger of Hindu domination over them. But now the circumstances have changed and they could be utilised as re-integration agents. We have to keep these changes in mind and work for a confederation of India or Pakistan or else war, wherever Pakistan thrusts it on us. The demand of Free East Bengal Radio to secure Free and fully antonomous East Bengal may also be noted in this connection.

The Defence Ministry had thought as early as 1952-55 that perhaps Pakistan would attack Chhamb-Jaurian-Akhnoor Sector to grab Kashmir and plans had been prepared in 1955 for an attack in the Lahore and Sialkot Sectors as a counteracting manoevour. These plans included the construction of Madhavapur road to save Chhamb-Jaurian. I want to know why this road was not built ?

Peaceful co-existance exists nowhere in the world today. There is a state of cold war between USA and USSR. Had our foreign policy been sound and effective, it would certainly had made some impression somewhere.

At the time of the Late Shri. Nehru, we used to think of a third Block—the Block of non-aligned nations. The idea of non-alignment has no meaning today. We should be prepared to align with countries having common ideas and who are prepared to follow the path of the welfare of the world. Who are with us to eradicate poverty, uphold the United Nations and re-unification of India and Pakistan. With these ends in view , we should certainly endeavour to win over both America and Russia or at least one of them. Apart from this , we should have sent our delegation to Thailand, Malayasia, Philipines, Taiwan, Japan, South Korea, Afghanistan, Nepal and Outer Mongolia for their better appreciation of our policies. But this has not been done.

So far Gandhism was being murdered but now it has committed suicide because the followers of Gandhiji are talking of war to day. Only those countries have food who have weapons, therefore the world is going towards war preparation rather than disarmaments and only USA and USSR can bring about disarmament if they want.

Though we ceaselessly talk of secularism, yet it could not be achieved in India. Time has brought about great changes in the world and its affairs and we have to adopt ourselves accordingly and we have therefore to bring necessary changes in our foreign policy also.

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवेल्ला) : यद्यपि मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पश कर के यह बताने की कोशिश की है कि सरकार ने स्थिति का ठीक से मुकाबला नहीं किया है और उनकी नीतियां समय के अनुसार प्रभावी नहीं सिद्ध हुई, परन्तु अन्य सभी सदस्यों ने सरकार की कार्यवाही का जो समर्थन किया है वे ठीक ही है। परन्तु हमें किये गये कार्यों से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये और यह समझ लेना चाहिये कि आगे हमारे ध्येय क्या हैं और उनको प्राप्त करने के लिये हमें क्या करना है। हमें उन कमियों और त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिय हमें अपनी विदेश नीति को अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाना होगा। इस संबंध श्री मसानी ने जो सुझाव किसी गुट में शामिल होने के बारे में दिया है वह भी तर्कसंगत नहीं है। परन्तु

हम गुटों से अलग रहने और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के नारे मात्र से ही अपने आप को ठीक सिद्ध नहीं कर सकते। गुटों से अलग रहने की नीति से देश को काफी लाभ पहुंचा है और इसका आधार भी अच्छा है परन्तु हम अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। इस नीति को अपनाने का आधार अपनी नीति निर्धारण की स्वतंत्रता कुछ ठीक नहीं है, हमें समझ लेना होगा कि पाकिस्तान हमारी मित्रता की भाषा को समझने को तैयार नहीं है, वह हमारे शान्ति के प्रयत्नों को निर्बलता का लक्षण समझता है। हमें उसके प्रति अपनी यह नीति बदलनी होगी हमें पाकिस्तान को स्पष्ट बता देना होगा कि यदि वे हमारी अन्तरित समस्याओं से अनुचित राजनीतिक लाभ उठायेगा तो वहां भी ऐसी समस्यायें हैं जिनका हम भी लाभ उठा सकते हैं और यह एकपक्षीय मित्रता अब नहीं चलेगी। वहां भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सामरिक महत्व से इतने दुर्बल है जिन्हें दबाया जा सकता है। वहां की जनता में भी विभिन्न महत्वाकांक्षायें हैं। यदि जनमत संग्रह एक ऐसी वस्तु है जिस के संबंध में पाकिस्तान तर्क प्रस्तुत कर सकता है तो पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में भी स्वायत्तता तथा जनमत संग्रह के लिये महत्वाकांक्षायें पाई जाती हैं।

इस सत्य से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि जिन देशों की हम ने अपनी क्षमता से अधिक सहायता की थी वे हमारे मित्र सिद्ध नहीं हुये। हमें ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे हम अपने मित्रों और शत्रुओं में भेद कर सकें। हमें ऐसे मित्रों को बताना होगा कि उचित अनुचित का विचार किये बिना शान्ति स्थापित करने के सिद्धान्त के बहुत गंभीर परिणाम निकल सकते हैं।

यह कहना कि अल्जीयर्स में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भारत का साथ किसी देश ने नहीं दिया और इसका स्थगन चीन की कूटनीतिक जीत और भारत की हार है, गलत है। क्योंकि मैं स्वयं वहां उपस्थित था। हमारी स्थिति यह थी कि भारत सदा अफ्रीकी-एशियाई एकता का इच्छुक है और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध वहां के देशों के अभियान में उनका साथी है और वहां हमारा दृष्टिकोण सदा यही रहा है कि हम किसी राष्ट्र का यह अधिकार नहीं समझते कि जब वह चाहे सम्मेलन बुलाये जब चाहे न बुलाये और न ही किसी को ऐसी पूर्व शर्तें रखने का अधिकार है कि कौन देश इस में भाग लेंगे और कौन नहीं। चीन जबकि जून में यह सम्मेलन आवश्य बुलाये जाने के पक्ष में था, चाहे अफ्रीकी देश भले ही अनुपस्थित रहें। अब चीन ने यह सम्मेलन बुलाने की तीन शर्तें रखी थी एक यह कि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र से कोई संबंध न रखे, दूसरी यह कि रूस को इसमें भाग न लेने दिया जाये और तीसरी यह कि यह सम्मेलन अमरीकी साम्राज्यवाद की निन्दा करने को सहमत हो। चीन चाहता था कि स्थायी समिति इसका फैसला करे कि सम्मेलन होगा अथवा नहीं परन्तु स्थायी समिति का निर्णय यह था कि विदेश मंत्री सम्मेलन ही इसका निर्णय लेगा। 61 में से 45 देशों ने अल्जीयर्स में इसमें भाग लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीत किसकी हुई।

हमें राष्ट्रमंडल छोड़ने के बारे में कोई निर्णय अनुचित शीघ्रता से नहीं लेना चाहिये। परन्तु क्या हमारा 18 वर्ष का अनुभव पर्याप्त नहीं है जिसके आधार पर हम यह निश्चय कर सक कि हमें राष्ट्रमंडल छोड़ देना चाहिये अथवा नहीं। अब हमें यह निश्चय कर ही लेना चाहिये और इसकी कसौटी शुद्ध राष्ट्रीय हित ही होनी चाहिये।

रोडेशिया के संबंध में सभा सरकार की नीति का समर्थन करेगी परन्तु हमें इस संबंध में ब्रिटिश रवैये को आंकने में अधिक स्पष्टवादी बनना होगा। संसार कभी ब्रिटेन को उसके कुकर्मों के लिये क्षमा नहीं करेगा। वह चाहता तो वर्तमान स्थिति कभी उत्पन्न न होती।

जहां तक हमारी विदेश नीति का संबंध है, हम आज बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहे हैं। अफ्रीका और एशिया में चीनी प्रभाव घटता जा रहा है। पाकिस्तान के मित्र भी उसकी सत्यनिष्ठा के प्रति शंकित हैं। इन्डोनेशिया में भी ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसे शायद भविष्य में हमारे संबंधों में सुधार हो सकता है। इसलिये आवश्यक है कि हमारी विदेश नीति साहसपूर्ण दूरदर्शितापूर्ण और सजीव हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी नीति अपनाये जो प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप न होकर क्रियामय हो, जो घटनाओं के बाद के विचार से न बन कर पूर्वविचारशीलता के आधार पर बने।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : यह उत्साहवर्धक बात है कि 1962 की हार के पश्चात अब भारत की निश्चयात्मक कार्यवाही से उसने अपने खोये गौरव को कुछ सीमा तक पुनः प्राप्त कर लिया है। इस संघर्ष में विभिन्न दशों द्वारा अपनाये गये रवैये को देखते हुये हमें अपनी विदेश-नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। यद्यपि जिन मंत्रों का उच्चारण करते रहे हैं और जिन उपदेशों का प्रचार करते रह है वे अपने आप में बहुत अच्छे है, परन्तु जब हमारे पड़ोसी देश भी इन्हें मानने से इन्कार करते हैं तो हमारी आंखे खुल जानी चाहियें। इसलिये हमारी विदेश नीति को अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण और क्रियात्मक होना चाहिये और अपने पड़ोसी देशों की विचारधाराओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

गुटनिर्पेक्षता की नीति का अन्धाधुन्ध अनुकरण करने से क्या लाभ जब कि जब अन्य देशों में अच्छा वातावरण नहीं बना पाये। भारत-पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के 110 सदस्य देशों में से केवल 85 ने ही किया जिन में से 63 निष्पक्ष रहे, 19 देशों ने स्पष्ट रूप से हमारा विरोध किया जिन में से 11 अरब देश भी थे।

मैं एशिया और अफ्रीका के देशों का उल्लेख करता हूं। हमें उनकी स्थिती का पूरा विश्लेषण करना होगा और इस बात का पता करना होगा कि ये देश हमारे प्रति इतना उपेक्षा भाव क्यों बनाये हुए हैं। हम तो इन देशों के लिए गत दस वर्षों से खूब जोश दिखाते रहे है। हमनें बांडुग में इनके लिए बहुत कुछ किया, अब अल्जीरिया में उनके लिए जोश दिखाया। परन्तु चीन ने इस बार भी मैदान मार लिया। अल्जीरिया की सरकार भी इस पक्ष में थी कि वहां सम्मेलन हो, परन्तु एक ही दिन के बाद स्थिति बदल गई। लगभग दस बरस हीं की तो बात है हमारा इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था। परन्तु अब चीन-पाकिस्तान धूरी भारी हो रही है। 1962 में जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था तो अफ्रीका के कुछ देशों ने स्पष्ट रूप से हमारा साथ दिया था, परन्तु पाकिस्तान के मामले में हमने देखा है कि किसी भी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया है। मेरा निवेदन यह है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष मे हमें विभिन्न देशों का जो व्यवहार देखने को मिला है, उसे देखते हुए हमें अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना ही होगा। हमें यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि जिन उच्च आदर्शों का हम प्रचार करते है, वे अपने आप में तो अच्छे हैं परन्तु उसका किसी अन्य देश पर कोई प्रभाव नहीं है। विदेश नीति के रूप में उसके द्वारा देशों को मित्र नहीं बनाया जा सकता।

हमें इस बात को आखें खोल कर देखना चाहिए कि किस तरह अफ्रीकी-एशियाई देशों पर पिंडी-पीकिंग धूरी का प्रभाव हो रहा है। यह देश इस प्रयास में है कि इस देश में लोकतंत्र का विकास न हो। हमें संसार में चल रही हवा से दूर नहीं रहना चाहिए। हमें बड़े व्यवहारिक आधार पर विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए। हमें अपने पड़ौसी देशों की विचारधाराओं की ओर ध्यान देना चाहिए, और वहां की घटनाओं का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। मलयेशिया, सिंगापुर तथा जापान जैसे देशों से निकटतम सम्पर्क स्थापित करने चाहिएं।

हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार देश में लोकतंत्र का विकास कर सकते है। इस दिशा में यदि कोई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े तो करना चाहिए। इस तरह का वातावरण निर्माण करना चाहिए कि हमारी नीति को गम्भीरता से लिया जाय।

श्री खाडिलकर (खेड) : पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष हुआ है, उसे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उसके प्रभावों के बारे में हम सही परिणाम नहीं निकाल सकेंगे, और हमें भविष्य के लिए कोई प्रकाश नहीं मिल सकेगा।

जैसा कि यह सर्व विदित है कि पहले संसार भर में संघर्ष करने वाले दो विरोधी गुट थे। परन्तु अब तो, साम्यवादी गुट में भी परस्पर विरोध बढ़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अफ्रीका तथा एशिया के नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रों की एकता में भी दरारे पड़ गयी है। विश्व की राजनीति में यह एक बिलकुल ही नई बात, और हमें इसका गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए। और गुटों का राजनीति में यह जो परिवर्तन आया है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस नये विकास की पृष्ठ भूमि में ही हमने अपनी विदेश नीति का विकास करना है। और उसे व्यवहारिक और प्रगतिशील स्वरूप देना है। इस तरह हम उन कमियों को दूर कर सकेंगे जो कि हमारी विदेश नीति में देखने को मिलती रही है। अल्जीरिया में जो कुछ हुआ, वह स्थिति का शोचनीय चित्र है।

गुटों से निरलेप रहने वाली नीति के पीछे एक लम्बा इतिहास है। श्री नेहरू ने बड़ी दूर दृष्टि से यह देखा था कि नये स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों के लिए शांति ही सब से बड़ी चीज है। शांति होने पर ही वे ठीक तरह से विकास कर सकते है। हमें इस नीति पर बदले हुए हालात में देखना और उस पर विचार करना है। श्री मलानी का यह कहना गलत है कि भारत को एशिया का नेता बनना चाहिए। पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, बर्मा, कम्बोडिया आदि की वर्तमान मनोवृत्ति को विचाराधीन रखते हुए ऐसा नहीं होने जा रहा है। मैं तो यह भी कहता हूं कि फारमोसा को मान्यता देने की बात करना भी मूल ही है। एक दिन वह अवश्य समाप्त हो जायेगा। वह जीवित तब ही रह सकेगा जब कि चीन उसकी स्वतन्त्रता तथा उसको बचाये रखने की बात करेगा। चीन और पाकिस्तान में जो गठबन्धन आज है, वह ब्रिटेन की सुझबुझ का परिणाम है। पाकिस्तान, आज एक जवान सुन्दरी की तरह किसी देश के साथ भी वफादारी के सम्बन्ध नहीं बना रहा। वह एक विकृत राष्ट्र का रूप धारण कर रहा है। वहां की जनता बिलकुल अज्ञान की स्थिति में है। वह विभिन्न स्वामियों के पीछे भाग रहा है और उसका संसार में कोई आदर नहीं हो रहा है।

एक अच्छी बात यह हुई है कि सुरक्षा परिषद में उसे बड़ी असफलता मिली है। इस असफलता के पश्चात उसे बिना यह जाने कि रूस के नियन्त्रण का लक्ष्य क्या है, उसे स्वीकार कर लिया है रूस ने महसूस किया है कि यदि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ौसी बन कर रहना है तो शत्रुता को भूला कर काश्मीर के प्रश्न को निलम्बित रखना चाहिए। इससे चीन भी उस क्षेत्र से दूर रहेगा। रूस भी वास्तव में यही चाहता था कि चीन को इस सामरिक क्षेत्र से दूर रखा जाय। मेरा कहना है कि हमें इस नई स्थिति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह एक तथ्य है कि सुरक्षा परिषद् किसी भी हालत में इस मामले में कोई निर्णय नहीं कर सकेगी।

अरब देशों में मजहबी भावनाए अधिक है, अतः इस कारण से कुछ अरब राष्ट्रों ने पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठाई है। परन्तु यह भी एक ठोस सत्य है कि हमें श्री नासिर के महत्वपूर्ण भाग और प्रभाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन के प्रयासों के कारण ही उन देशों ने भारत को आक्रान्ता घोषित नहीं किया है। एक बात हमको समझ लेनी चाहिए वह यह कि पाकिस्तान के साथ अपने सम्बधों के मामले में हमें अपनी नीति के मूल सिद्धान्तों को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश की रक्षा करते हुए हमें लोक तंत्र और धर्मनिर्पेक्षता की रक्षा करनी होगी। इसलिए इस समस्या के बारे में हमें कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि उनके वर्तमान नेताओं के विरुद्ध है।

श्री जी० म० कृपलानी (अमरोहा) : बहुत से कांग्रेसी सदस्यों ने कहा है हमारी विदेश नीति की बहुत शानदार सफलता हुई है। मेरे विचार में ऐसा कह कर वे अपने आप से अन्याय कर रहे हैं। और यह रणक्षेत्र में लड़ रहे सैनिकों से भी अन्याय है। विदेश नीति ने तो हमें संसार भर में अकेला छोड़ दिया है, यदि कोई सफलता है तो वह सैनिक मशीनरी की है। गत 18 वर्षों में हमारी विदेश नीति को भारी असफलताओं का मुँह देखना पड़ा है। एक बात हमको याद रखनी है, वह यह कि देश की विदेश नीति का आधार घटनाओं के पूर्वानुमान पर होता है। मामला चाहे तिब्बत का हो, चाहे पाकिस्तान का, प्रश्न गोवा का हो अथवा किसी और देश का, हम कहीं भी इस स्थिति को ठीक ढंग से समझ नहीं पाये हैं।

[श्री जी० म० कृपलानी]

स्थिति यह है कि हम आज तक यह अनुमान ही नहीं कर पाये कि चीन के इरादे क्या है। हम यह भी नहीं समझ पाये कि चीनी साम्यवाद का स्वरूप तथा रूसी साम्यवाद का स्वरूप भी नहीं समझ पाये। यदि हमने माओं का साहित्य पढ़ा होता तो हम यह भूल कभी भी न करते। अंग्रेजों ने स्वेज के मामलें में धोका खाया था, क्योंकि वे अनुमान नहीं लगा पाये थे। अब रोडेशिया में पुनः धोका खा रहे हैं। हमारे सैनिकों ने रणक्षेत्र में जो विजय प्राप्त की थी, उसका श्रेय विदेश नीति को नहीं दिया जाना चाहिए।

आज भी हमारे भूत पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री सैनिक प्रशिक्षण न देने की बात करते है, हालांकि स्थिति यह है कि इसी के अभाव में हमने नेफा में चीन से मार खाई थी। उन्होंने युद्ध लिप्सा के मनोविज्ञान की निन्दा की है। और हमारे नेता और वक्ता पाकिस्तान से सुलह की बात करते हैं। आज के हालात में यह बड़ी अजीब दिखाई देता है। ये लोग प्रतिरक्षा की उपेक्षा करके यह बातें कर रहे है। लोग कहे चले जा रहे हैं कि हमारी विदेश नीति सफल हुई है। इस गुटों से अलग रहने वाली नीति है क्या, इस पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा। मेरा निवेदन यह है कि सैद्धान्तिक रूप में यह गुटों से अलग रहने वाली नीति एक अंतर्गत बात है। यदि हम और हमारा देश संकट में है जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते, तो हमें जहां से भी सहायता मिले, उसे ले लेना चाहिए। यह सम्भव है कि किसी विशेष समय और परिस्थिति में यह नीति सफल हो जाय, सदा के लिए ऐसा हो सकना सम्भव नहीं हो सकता। हमें सिद्धांतों की ओर अधिक ध्यान न देना चाहिए। देश की प्रतिरक्षा तथा आत्मपरीक्षण करके ही विदेश नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इस नीति का आधार हमारे अपने राष्ट्रीय हित होने चाहिए।

हम गुटों से मुक्त रहने का ही नहीं, विश्व शांति का उपदेश भी संसार भर को देते रहते हैं। कहा जाता है कि भारत का लक्ष्य तो विश्वशांति है। यदि यह कहा जाय कि चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करो तो कहा जाता है कि हम युद्ध पिपासू है। आप शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बातें करते हैं। हम अपनी प्रतिरक्षा के लिये भी लड़ना नहीं चाहते। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम गोआ को भी शांतिप्रिय ढंग से प्राप्त करना चाहते थे परन्तु ऐसा संभव नहीं हो सका। उसके लिए हमें शस्त्र उठाने ही पड़े। मेरा निवेदन है कि बातें करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हवा में उड़े, व्यवहार की बात करें। साथ ही हमें सावधान भी रहना चाहिए। हमें अपनी विदेश नीती का समर्थन करते हुये सम्मानित सिद्धान्तों को सामने रखना चाहिए। हम आज की स्थिति में गांधी जी की अहिंसा के आधार पर कोई रास्ता नहीं अपना सकते। पुराने तरीकों को हमें अब छोड़ देना होगा।

हमारा विदेशों में प्रचार प्रबल नहीं है। यह ठीक है, परन्तु ऐसा कहने पर अब कई सज्जन नाराज होते है। यदि यह स्थिति है तो आप कई लोगों को शिष्टमंडल के रूप में विदेशों में क्यों भेज रहे हैं ? जब कि हमारे विदेशी संसाधन इतने कम है। अन्य देशों में यह प्रणाली है कि विशेष दूत भेजा जाता है ताकि वह राज्याध्यक्षों के साथ खुले रूप से बातचीत कर सकें। हमारे कूटनीतिक मिशन धन और समय को नष्ट करते है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समय में तो कूटनीति केवल उनका व्यक्तिगत विषय था। जिन देशों में हमारे बड़े बड़े लोग शिष्टमंडलों के रूप में जाते हैं, उन्हें न अपने ही देश का कुछ पता होता है और न ही उस देश का जिसमें वे जा रहे हैं।

हम कितने चतुर है यह बात आप इस बात में देखिए कि हम अरब राष्ट्रों के बारे में क्या समझ रहे हैं। हम यह समझ रहे हैं कि अरब विश्व का अरब से कोई सम्बन्ध नहीं। हम 'मिश्र' को जिसने अपना नाम संयुक्त अरब गणराज्य रख लिया है, को ही अरब संसार समझ रहे हैं। संयुक्त अरब गणराज्य के लिये हम इसराईल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते। यह कितनी लज्जा की बात है। हमारे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से कोई भी वहां कभी नहीं जायेगा ! इसराइल के लोग ऐसे है जिन्होंने मरुस्थलों को उद्यान बना दिया है। उन्होंने जंगल का मंगल कर दिया है। अरब लोग कुछ भी कहते रहें, वह शान से जी रहें हैं। इस दिशा में हमें स्थिति का समझना चाहिए। हमारें उप विदेश मंत्री ने जोर्डन के साथ सम्बन्धों की बात की है। यह वही देश है जिसने हमारे विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन किया है।

बर्मा, नेपाल, रूस तथा अफ्रीकी देशों के इसराइल तथा अरब दोनों के साथ सम्बन्ध है, फिर भी वह चल रहे है। उनका कुछ नही बिगड़ा, फिर हम ही क्यों भयभीत हो रहे हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि विदेश नीति दृढ़ता पर निर्भर करती है।

हमनें अपने सब से योग्य व्यक्ति पश्चिमी देशों में भेजे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में हमने बहुत कम व्यक्ति लोगों को भेजा है। हम इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हालांकि हमारे हितों की दृष्टि से यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरीका ने पकिस्तान का समर्थन करके हमारे हितो को काफी हानि पहुंचाई है। हमने उसकी इसके लिये निन्दा नहीं की है। यह बहुत भारी भूल है। मेरा मत यह है कि हमे इस बात को बड़ी गम्भीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए था कि वियतनाम में अमरीका की नीति क्या है। हम उस नीति से सहमत होते अथवा नहीं, परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति जानसन ने इसे व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न बना लिया है। इस तरह ब्रिटेन के बारे में भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम कुछ भी करे, बिटेन हमारा मित्र नहीं बन सकता। हमें इस बात पर विचार करना है कि हमें राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहिये अथवा नहीं।

एक विचार करने का प्रश्न है, ब्रिटेन में हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय में 3000 से अधिक कर्मचारी है। यह ठीक ही पूछा जा सकता है कि इतनी संख्या में वहां कर्मचारी रखने का क्या लाभ है। वहां अधिक से अधिक 12 व्यक्तियों से काम चल सकता है। एक ही कार्यालय पर इतना खर्च हो जाता है, जितना की अन्य सभी दूतावासों पर होता है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के धन का कुप्रयोग न हो। कांग्रेस सरकार को इस दिशा में जागरूक होना चाहिए।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : आज जो यहां विवाद हो रहा है, उसे सभी अखबार बड़े बड़े शीर्षकों में छाप रहे हैं। एक आध को छोड़ कर सभी यह राय व्यक्त कर रहे हैं कि विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि विदेशी नीति के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। लगभग सरकार के सभी उच्चतम क्षेत्रों में कहा गया है कि हमें अपनी विदेश नीति के बारे मे फिर से सोचना चाहिए। यह मत लगभग सभी दलों ने व्यक्त किया। हमारी सरकार लगभग इस दिशा में 'पुरानी लाइनों' पर ही चल रही है। हम केवल गुटों से निरपेक्ष रहने की नीतीका ही बात कर रहे है। रूस, अमरीका और ब्रिटेन, सभी बड़े बड़े राष्ट्रों ने समय समय पर अपन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अपनी नीति में परिवर्तन किया है। मेरा निवेदन है कि ऐसे रास्ते है जिन पर चल कर हम भी अपनी पुरानी नीति से ही दूसरे रास्ते निकाल सकते है। नई नीति का निर्माण कर सकते हैं जिसमें देश की भावी मांगों का पूरा तरह ध्यान रखा जा सकता है।

यदि उनमें हिम्मत है तो उनको रूस के प्रधान मंत्री और नेताओं से कहना चाहिये कि वे स्वयं वक्तव्य दें और फिर समूचा राष्ट्र उन के समर्थन और सहानुभूति का आभारी होगा।

श्री खुश्चेव के समय में उन्होंने स्पष्ट रूप से विश्व को और पाकिस्तान को बता दिया था कि काश्मीर भारत का है और यदि कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा तो वह अपनी जोखिम पर करेगा। क्या आज भी रूस की विदेश नीति ऐसी ही है। आज हम बराबर यह कहते हैं कि रूस हमारी कई प्रकार से और सैनिक रूप से सहायता कर रहा है। यह सच है लेकिन पाकिस्तान रेडियो सुनिये तो पता चलेगा कि एक और रूसी शिष्टमंडल वहां गया है और वे कई प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बनाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके लिये मैं रूस को दोष नहीं देता। यह तो उनकी अपनी नीति है।

अमरीका और रूस को लीजिये। इनका इतिहास बडा ज्वलन्त है। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध किया और लीग आफ़ नेशन्स की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को युद्ध अपराधी घोषित किया। उन्होंने पहला विश्व युद्ध संसार मे लोकतंत्र स्थापित करने के लिये और दूसरा विश्व युद्ध स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये लडा। अब वे क्या कर रहे हैं? अब वे देश इन दोनों युद्धों के आदर्शों के विरुद्ध हैं।

[श्री हनुमन्तैया]

हमारी सीमा पर एक सैनिक तानाशाह बैठा है। वह धर्म के आधार पर शासन चलाना चाहता है। इंगलैण्ड में पोप के ऐसे ही रवैये के विरुद्ध विद्रोह किया था और कई सौ वर्ष पूर्व इंग्लेण्ड को धर्म-निरपेक्ष बना लिया। आज अमरीका और ब्रिटेन इस सैनिक तानाशाही को, इस धार्मिक तानाशाही को 1965 में सहारा देकर शांति स्थापित करना चाहते हैं और फिर काश्मीर की बात करते हैं। क्या यह कभी संभव है ?

मैं अमरीका और ब्रिटेन के नेताओं से अपील करता हूँ कि वे यह सोचें कि जब जर्मनी विभाजित है तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि एक प्रकार का समझौता करके जर्मनी को एक किया जाए; क्या हम यह नहीं कह सकते कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को मिला कर एक किया जाए। अतः काश्मीर के बारे मे हमें सलाह देने से पूर्व उन्हें सैकड़ों बार सोचना चाहिए।

मैं सरकार का उनकी कार्यवाही के लिये समर्थन करता हूँ। हमें काश्मीर के बारे में बातचीत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आजाद काश्मीर को काश्मीर के साथ मिलाया जाए। श्री स्वर्ण सिंह जी ने वाद-विवाद का आरम्भ करते हुए बड़ा सावधानी पूर्वक और कानूनी भाषण दिया था। सुरक्षा परिषद में भी उन्होंने ऐसा ही भाषण दिया होगा। लेकिन सुरक्षा परिषद पर तर्कों का असर नहीं होता चाहे वे कितने ही युक्तियुक्त क्यों न हों। सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय नहीं है। हमने सदैव ऐसी गल्ती की है और जब कभी हम क्षुब्ध होते है तो संसार में हर अन्य किसी को दोष दे देते हैं। यदि अन्याय और गलत विचारों के बावजूद भी आज पाकिस्तान को इतने राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है तो वह किसी कारण से नहीं बल्कि इसके गठजोडों के कारण है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए। प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह राज्यों के प्रमुखों के साथ केवल भारत की स्वतंत्रता और विश्व शांति की रक्षा के लिये नहीं बल्कि संसार में न्याय सुनिश्चित करने के लिये बातचीत करें। लेकिन यह कहने का कि हमने 18 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, अर्थ है कि हम पूरी तरह असफल रहे हैं। विदेश नीतियां समय समय पर बदलती रहती हैं। वर्तमान स्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि हमारे मित्र कौन हैं और शत्रु कौन हैं और कौन मित्र हो सकते हैं।

जहां तक राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध है, तीन साल पहले जब चीन ने हम पर हमला किया था तो इसकी प्रतिक्रिया हुई। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, प्रतिपक्षी दल के नेता और अन्य सदस्यों ने भारत के पक्ष में भाषण किये। ब्रिटेन और अमरीका ने हमें धोखा नहीं दिया है। जहां तक चीन का सम्बन्ध है, वे हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के लिये उनके हृदय में स्थान है और वे पाकिस्तान और भारत में समझौता कराना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति में फेरबदल करना पड़ेगा। हमारे विचार अपने हैं और पाकिस्तान के अपने विचार हैं। हमारी अपनी विदेश नीति बनाने में और सैन्य शक्ति बढाने में राष्ट्रमंडल बाधक नहीं है। अब अमरीका और ब्रिटेन अपना रुख बदल रहे हैं। अब वे कह रहे हैं कि अब जनमत-संग्रह का प्रश्न समाप्त हो चुका है। शायद सरकार के दृढ रवैये के कारण उन्हे हमसे सहमत होना पडा हो। ब्रिटेन महात्मा गांधी से भी सहमत हो गया था हालांकि उसने 60 वर्षों तक स्वराज्य के विचार का प्रतिरोध किया। मुझे विश्वास है कि यदि हम अपनी विदेश नीति सम्मानपूर्व, मर्यादापूर्ण और समझबूझ के साथ बनाएंगे तो ब्रिटेन और अमरीका दोनों यह समझने लगेंगे कि भारत ने जो रुख अपनाया है, वह ठीक है। यदि आप लडते हैं तो आपको एक पंजाबी योद्धा की तरह लडना चाहिये और यदि आप समझौता करना चाहते हैं तो आपको वास्तविक मित्रतापूर्ण ऐसा करना चाहिये। हमे हिचकना नहीं चाहिये और अपने रुख पर दृढ रहना चाहिए।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहिले, यह निश्चित मत होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति बनाने रखने के लिये आजाद काश्मीर भारत को दे दिया जाय। दूसरे, आप यह न कहें कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। तीसरे, हमें इजरायल, तैवान और पूर्वी जर्मनी को और उस हर देश को, जहां पर सरकार है, मान्यता देनी चाहिए जब तक कि यह संयुक्त राष्ट्र के संकल्प द्वारा ऐसा करने पर प्रतिबन्ध न हो जैसे कि रोडेशिया।

चीन का इरादा यह है कि सारा संसार साम्यवादी नेतृत्व के अधीन आ जाय। अतः हमें चीन के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को शामिल न करने की बात कहने वाले देशों का साथ देना चाहिये। तिब्बत का प्रश्न राष्ट्र संघ में उठाया जाना चाहिये। यह प्रश्न उठाने का यही उपयुक्त समय है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Chairman, Sir, an impression has been created due to our weak publicity that the main issue of conflict between India and Pakistan is Kashmir. They think that if the problem of Kashmir is solved, both India and Pakistan would remain peacefully being neighbourers. But this is not correct. If Kashmir problem is solved, Pakistan can create other problems by sending intrudors in Assam or in some other area. For this it is necessary to understand the mentality which is the basis of this conflict between India and Pakistan. This is the mentality which was responsible for the partition of the country and unless we strike out that, this conflict would never come to an end.

I agree that the Kashmir problem must be solved at the earlier. For the last 18 years we have been dilly-dallying with this issue and the result is there before us. The Kashmir problem must be settled once for all.

We must tell the U.N. and the security council that the problem of Kashmir exists only with regard to that part of Kashmir which is under the illegal occupation of Pakistan and the people of India cannot tolerate such situation any more.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*.]

The problem of Kashmir is not religious. If it was based on religion it would have settled much earlier. The land was distributed between India and Pakistan. If U.S.A. and Britain say that most of the people there belong to a particular religion, and their sympathy is with Pakistan they can go to Pakistan but the the land cannot be given to Pakistan. Once partition has been effected the question of giving a price of territory does not arise at all. If the Government of India does any such thing, we would be inviting the same danger and commiting the same blunder as we did when China had swallowed Tibet.

It is time when we should do away with Article 370 of the Constitution. This Article gives wrong impression in other countries. The Government should allow Khan Abdul Ghaffar Khan to direct the Pakhtoen movement from Delhi as we are allowing Dalai Lama to direct liberation movement of Tibetians. We should also give our support to East Pakistan. This will give a crushing blow to Pakistan.

Pakistan has been violating ceasefire every day. It is time when we must give them a warning that we are not going to tolerate this nonsense any more and that if, they do not stop it within a particular time-limit they should be prepared to face the consequences and then no country would say that this is India which spoiled the existence of Pakistan.

The way of thinking and taking decision should be changed. It is time that the resources should be fully utilised. We should take the services of those private industrialists for defence production work who can help in this direction.

I congratulate Sardar Swarn Singh for his bold action in the Security Council when he walked out of its sitting in protest of Mr. Bhutto's abusive language.

[Shri Prakash Vir Shastri]

But the unfortunate matter is that no country in the security council pointed out that the standard of security council should not be allowed to lower down in such manners. This shows how weak and ineffective our foreign policy is. People say that our foreign policy should be changed but I say that the need is to change the working of the External Affairs Ministry. We should change those persons who prepare our policy. Best brains should be put on important job of presenting the case of Kashmir before world powers. We should see that persons included in the delegations being sent abroad should be familiar with the issue which they are going to clear there, otherwise it would be of no help. We must send such Members of Parliment to different countries as have the special knowledge of those countries, otherwise the objective will not be fulfilled. Our publicity is very weak and ineffective. Our present publicity programme is hampering our self-respect. We should not neglect our nieghbour countries. Our foreign policy should have connections with countries rather than with persons.

Besides diplomatic relations we should strengthen the cultural ties with Thiland, Japan and Ceylon. If Govt. does this, they would be doing a lot for the country.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सभापति महोदय, हम गुटबन्दी और गुट-निरपेक्षता की बात करते रहे हैं। विदेश निति को बहुत सरल बनाना, संसार में विद्यमान स्थिति का अति-सरलीकरण तथा उस रवैये का अति सरलीकरण कि हमें मित्रों की आवश्यकता है और जब भी हम मित्रों की तलाश करेंगे, वे हमें मिल जायेंगे, एक गलत बात है। इनसे जितनी जल्दी छुटकारा हो जाय उतना अच्छा है।

आज यह कल्पना करना बडी आश्चर्यजनक बात है कि हमें मित्र बनाने चाहियें और जैसे ही हम मित्र बनाने का प्रयत्न करेंगे, हम मित्र बना सकेंगे। हम यह महसूस नहीं करते और हम यह भूल जाते हैं कि विदेश नीति के सम्बन्ध में प्रत्येक देश हित प्रथम और सर्वोपरि होता है। संसार में किसी भी देश ने मौजूदा समय के लिये नहीं बल्कि भविष्य के लिये अपने हित को देखे बिना अपनी विदेश नीति नहीं बनाई।

हम यह समझते है कि चीन ने हमें धोखा दिया है और इसलिये हमें अमरिका की शरण में चले जाना चाहिये जैसे कि वह हमें अपनी शरण में लेने को आतुर है। यह बडा गलत विचार है। यह उचित समय है जब कि सरकार यह स्पष्ट करे कि इस देश के साथ तभी मित्रता की जायेगी जब दोनों देशों के हित सम्बन्धित होंगे। यह सदा ही किसी विशेष स्थिति में मित्र बन जाने का प्रश्न है। कोई स्थायी शत्रु नहीं है, कोई स्थायी मित्र नहीं है। श्री केनेडी ने कहा था कि राजनीति में कोई मित्र नहीं होता केवल साथी (allies) होते हैं। यह सच है।

आज हमारे मित्र हैं। हम पृथक नहीं हैं। मैं यह बात नहीं मानती। यदि चीन का दमन होता है तो बहुत से देश प्रसन्न होंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जैसे ही चीन का दमन करना चाहे, अन्य देश हमारी कार्यवाही में हमारी सहायता करें। यह रवैया ठीक नहीं है। यह रवैया भी गलत है कि जैसे ही कोई देश हमारे साथ गलत व्यवहार करे हम उसका बदला लें या अन्य देशों से यह आशा करें कि जैसे ही हम अपनी लड़ाइयां लड़ें, वे अपने शस्त्रों तथा गोला-बारूद के साथ हमारी सहायता के लिये आ जाय। इस प्रकार के रवैये से हमारा सम्मान घट रहा है।

हमें गुट-निरपेक्षता की नीति पर दृढ रहना चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हथियार नहीं उठायेंगे। गुट-निरपेक्षता की नीति किसी परिस्थिति के सम्बन्ध में विशेष

दृष्टिकोण की नीति है। भारत स्थित कनाडा के उच्चायुक्त ने भी, भारत की नीति की सराहना करते हुए, इसकी आलोचना की।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी विदेश नीति बड़ी सफल रही क्यों कि इसमें दूरदर्शिता की भावना थी। आज समूचे संसार में विदेश नीति के आधार में बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है। आज संसार में कोई भी देश उस स्थिति में नहीं है और वही नीति नहीं अपना रहा है और इसलिये भारत में भी नई स्थिति, नये वातावरण को देखते हुए नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये। श्री नेहरू ने जो कुछ किया उसे भुला देना ठीक नहीं है। उनकी नीतियां सदा के लिये अमर रहेंगी क्योंकि उनमें मानवता के मूल तथ्य हैं।

हमारी विदेश नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए समुचित विकास की आवश्यकता है।

अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस में बड़े अनुसंधान केन्द्र हैं जहां पर वे विश्व के प्रचलित नीतियों का अध्ययन करते हैं। क्या हमारे यहां इसका कोई केन्द्र है। अमरीका में चीन संबंधी समाचारों का अध्ययन करने के लिए एक बड़ा विभाग है। परन्तु हमने अपने विदेश मंत्रालय में अफ्रीका, अमरीका, मध्यपूर्व आदि देशों के लिए डायरेक्टोरेट बना रखे है परन्तु वहां पर नियत नीतियों के बारे में अध्ययन करने के लिए कोई केन्द्र नहीं बना रखा है। हमें ऐसा केन्द्र बनाना चाहिए जिससे अन्य देशों की नीतियों के बारे में हमें पता लग सके और तब हम अपनी नीति बना सकें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

अब मैं अपने पक्ष का विदेशों में प्रचार के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हम जानते हैं कि हमारे देश का विभाजन श्री जिना द्वारा प्रतिपादित दो-राष्ट्र के सिद्धान्त पर हुआ था। आज भी पाकिस्तान के नेता उसी सिद्धांत के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के दो राष्ट्र के प्रचार के कारण हमारे भारत को अमरीका में हिन्दू भारत कहा जाता है जबकि हमारा सिद्धान्त इसके एकदम विपरीत है। परन्तु अमरीका आदि देशों में ऐसा प्रचार नहीं किया जा रहा है जिससे उनको यह मालूम हो कि हमारा देश दो राष्ट्र सिद्धान्त को माननेवाला नहीं है।

अमरीका के पत्रकारों तथा कुछ ब्रिटिश पत्रकारों ने हमारी आलोचना की है कि हमने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे देश ने कभी भी ऐसी जर्रत नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करें। परन्तु पाकिस्तान जबसे वह बना है यही कोशिश कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करे। श्री जफरूल्ला खां ने महासभा में बोलते हुए कहा था कि 'पाकिस्तान कभी भी काश्मीर में अपने सैनिकों को भेजनेसे नहीं रोकना चाहे उसे अन्तर्राष्ट्रीय अथवा किसी अन्य प्रकार से कितना भी जोर डाला जाये'। अमरीका तथा ब्रिटेन कों इन बातों को भूलना नहीं चाहिये। इसके बाद मैं पश्चिम पंजाब के मुख्य मंत्री श्री मीर मुमताज़ दौलताना के शब्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं जिनमें उन्होंने कहा कि "संयुक्त राष्ट्र चोरों की संस्था है"। अमरीका तथा ब्रिटेन को समझना चाहिये कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की किस प्रकार अवहेलना पहलेसे ही करता आ रहा है। परन्तु हमारी प्रचार व्यवस्था खराब होने के कारण हम अपनी ठीक, साफ बात उन तक पहुंचा नहीं सके और इसलिये वहां के पत्रकारों को जो गलतफहमी हो गई उस को दूर नहीं कर पाये।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

अन्त में मैं एक बार फिर सरदार स्वर्ण सिंह की प्रशसा करती हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुतसे सदस्यों का भाषण सुना । मेरा विचार उनक भाषणों में कही गई सभी बातों का उत्तर देने का नहीं है। कुछ बातों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। शेष बातों का उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्री स्वयं देंगे।

आरंभ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने प्रधान मंत्री का पद संभाला था उस समय देश के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें थी जिनको सुलझाना था। मैं चाहता था कि भारत में शांति रहे और पड़ौसी राज्यों से हमारे संबंध अच्छे रहे। लंका के प्रधान मंत्री भारत एक वर्ष पहले यहां आये तथा कई वर्षों से जो समस्या हमारे सामने लटक रही थी उसको हमने संतोषजनक रीति से शांति से हल कर लिया। हमारी दिल्ली में उनसे बातचीत हुई तथा इस संबंध में एक समझौता हो गया तथा मुझे प्रसन्नता है कि लंका के नये प्रधान मंत्री उसको लागू करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूं। हमारे आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

बर्मा में हमारे नागरिकों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा वे लोग बर्मा से लौट कर आ रहे हैं। मैंने अपने विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह से कहा है कि वह बर्मा जायें। वह वहां गए तथा उन्होंने बर्मा सरकार से बातचीत की। यद्यपि हमारी सभी समस्यायें उनके साथ हल नहीं हो पाई परन्तु कुछ सुधार अवश्य हुआ है। पहले हमारे नागरिकों को अपनी आस्तियां वहां पर छोड़नी पड़ती थी परन्तु अब कुछ स्थिति बदल गई है। बर्मा के प्रेसीडेंट जनरल ने विन भारत आए और उनसे हमारी बड़ी लाभदायक बातें हुईं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हो गए हैं।

मैं स्वयं काठमांडू गया था और स्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि नेपाल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि आरंभ में मेरी यही इच्छा थी पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे हो जायें। मैं समझता हूँ कि यदि भारत और पाकिस्तान मित्रता से शांति से रहें तो बहुत अच्छा हो और इसी कारण मैं काहिरा से लौटते हुए कराची गया था। वहां पर प्रेसीडेंट अयूब से मेरी बातचीत हुई। बातचीत से मुझे आशा बंधी थी कि संभवतया हमारी समस्यायें हल हो जायें। उनका विचार था कि, सीमाओं पर होने वाली मुठभेड़े बंद होनी चाहिए। मैंने भी उनको यही सुझाव दिया कि दोनों देशों के सैनिक अधिकारी मिल कर कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिससे ये मुठभेड़ें न हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि दोनों देशों के गृह-मंत्री मिलकर शरणार्थियों की समस्या हल कर लें। मैंने उनसे कहा कि मैं इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूँ।

दिल्ली लौटने पर मैंने गृह-मंत्री सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव भेजे परन्तु पाकिस्तान ने इस सम्मेलन का विलम्बन कर दिया। एक और तारीख निश्चित की गई जिसको भी पाकिस्तान ने नहीं माना। हमने तीसरी बार उन्हें लिखा। उसका उन्होंने उत्तर दिया कि "इस समय स्थिति ठीक नहीं है।" ऐसी बातें हुई। मैं नहीं जानता था कि पाकिस्तान कुछ और तैयारियां कर रहा है। वह कुछ इलाके हड़पना चाहता है। पहले उसने कच्छ की रन पर हमला किया। हमने फिर भी मामले को शांति से निबटाना चाहा। हमने कच्छ की रन को खाली करना तथा उस पर चर्चा करना स्वीकार कर लिया। समझौता भी हो गया परन्तु फिर भी पाकिस्तान को संतोष नहीं हुआ और इसके विपरीत वह यह समझे कि हम कमजोर हैं और वह जबरन हम से कुछ भी करा सकते हैं। जम्मू तथा काश्मीर को पाकिस्तान में वह मिला सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर में घुसपैठिये भेजे। इन्होंने जम्मू तथा

काश्मीर में शांति तथा व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न किया तथा ऐसा प्रयत्न किया जिससे सुरक्षा परिषद तथा महासभा में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाये कि जम्मू तथा काश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिली।

इसके बाद उन्होंने छम्ब के इलाके पर नियमित सेनाओं से हमला कर दिया। हमने इसके विरोध में बहुत कुछ हल्ला मचाया। परन्तु विश्व के किसी भी देश ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सभी चुप रहे। परन्तु जैसे ही हमने लाहौर की ओर बढ़ना शुरू किया विदेशों में भारत के विरुद्ध वक्तव्य तथा लेख निकलने शुरू हो गये। ये हमारे साथ विदेशों ने अन्याय किया। उन्होंने हमारी बात तथा स्थिति को नहीं समझा।

अन्त में मामला सुरक्षा परिषद को भेजा गया। वहां पर इस पर विचार हुआ। हमने वहां भी यही कहा कि आक्रामक का पता लगाया जाये और अब समस्त विश्व को मालूम हो गया है कि किसने आक्रमण किया था। परन्तु सुरक्षा परिषदने अभी भी आक्रमक की घोषणा नहीं की है और इसी के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान को और प्रोत्साहन मिलता है कि वह ऐसे काम करे।

मैं नहीं जानता पाकिस्तानके क्या इरादे हैं। परन्तु एक ओर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने लोगों को यह बताना चाहते है कि पाकिस्तान अब भी लड़ रहा है। उन्होंने अपने लोगों में यह खबर फैला रखी है कि भारत हार गया है और पीछे भगा दिया है। परन्तु यह तथ्य है कि पाकिस्तान का एक बड़ा भाग हमारी सेना के कब्जे में है। मैंने संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव को लिखा है कि पहले युद्धविराम के प्रश्न का फैसला हो जाये फिर सेना पीछे हटाने के प्रश्न को लिया जाये। परन्तु सुरक्षा परिषद ने दोनों पर एक ही साथ विचार करने का फैसला किया है। हम इसके लिये तैयार हैं। परन्तु मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो यह कि यदि पाकिस्तान युद्धविराम का उल्लंघन करता है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे (**अन्तर्बाधा**)। दुसरे यह कि युद्धविराम के प्रभावशाली होने के पश्चात हम किसी ऐसे समझौते पर राज़ी नहीं होंगे जिससे घुसपैठियों को फिर से हमारी सीमा उल्लंघन करने का अवसर मिले। राष्ट्रपति अयूब के साथ मेरी वार्ता के संबंध में भी कुछ बातें कही गई हैं। जैसा कि सभा जानती है यह सुझाव रूस सरकार ने बिल्कुल आरम्भ में दिया था। यद्यपि यह समय इन बातों के लिये मौजूद नहीं है फिर भी हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि हम वहां पर काश्मीर के प्रश्न पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। यदि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के प्रश्न को लिया जाये तो हम उसपर बातचीत करने के लिये तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है और हम उसके साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। परन्तु राष्ट्रपति अयूब और वहां के विदेश मंत्री यह समझते हैं कि समस्या का समाधान यह है कि काश्मीर पर बातचीत ही नहीं अपितु काश्मीर ही उनको मिल जाये। यह प्रस्ताव हमारे लिये स्वीकार करना बिल्कुल असम्भव है।

चीन के संबंध में मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। यह कहना कठिन है कि चीन और पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहे हैं। परन्तु यदि चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हम पर हमला किया तो हमारे सामने कठिन स्थिति आ जायेगी। इसके लिये हमें तैयारी करना है और देश को औद्योगिक, आर्थिक और प्रतिरक्षा की दृष्टि से मज़बूत बनाना है।

जहां तक गुटनिर्पेक्षता की नीति का संबंध है मैं इसपर अधिक कहना नहीं चाहता। श्री मसानी ने पहली बार यह कहा है कि रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होने चाहिये। मुझे यह कहने के जरूरत नहीं कि कठिन समय में रूसने जो हमारी सहायता की हम उसको भुला नहीं सकते हैं।

भारत पाकिस्तान प्रश्न पर अमरीका से हमारे कुछ मतभेद हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अमरीका के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने चाहिये। रुस और अमरीका ही दो बड़ी शक्तियां हैं जो संसार में शांति बनाये रख सकती हैं। ये दोनों देश शांतिपूर्वक ढंग से रहें तो संसार के सभी विकासशील देशों को सहायता मिलती रहेगी और संसार में शांति बनी रहेगी और लोग अच्छी तरह रहेंगे।

[श्री लालबहादुर शास्त्री]

यह सच है कि हमारे कुछ मित्रों ने स्पष्ट रूप से हमारा समर्थन किया है। जब कोई झगड़ा होता है तो अन्य देश यही प्रयत्न करते रहे हैं कि उसका शांतिपूर्व ढंग से निपटारा हो जाये। वे अपने हृदय की बात को स्पष्ट नहीं करते हैं। अरब और मध्यपूर्व के कुछ देशों ने हमारा विरोध किया है। परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि अरब शिखर सम्मेलन में किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया।

उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारा रवैया गांधीजी के समय से ही रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका का अधिकांश देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है। दक्षिण रोडेशिया के अल्पसंख्यक गोरे लोगों ने एक पक्षीय रूप से स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी है। हम बहुसंख्यकों के शासन में विश्वास करते हैं। हम रोडेशिया की गोरी सरकार को मान्यता नहीं देते। वहां के बहुसंख्यक अफ्रीकी लोगों को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है।

जहां तक मेरे अमरीका जाने का प्रश्न है, मैंने पहले कभी इससे इनकार नहीं किया था। श्री पाटिल वहां पर निमन्त्रण का प्रबन्ध करने नहीं गये थे। निमन्त्रण तो पहले से ही था और जरूरत पड़ने पर फिर भी आ सकता था। और राष्ट्रपति जॉनसन की सुविधा को ख्याल में रख कर मुझे इसका निर्णय करना था कि कब जाया जाये। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के दिमाग से मैं यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि कोई बात स्वीकार करने के लिये मुझ पर दबाव डाला जा सकता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 17 नवम्बर, 1965/26 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the November 17, 1965/Kartika 26, 1887 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 5—51 लोक सभा।65—25-8-66—600